चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 03 अगस्त–09 अगस्त 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

लालू-नीतीश अहंकारी, जातिवादी और भ्रष्टाचारी हैं

आज बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है. बिहार में अच्छे डॉक्टर हैं, पत्रकार हैं, आईएएस अधिकारी सबसे ज़्यादा बिहार से बनते हैं. फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है. इसकी वजह क्या है? क्या यहां की लीडरशिप इसके लिए ज़िम्मेदार है या फिर जाति-पात की राजनीति इस सबके लिए दोषी है? जिस बिहार ने जेपी के नेतृत्व में जाति-पात को भूलकर, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपातकाल के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, उसी बिहार में आज जाति की राजनीति इतनी ताकतवर क्यों बन गई है? जाति क्यों विकास पर भारी पड़ गई है? ये ऐसे सवाल हैं, जो बिहार विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही एक बार फिर प्रासंगिक हो गए हैं. हमने इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की और बिहार के कद्दावर नेता राम विलास पासवान से बिहार की वर्तमान एवं भविष्य की राजनीति पर एक लंबी बातचीत की. राम विलास जी ने बिहार के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात को लेकर हमारे विशेष संवाददाता से खुलकर अपने दिल की बात रखी.

विशेष संवाददाता

बिहार में लैक ऑफ लीडरशिप यानी नेताओं की कमी नहीं है. लीडर तो बिहार में इतने हैं कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे. बिहार में गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला भी राजनीति की बात करता है. लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं की नीयत साफ़ नहीं है. नीयत का मतलब यह है कि वे जाति से ऊपर सोच ही नहीं पाते. आज़ादी की लड़ाई से निकलने वालों की एक पीढ़ी थी, जिसमें डॉ. श्रीकृष्ण सिंह वगैरह थे. लेकिन, जिस समय डॉ. श्रीकृष्ण सिंह थे, उस समय भी बिहार में दो ग्रुप थे. एक डॉ. श्रीकृष्ण सिंह जी का ग्रुप था और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह जी का. एक ग्रुप एक जाति का प्रतिनिधित्व करता था, तो दूसरा ग्रुप दूसरी जाति का. चूंकि श्री बाबू आज़ादी की लड़ाई से निकले थे, सो उन्होंने अपने काम में कभी कास्ट लाइन झलकने नहीं दी. ऐसा नहीं है कि इस समस्या से बिहार ऊपर नहीं उठा है. बिहार में जब जेपी का आंदोलन हुआ था, तो लोग कास्ट क्रीड (जाति-पात) सब भूल गए थे. जेपी आंदोलन के सक्रिय सिपाही रहे राम विलास पासवान इस बारे में कहते हैं, तब लोगों के पास एक ही मुद्दा था. लोग कहते थे कि भाई, हम लोग आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं. पहली बार सड़क पर दलित, अमीर, ग़रीब सब जेपी के नेतृत्व में निकल पड़े थे, लेकिन हम उस ट्रेंड को कायम नहीं रख सके.

लेकिन जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ, दिल्ली में सरकार बनी, जाति-पात का खेल फिर से चलने लगा. आख़िर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि जेपी का आंदोलन छात्रों एवं युवाओं तक सीमित नहीं रहा, उसमें राजनीतिक दलों का समावेश हो गया. और, हर राजनीतिक दल किसी न किसी जाति से, संकीर्ण विचारधारा से बंधा हुआ था. तो क्या बिहार में इस जाति प्रथा या जाति से ऊपर उठकर विकास की कोई संभावना है? राम विलास पासवान का मानना है कि बिल्कुल संभावना है. 2005 में नीतीश कुमार की सरकार बनी. लालू यादव से नाराज़ जनता ने नीतीश कुमार की सरकार बना दी. पांच साल तक एनडीए सरकार ने क़ानून व्यवस्था के मसले पर ईमानदारी से काम किया. ज्यों ही लगने लगा कि सड़कों की स्थिति कुछ सुधर गई है, स्कूलों की स्थिति कुछ सुधर गई है, विकास हो रहा है, तो लोग जाति-पात को भूल गए. ज़ाहिर है, पहली बार सरकार में

विपक्ष की राजनीति सत्ता की राजनीति से अलग होती है. विपक्ष का मूल काम होता है सरकार के कृत्यों की आलोचना करना. राम विलास पासवान मानते हैं कि वह शुरू से विपक्ष में रहे हैं और कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से कोई विकास नहीं हुआ. वह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं हुआ.

भ्रष्टाचार कम हुआ था. लालू यादव के समय में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था. नीतीश कुमार के जमाने में भ्रष्टाचार थोड़ा कम हुआ. क़ानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार हुआ, तो लोगों को महसूस हुआ कि यह एक बेहतर सरकार है. लोगों को लगा कि नीतीश कुमार की दूसरी बार सरकार बनेगी, तो बिहार जीडीपी में, सब कुछ में आगे हो जाएगा. दूसरी बार जब चुनाव हुआ, तो लोगों ने विशुद्ध रूप से विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट दिया. यह कोई मामूली बात नहीं है कि वह 243 में से 200 से अधिक सीटें जीते थे. राम विलास पासवान के मुताबिक, दूसरी बार चुने जाने के बाद नीतीश कुमार अहंकार में डूब गए. वह कहते हैं, नीतीश कुमार ने कहा कि हमने नींव डाली है, अब हम महल बनाएंगे. लेकिन, उन्होंने नींव का ही पत्थर उखाड़ना शुरू कर दिया. फिर उसी राह पर बिहार चलने लगा, भ्रष्टाचार की राह पर. जीडीपी के मुद्दे पर लोगों को भरमाने का काम किया गया. मान लीजिए, गुजरात में पहले से सौ किलोमीटर सड़क बनी है और आगे एक किलोमीटर सड़क बनती है, तो 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जीडीपी में. बिहार में जहां एक भी किलोमीटर सड़क नहीं है और एक किलोमीटर सड़क बनती है, तो 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई जीडीपी में. इसे लेकर यह दिखाना शुरू कर दिया गया कि हम तो गुजरात से भी आगे चले गए. हमारा 22 प्रतिशत का ग्रोथ है.

बिहार के लोगों को लगा कि नीतीश सरकार ने पांच साल में अच्छा काम किया. उसका नतीजा यह हुआ कि लोग जाति-पात को भूल गए और उन्होंने नीतीश कुमार को दोबारा भारी बहुमत से चुना. इसलिए यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि बिहार की जनता को अगर थोड़ी-बहुत भी उम्मीद की किरण नज़र आती है, तो वह जाति-पात को भूल जाती है. लेकिन, जब दोबारा सरकार बनी, तो क्या हुआ? राम विलास पासवान के मुताबिक, दूसरी बार सरकार बनने के बाद फिर उसी तरह से भ्रष्टाचार शुरू हो गया. कभी बैकवर्ड, तो कभी फॉरवर्ड, तो कभी इस जाति को बढ़ावा दो, तो कभी उस जाति को बढ़ावा दो वाली राजनीति शुरू हो गई. राम विलास पासवान कहते हैं, आज भले ही अनंत सिंह या सुनील पांडेय जेल में बंद हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या 10 सालों से वे क्रिमिनल नहीं थे? 10 सालों से तो वे नीतीश कुमार के साथ ही थे. यदि वे क्रिमिनल हैं भी, तो नीतीश कुमार क्यों पूरे समुदाय को इससे जोड़ते हैं? मानो पूरा का पूरा भूमिहार समाज क्रिमिनल हो गया है. इस तरीके की भाषा का प्रयोग लालू यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं. अब कह रहे हैं कि हम फिर 1990 को दोहराना चाहते हैं.

विपक्ष की राजनीति सत्ता की राजनीति से अलग होती है. विपक्ष का मूल काम होता है सरकार के कृत्यों की आलोचना करना. राम विलास पासवान मानते हैं कि वह शुरू से विपक्ष में रहे हैं और कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से कोई विकास नहीं हुआ. वह कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में कोई सुधार नहीं हुआ. नीतीश कुमार ने कुछ जाति विशेष के अपराधियों को जेल में बंद करा दिया. लोगों को लगा कि बहुत काम हो रहा है. यूपीए सरकार के समय केंद्र से बिहार में खूब पैसा गया. उससे सड़क आदि में सुधार होना शुरू हुआ. राम विलास पासवान कहते हैं, लोगों को लगा कि यह आदमी विकास करना चाहता है, विकास हो रहा है. लेकिन जैसे ही वह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लालू-नीतीश अहंकारी, जातिवादी और भ्रष्टाचारी हैं | P-3

उम्मीद है, सीबीआई एसटीएफ जैसी ग़लती नहीं करेगी | P-4

एनसीईआरटी पेपर खरीद घोटाला | P-6

लालू-नीतीश अहंकारी, जातिवादी और भ्रष्टाचारी हैं

पृष्ठ 1 का शेष

दोबारा सत्ता में आए, वही ठेकेदारी, वही भ्रष्टाचार. अफसरशाही का नंगा नाच होने लगा. जब नीतीश कुमार गांवों में जाने लगे, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आप कहते हो कि उस घर में शादी न करो, जहां शौचालय न हो. इसलिए हमारे यहां शौचालय बनवा दो. पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है. नीतीश कुमार ने आशा कर्मचारियों और तीन लाख शिक्षकों को लॉलीपॉप थमा दिया. जब लोगों का विरोध शुरू हुआ, तो खूब विरोध हुआ. यहां तक कि पत्थरबाजी होने लगी. उनके मुताबिक, जब नीतीश कुमार को लगा कि विकास के नाम पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब वह धीरे-धीरे दलित-महादलित, जाति-पात की राजनीति पर उतर आए. लव-कुश का नारा देने लगे. लव माने कुर्मी और कुश माने कुशवाहा. इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार में सुधार हो सकता है, यदि लीडरशिप की नीयत सही हो जाए.

बिहार के तीनों बड़े नेता जेपी आंदोलन से निकले हुए हैं. ये तीनों नेता हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राम विलास पासवान. राजनीति में किसकी कितनी हैसियत रही, इस बारे में राम विलास पासवान कहते हैं कि नीतीश जी का ज़्यादा रोल कभी नहीं रहा. वह टेक्निकल आदमी थे, इंजीनियर थे. वह मास मूवमेंट में कभी रहे नहीं. मास मूवमेंट में रहते, तो 1977 में क्यों हार जाते या 1980 में क्यों हार जाते? नीतीश का तो उदय ही 1985 के बाद हुआ. राम विलास पासवान मानते हैं कि उनका कद छोटा करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को राजनीति में बढ़ाने का काम किया और वही उन्हें दिल्ली लाए. लेकिन, नीतीश कुमार को राम विलास पासवान उस कैटेगरी में नहीं मानते, जिससे वह उनका कद छोटा कर सकें. राम विलास पासवान इसके लिए उदाहरण भी देते हैं और कहते हैं कि वह 1969 में राजनीति में आए, एमएलए बने. बकौल राम विलास, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार को सोशलिस्ट मूवमेंट से कभी कोई मतलब नहीं रहा, वे सोशलिस्ट मूवमेंट में एक दिन भी जेल नहीं गए. हां, शरद यादव जी और केसी त्यागी जी ज़रूर सोशलिस्ट विचारधारा के हैं.

सवाल यह भी है कि राम विलास पासवान लालू प्रसाद यादव से अलग क्यों हुए? जेपी आंदोलन से एक साथ निकले इन दोनों नेताओं की राहें अलग क्यों हो गईं? राम विलास पासवान इसके लिए लालू यादव के व्यवहार को ज़िम्मेदार मानते हैं. वह कहते हैं, लालू जी के डाउनफॉल का मुख्य कारण उनका अहंकार था. जेपी का मूवमेंट मिल जाने के कारण लालू यादव टाइप के आदमी लीडर बन जाते हैं. उनके पास न तो कोई विजन रहा, न कोई कल्पना रही. वह कितने दिन स्कूल-कॉलेज या क्लास में रहते थे या नहीं रहते थे, मैं जानता हूं. 1977 के चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता था. मुझे याद है कि 1980 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो लालटेन लेकर दलितों की बस्ती में घूमते थे लालू जी.

राम विलास कहते हैं, लालू यादव जितने अहंकारी हैं, उनसे कम अहंकारी नीतीश कुमार नहीं हैं. नीतीश कुमार की हालत गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज वाली है. उन्हें लालू यादव के वोट चाहिए, एमवाई (मुस्लिम-यादव) वोट भी चाहिए और अकेले हाथ उठाए हुए फोटो खिंचवा कर प्रचार कर रहे हैं. यह उनका अहंकार ही तो है. भ्रष्टाचार के मसले पर राम विलास लालू यादव और नीतीश कुमार को एक ही कठघरे में खड़ा करते हैं. उनके मुताबिक, लालू यादव को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है. जेल से निकले हैं, जमानत पर हैं.

यह जानना भी ज़रूरी है कि जनता दल के गठन के समय क्या हुआ? जनता दल बन गया, तो शुरू में देवीलाल जी और वीपी सिंह जी बिल्कुल साथ-साथ थे. देवीलाल जी ने सरकार बनाने में बहुत मदद की थी. राम विलास पासवान का मानना है कि चंद्रशेखर जी दिल से कभी वीपी सिंह के साथ नहीं रहे. 1989 का चुनाव आ गया था और उस समय दो गुट बन गए थे. राम विलास पासवान के मुताबिक, चंद्रशेखर जी, देवीलाल जी और लालू यादव जैसे लोग एक खेमे में आ गए थे और वह खुद वीपी सिंह के साथ थे. जब चुनाव का समय आया, तब रघुनाथ झा पार्टी अध्यक्ष थे बिहार के. चंद्रशेखर जी ने बनाया था. रघुनाथ जी ने क्या किया? राम विलास जी बताते हैं कि रघुनाथ झा और लालू यादव ने मिलकर प्रस्ताव रख दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने कि राम विलास पासवान को हाजीपुर से चुनाव न लड़ाया जाए, दूसरी जगह से लड़ाया जाए, क्योंकि हाजीपुर के लोग उनके ख़िलाफ़ हैं. फिर सवाल आया कि किसे दिया जाए वहां से टिकट? जवाब मिला कि राम सुंदर दास जी को दिया जाए. राम सुंदर दास जी भी वहां बैठे हुए थे. लेकिन, वीपी सिंह जी ने अंत में टिकट राम विलास पासवान को ही दिया.

इसी दौरान राम विलास पासवान और लालू यादव के बीच मनभेद शुरू हो गया. टिकट मिलने के बाद राम विलास पासवान ने रिकॉर्ड पांच लाख 26 हज़ार वोटों से हाजीपुर से जीत हासिल की. वीपी सिंह जी ने उन्हें मंत्री भी बनाया. 1990 में विधानसभा चुनाव हुआ. उस चुनाव के बाद वीपी सिंह जी ने राम विलास पासवान से पूछा था कि क्या वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में ही रहने की बात कहकर मना कर दिया. यह पूछने पर कि फिर किसे बनाया जाए, राम विलास पासवान ने राम सुंदर दास का नाम आगे कर दिया. राम सुंदर दास जीत भी जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ? इस बारे में राम विलास पासवान बताते हैं कि इसी बीच चंद्रशेखर जी ने एक नया दांव खेला. उन्हें पता था कि ये 11 वोट लालू यादव के नाम पर नहीं मिलने वाले. इसलिए बीच में रघुनाथ झा को खड़ा कर दिया गया. रघुनाथ झा ने 11 वोट झटक लिए और इस वजह से तीन-चार वोटों से लालू जी निकल गए. राम विलास ईमानदारी से यह स्वीकारते हैं कि उस समय पशुपति कुमार पारस या उनके साथ के लोगों ने लालू यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए होने वाली वोटिंग में वोट नहीं दिया था. वह कहते हैं, हमने छिपाया भी नहीं, खुलकर ख़िलाफ़ में वोट दिया. लालू जी को भी मालूम था और शायद उस बात को न लालू यादव कभी भूल पाए और न हम. हम दिल से कभी उसके बाद नहीं मिल पाए.

हालांकि, चुनाव के समय इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती थी, क्योंकि कहीं न कहीं ये सारे नेता धर्मनिरपेक्षता और जाति के मसले पर कमोबेश एक ही राजनीतिक लाइन पर चलने वाले लोग हैं. अभी बिहार की जो समस्याएं हैं, वे भयावह हैं. जाति वाले मामले पर राम विलास पासवान ज़्यादा चिंतित नहीं दिखते. वह कहते हैं, इस बात से मैं उतना चिंतित नहीं हूं. बिहार में इतना ही होता है कि चुनाव सिर्फ़ कास्ट लाइन पर होता है. जो सबसे मूलभूत समस्या है, वह है भयंकर तरीके से पिछड़ापन. नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए राम विलास कहते हैं कि नीतीश कुमार को सत्ता में आए दस साल हो गए हैं. वह सुई का कारखाना तक नहीं लगवा सके, लेकिन भाषण में ऐसी बातें होती हैं, मानो बिहार का औद्योगीकरण हो गया हो. बिहार में दो बड़े पुल हैं, उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने वाला पटना-हाजीपुर पुल और दूसरा मोकामा का. दोनों पुलों की हालत जर्जर है. अब दस सालों में आप पुल नहीं बना सके. 1200 करोड़ रुपये का बजट है. अब 600 करोड़ रुपये और लग रहे हैं. पटना में हड़ताली चौक पर म्यूजियम बना रहे हैं. हाईकोर्ट ने अभी एक महीने पहले कहा कि यह पैसे का अपव्यय है. शराबबंदी के मसले पर राम विलास का कहना है कि पिछले दस सालों में नीतीश सरकार ने शराब को बढ़ावा दिया, गांव-गांव में शराब की दुकान खुल गई. बच्चों के हाथों में किताब की जगह शराब की बोतल थमा दी गई. अब नीतीश कहते हैं कि अगली बार सरकार में आएंगे, तो शराबबंदी करेंगे. इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात क्या होगी?

बकौल राम विलास, पटना में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है और एम्स के 80 प्रतिशत मरीज बिहार से आते हैं. पिछले दस सालों में एक पैसे का निवेश नहीं हुआ. न कहीं स्कूल बढ़िया है, न कहीं कॉलेज बढ़िया है. कटिहार में एक मेडिकल कॉलेज था, उसे बंद करने की कोशिश की गई. राम विलास दूसरे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कहीं भी दूसरी जगह चले जाइए, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में. हर जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे. बिहार में क्या है? बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा? शिक्षा की वही हालत, स्वास्थ्य की वही हालत, पीने का पानी नहीं, ग़रीबी उसी भयंकर तरीके से है. अब चुनाव आया है, तो फिर से जातिवाद शुरू. दरअसल, उन्हें साफ़ दिख रहा है कि लोग विकास के नाम पर तो वोट नहीं देंगे, इसलिए बैकवर्ड-फॉरवर्ड करो. राम विलास कहते हैं कि जो लोग भाजपा पर आरोप लगाते थे कि वह जाति की राजनीति करती है, वही लोग आज खुद जाति के आधार पर रोज सम्मेलन कर रहे हैं और कहते हैं कि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही? यदि जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी हो गई, तो मामला इन्हीं लोगों के विपरीत चला जाएगा.

राम विलास कहते हैं, लालू यादव जितने अहंकारी हैं, उनसे कम अहंकारी नीतीश कुमार नहीं हैं. नीतीश कुमार की हालत गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज वाली है. उन्हें लालू यादव के वोट चाहिए, एमवाई वोट भी चाहिए और अकेले हाथ उठाए हुए फोटो खिंचवा कर प्रचार कर रहे हैं. यह उनका अहंकार ही तो है. भ्रष्टाचार के मसले पर राम विलास लालू यादव और नीतीश कुमार को एक ही कठघरे में खड़ा करते हैं. उनके मुताबिक, लालू यादव को किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, उन्हें खुद कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है. जेल से निकले हैं, जमानत पर हैं. नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ भी कोई कम आरोप नहीं लगे. सीएजी ने जो रिपोर्ट दी थी, उस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए. राम विलास बिहार में बीडीओ, एसडीओ व कलेक्टर के ट्रांसफर-पोस्टिंग में पैसे के खेल का भी आरोप लगाते हैं. उनके मुताबिक, बिहार में हर चीज में कमीशन तय है. पुल बन नहीं रहा है, पुल गिर रहा है. जातिवाद तो खुलकर जारी है. और जब तक ऐसा रहेगा, तब तक बिहार तरक्की नहीं कर सकेगा.

अब सवाल है कि तब इन दोनों के अलावा बिहार के सामने क्या विकल्प बचता है? राम विलास पासवान के मुताबिक, एक ही विकल्प है, भाजपा. उनका मानना है कि भाजपा में नेता बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं. वे सब कुछ देख रहे हैं. पासवान कहते हैं कि अभी सरकारें बनी हैं, चाहे फडणवीस की सरकार हो, खट्टर की सरकार हो या झारखंड की. इन सरकारों में भ्रष्टाचार का मुद्दा तो नहीं आया है. बिहार विधानसभा चुनाव में महा-गठबंधन के असर के सवाल पर राम विलास कहते हैं कि ये लोग झारखंड में एक साथ चुनाव लड़े थे, कितनी सीटें जीते वहां से? वही हाल बिहार में होने वाला है. लालू यादव दिन-रात नरेंद्र मोदी-नरेंद्र मोदी करते रहते हैं और जब फोटो खिंचवाने का समय आता है, तो परिवार के साथ अपनी फोटो उनके साथ खिंचवाने में गर्व महसूस करते हैं. सैफई में मुलायम सिंह के यहां उन्होंने कैसे फोटो खिंचवाई?

बिहार की हालत बहुत ही दयनीय है, इसे लेकर राम विलास पासवान एक कहावत सुनाते हैं. वह कहते हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और पान सड़ा क्यों? इसका एक ही जवाब है कि उसे पलटा नहीं गया. इसलिए घोड़े की चाल बिगड़ गई, रोटी जल गई और पान सड़ गया. उसे पलटना ज़रूरी है. ■

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 22
दिल्ली, 03 अगस्त–09 अगस्त 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

feedback@chauthiduniya.com

10 अगस्त को उड्डयन निदेशालय के अनुरक्षण अभियंता कन्हैया लाल गुप्ता अमेरिका रवाना होंगे और वह वहां 14 अगस्त तक रहेंगे. राज्य उड्डयन निदेशालय के पायलट कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन अरुण कुमार 14 अगस्त को अमेरिका जाएंगे और 31 अगस्त तक वहां रहेंगे. कुल 18 दिनों के प्रवास पर प्रति पायलट 17 लाख 78 हज़ार 550 रुपये खर्च होंगे. एक अदद विमान खरीदने के लिए नौकरशाहों द्वारा बनाए गए तामझाम का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. पायलट कैप्टन प्रवीण किशोर 18 सितंबर को अमेरिका जाएंगे और पांच अक्टूबर तक वहां रहेंगे. उन पर सरकार 17 लाख 78 हज़ार 550 रुपये खर्च करेगी. फिर 28 नवंबर को वायुयान अनुरक्षण अभियंता मोती राय भी 23 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे और उन पर सरकार 11 लाख 275 रुपये खर्च करेगी.

एक विमान के लिए दर्जन भर अफसर साल भर करेंगे अमेरिका में मौज

जनता के धन पर समाजवाद की फ्लाइट

प्रभात रंजन दीन

विमान खरीदना, उसे दुर्घटनाग्रस्त करके कौड़ियों के भाव बेच डालना और फिर से विमान खरीदना उत्तर प्रदेश सरकार का शगल बन गया है. विमान खरीदने के बहाने नौकरशाहों की विदेश में तफरीह हो रही है और नेताओं के लिए हवाबाजी का इंतजाम. नेताओं और नौकरशाहों को इससे क्या मतलब है कि प्रदेश में किसान तबाह हो रहे हैं या चीनी मिलों ने किसानों का बकाया देने से मना कर दिया है या प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. सब तरफ़ आखेट चल रहा है. क़रीब 44 करोड़ रुपये का एक विमान खरीदने के लिए जो आबा-काबा अमेरिका जा रहा है, उस पर समाजवादी सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. कुछ लोग पहले अमेरिका जा चुके है, वे मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव अनिता सिंह और नागरिक उड्डयन के निदेशक देवेंद्र स्वरूप का अमेरिका में स्वागत करेंगे. जिस समय चौथी दुनिया का यह अंक छपकर आपके हाथ में होगा, विमान खरीदने गए और जा रहे कथित विशेषज्ञ अमेरिका के विभिन्न शहरों में मौज कर रहे होंगे. अलग-अलग खेपों में अमेरिका जाने का क्रम अभी जारी रहेगा. यह इस साल दिसंबर महीने तक चलेगा. अमेरिका की बीचक्राफ्ट कंपनी से खरीदे जा रहे विमान सुपर किंग एयर-बी-250 (मॉडल बी-200 जीटी) की क़ीमत 67,00,000 यूएस डॉलर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी मर्जी से मुद्रा की क़ीमत का भी निर्धारण कर लिया और बीचक्राफ्ट कंपनी को 65 रुपये प्रति डॉलर की दर से 43 करोड़ 55 लाख रुपये (भारतीय मुद्रा) देने का करार कर लिया. दिलचस्प बात यह है कि जिस तारीख को करार हुआ और जिस तारीख को यह ख़बर लिखी जा रही है, एक यूएस डॉलर की क़ीमत 65 रुपये थी ही नहीं. यानी अमेरिकी कंपनी को मुद्रा की वास्तविक क़ीमत से अधिक का भुगतान कर दिया गया. सवाल यह है कि बीचक्राफ्ट और उसकी सहयोगी कंपनी टेक्सट्रॉन का दफ्तर दिल्ली में है और उसके डीलर भारत में हैं, तो इस भारी लाव-लश्कर के अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत थी?

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रमुख सचिव अनिता सिंह एवं नागरिक उड्डयन महकमे के निदेशक देवेंद्र स्वरूप वायुयान के टेक्निकल एक्सेप्टेंस और डिलीवरी के लिए अनुबंध की शर्तों-विशिष्टियों के अनुसार वायुयान की गुणवत्ता आदि सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका जा रहे हैं. यह अख़बारी नहीं, सरकारी कथ्य है, जो यात्रा मंजूरी के सरकारी आदेश पर लिखा हुआ है. अनिता सिंह मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव होने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की महानिदेशक भी हैं. एक विमान खरीदने के महत्वपूर्ण कार्य के लिए दोनों अधिकारी 30 जुलाई से लेकर आठ अगस्त तक अमेरिका में रहेंगे. अमेरिका प्रवास के दौरान वे कन्सास के विचिटा और कुछ अन्य शहरों में भी जाएंगे. इन पर प्रति व्यक्ति 11 लाख रुपये खर्च होंगे यानी दोनों अधिकारियों पर सरकारी खजाने के 22 लाख रुपये खर्च होंगे. सरकारी पायलट कैप्टन पंकज सिंह एवं कैप्टन कमलेश्वर सिंह पहले ही अमेरिका जा चुके हैं. वे वहां अनिता सिंह एवं देवेंद्र स्वरूप का स्वागत करेंगे और 17 जुलाई से छह अगस्त तक अमेरिका में ही रहेंगे. इन दोनों पायलटों के 21 दिनों के अमेरिका प्रवास पर प्रति पायलट 17 लाख 78 हज़ार 550 रुपये खर्च होंगे. इसके बाद राज्य नागरिक उड्डयन निदेशालय के वायुयान अनुरक्षण अभियंता हरजीत सिंह 25 जुलाई को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे. वह 16 अगस्त तक अमेरिका में रहेंगे और 23 दिनों में उन पर राज्य सरकार 11 लाख 275 रुपये खर्च करेगी.

10 अगस्त को उड्डयन निदेशालय के अनुरक्षण अभियंता कन्हैया लाल गुप्ता अमेरिका रवाना होंगे और वह वहां 14 अगस्त तक रहेंगे. राज्य उड्डयन निदेशालय के पायलट कैप्टन प्रज्ञेश मिश्र एवं कैप्टन अरुण कुमार 14 अगस्त को अमेरिका जाएंगे और 31 अगस्त तक वहां रहेंगे. कुल 18 दिनों के प्रवास पर प्रति पायलट 17 लाख 78 हज़ार 550 रुपये खर्च होंगे. एक अदद विमान खरीदने के लिए नौकरशाहों द्वारा बनाए गए तामझाम का सिलसिला यहीं नहीं रुकता. पायलट कैप्टन प्रवीण किशोर 18 सितंबर को अमेरिका जाएंगे और पांच अक्टूबर तक वहां रहेंगे. उन पर सरकार 17 लाख 78 हज़ार 550 रुपये खर्च करेगी. फिर 28 नवंबर को वायुयान अनुरक्षण अभियंता मोती राय भी 23 दिनों के लिए अमेरिका जाएंगे और उन पर सरकार 11 लाख 275 रुपये खर्च करेगी. नौकरशाहों, पायलटों एवं इंजीनियरों की अमेरिका यात्रा का यह आधिकारिक ब्यौरा बहती गंगा में हाथ धोने की लत का खुलासा है. एक विमान के लिए इतने ढेर सारे लोगों की सरकारी खर्चे पर अमेरिका यात्रा और पूरे वर्ष भर तफरीह सत्ता की अराजकता का बेजोड़ नमूना है. सरकार कहती है कि पायलटों एवं इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है. जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के ही एक पूर्व पायलट ने कहा कि विमान तो पहले भी खरीदे जाते रहे हैं, लेकिन ऐसी आलीशान ट्रेनिंग-यात्रा तो पहले कभी नहीं हुई. बीचक्राफ्ट और टेक्सट्रॉन के बीच हुए करार के बाद सेसना विमान बनाने वाली कन्सास (यूएस) की कंपनी टेक्सट्रॉन बीचक्राफ्ट विमानों के विक्रय का काम भी कर रही है.

बहरहाल, विमान के टेक्निकल एक्सेप्टेंस और उसकी गुणवत्ता के निरीक्षण-परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन दो अधिकारियों को चुना, उनमें से एक अनिता सिंह मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात हैं और हवाई यात्रा करने के अलावा वैमानिकी से उनका दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. दूसरे, देवेंद्र स्वरूप की योग्यता यह है कि वह मायावती सरकार के कैबिनेट सचिव सह पायलट रहे शशांक शेखर सिंह की चौकड़ी के सदस्य थे और तबसे लेकर अब तक अखिलेश सरकार के कार्यकाल में भी उड्डयन महकमे में डटे हुए हैं. उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन महकमे का बंटाधार हो गया. बेशक़ीमती विमान नष्ट हो गए, हेलिकॉप्टर खटारा हो गए, कर्मचारियों का बेइंतिहा शोषण-उत्पीड़न हुआ और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया. भ्रष्टाचार उजागर करने वाले कर्मचारियों को बेरहमी से नौकरी से निकाला गया या वीरान इलाकों की नॉन-ऑपरेशनल हवाई पट्टियों पर तबादला कर दिया गया, जहां उन्हें वेतन के लाले पड़ गए. उन्हीं अधिकारी को अखिलेश यादव ने भी योग्य माना है. ऐसी ही योग्यता के मानकों के कारण करोड़ों में खरीदे गए विमान कौड़ियों में बिक रहे हैं. कई विमानों का तो कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार का बेहतरीन विमान सुपर किंग एयर-300 एलडब्ल्यू (वीटी-यूपीए) कुछ अर्सा पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उसे इसी महीने ओडिसा की एक कंपनी मैसर्स ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को महज छह करोड़ 75 लाख रुपये में बेच डाला गया. यह कोई पहला मामला नहीं है. खराब परिचालन और रखरखाव के कारण ऐसे कई विमान और हेलिकॉप्टर पड़े हैं, जिनका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है. बार-बार निविदा निकाली जाती है, लेकिन कोई खरीदार नहीं आता. सरकार खुद यह स्वीकार करती है. सरकारी भाषा में की गई यह स्वीकारोक्ति देखिए...राज्य सरकार के निष्प्रयोज्य वायुयानों/हेलिकॉप्टरों के विक्रय हेतु प्राप्त निविदाओं में से वायुयानों/हेलिकॉप्टरों के निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के परिप्रेक्ष्य में दो वायुयानों सुपर किंग एयर-300 एलडब्ल्यू (वीटी-यूपीए) एवं प्रीमियर-1-ए (वीटी-यूपीएन) तथा दो हेलिकॉप्टर चेतक एवं बेल-230 तथा उनके रोटेबल्स के निस्तारण हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी. निविदा समिति के समक्ष निविदा खोली गई. प्रीमियर-1-ए के लिए मात्र एक निविदा प्राप्त हुई. बेल-230 हेलिकॉप्टर एवं चेतक हेलिकॉप्टर हेतु कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई. फलतः इनके विक्रय हेतु पुनः निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी. इस सरकारी स्वीकारोक्ति से उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन महकमे की दशा-दिशा समझ में आ जाती है.

प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव को लेकर दिल्ली गया अत्याधुनिक विमान प्रीमियर-1-ए (वीटी-यूपीएन) कुछ दिनों पहले हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उसे ट्रक पर लादकर लखनऊ लाया गया. अब निदेशालय उसे कौड़ियों में ठिकाने लगाने पर लगा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा. इसके लिए तमाम दलालों से संपर्क साधा जा रहा है. इस विमान को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने 40 करोड़ रुपये में खरीदा था. छह सीटों वाला चेतक हेलिकॉप्टर तो 2009 से ग्राहक की बाट जोह रहा है. बेल हेलिकॉप्टर भी दो साल से बिकने के लिए ग्राहक तलाश रहा है. कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव एवं राजेंद्र चौधरी को लेकर गए विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच-पड़ताल में पता चला कि लैंडिंग-गियर में खामी के बारे में पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कोई सूचना नहीं दी और इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत लिए बगैर इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 27 नंबर रन-वे पर विमान की बेली-लैंडिंग करा दी. पूरा विमान रन-वे पर पेट के बल घिसटता हुआ किनारे की गीली ज़मीन में जाकर धंस गया. तकनीकी विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर कंक्रीट रन-वे पर ही विमान घिसटता, तो उसमें आग लग जाती और भीषण हादसा हो सकता था. ऐसे ही लापरवाह पायलटों के बूते उत्तर प्रदेश सरकार के विमान उड़ रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, फिर नए विमान खरीदे जा रहे हैं. प्रीमियर-1-ए (वीटी-यूपीएन) मायावती के कार्यकाल में खरीदा गया था. इसे पहले जर्मनी, फिर यूक्रेन की आईबीई ट्रेड कंपनी ने खरीदा गया और फिर जून 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुर्द किया गया.

विडंबना यह है कि विमानों-हेलिकॉप्टरों की खरीद-फरोख्त से लेकर यात्राओं के ब्यौरे मांगने पर सरकार सूचना नहीं देती. सच बाहर निकालने के लोकतांत्रिक-संवैधानिक तौर-तरीकों पर सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है. सूचना के अधिकार को सरकार ने पंगु बनाकर रख दिया है. विमानों एवं हेलिकॉप्टरों के आने-जाने का ब्यौरा रखने वाली लॉग बुक, जर्नी लॉग बुक को सरकार ने पायलटों और विमान इंजीनियरों की निजी संपत्ति घोषित कर दिया है. सरकार कहती है कि वायुयान एवं हेलिकॉप्टरों की कहां-कहां यात्रा हुई और कहां-कहां रि-फ्यूलिंग हुई, इसका विवरण परिचालन इकाई द्वारा संकलित नहीं किया जाता. दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि बेवकूफाना तरीके से उड़ाने के कारण जो बेशक़ीमती विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनका ब्यौरा भी आम नागरिकों को नहीं मिल पाता. सरकार केवल इतना बताती है कि कितने हवाई जहाज एवं हेलिकॉप्टर उड़ान के लायक हैं और कितने उड़ान के लायक नहीं हैं. उड़ान के लायक क्यों नहीं रहे, इसका कोई जवाब नहीं मिलता. प्रदेश का उड्डयन महकमा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अधीन है. ■

राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे सरकारी विमान!

उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया गया. संदेहास्पद लोगों और महिलाओं की सरकारी विमानों से आवाजाही हुई. उड्डयन निदेशालय के कुछ संदेहास्पद अधिकारियों ने बॉम्बे ब्लास्ट (1993) के समय सरकारी टेलीफोन से पाकिस्तान बातचीत की. लेकिन इन गंभीर शिकायतों को निदेशालय एवं शासन टालता रहा और झूठी सूचनाएं देता रहा. उड्डयन महानिदेशालय के कर्मचारी व्हिसिल ब्लोअर देवेंद्र दीक्षित ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सरकारी विमान से जासूसी के इरादे से कानपुर सैन्य क्षेत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई. उड्डयन महानिदेशालय के फोन से लगातार पाकिस्तान कॉल होती रही. लॉग बुक में औपचारिक इंट्री किए बगैर संदेहास्पद महिलाओं को विमान द्वारा लखनऊ लाया गया और दिल्ली ले जाया गया. डॉल्फिन हेलिकॉप्टर से विदेशी महिला को नेपाल सीमा तक पहुंचाया गया और विमानों की खरीद में विदेशी कंपनी के साथ मिलकर खूब घोटाला किया गया. इन शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया कि जांच कमेटी गठित हुई, जांच हुई और शिकायतें फर्जी पाई गईं. जबकि सत्य यह है कि सरकार ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की. उत्तर प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से कहा था कि तीन सदस्यीय जांच समिति ने शिकायतों की बाकायदा छानबीन की और उन्हें निराधार पाया. कुछ ही अंतराल के बाद सरकार अपना दिया जवाब भूल गई. जब दोबारा सरकार से उन शिकायतों का हवाला देते हुए जांच समिति गठित होने का ब्यौरा मांगा गया, तो सरकार ने कह दिया कि जांच के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई थी. आपको बताते चलें कि उड्डयन महकमे के घोटाले उजागर करने वाले व्हिसिल ब्लोअर देवेंद्र दीक्षित को पहले तो अनगिनत तबादलों से प्रताड़ित किया गया, फिर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. देवेंद्र दीक्षित द्वारा उसी शिकायत को मुख्य सचिव के समक्ष पेश किए जाने के बाद मुख्य सचिव कार्यालय ने उन्हें सूचना दी कि उनकी शिकायत को उचित कार्रवाई के लिए नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव के पास भेज दिया गया है. कार्रवाई क्या हुई, इसे बताने की किसी को फुर्सत नहीं थी, क्योंकि आला अधिकारी विदेश यात्रा की तैयारियों में मशरूफ थे और अन्य अधिकारी उन्हें तैयारियां कराने में.

सरकारी विमान है या निजी वाहन!

पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने आरटीआई के ज़रिये मांगी गई सूचना में बताया कि राजकीय विमानों का उपयोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के गणमान्य महानुभावों की शासकीय यात्राओं के लिए होता है. राजनेताओं के निजी आयोजनों के लिए राजकीय विमानों का उपयोग नहीं किया जाता है. इस हास्यास्पद जवाब के कुछ ही दिनों पहले आधिकारिक तौर पर यह खुलासा हो चुका था कि कुछ दिनों के अंतराल में ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकारी विमान से 46 बार सैफई गए और वरिष्ठ मंत्री शिवपाल यादव 51 बार सैफई गए थे. यह तथ्य उजागर होने पर राज्य सरकार ने नहीं बताया कि मुख्यमंत्री की 46 बार और वरिष्ठ मंत्री की 51 बार सैफई यात्रा किन शासकीय वजहों से हुई तथा उन शासकीय यात्राओं से प्रदेश को क्या उपलब्धि हासिल हुई. सैफई महोत्सव में सरकारी विमानों के बेजा इस्तेमाल की ख़बरें पहले ही सुर्खियों में रही हैं. विकिलीक्स ने भी यह खुलासा किया था कि उत्तर प्रदेश के सरकारी विमानों का बेजा नहीं, बेहूदा इस्तेमाल होता है. पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तो सरकारी विमान मुंबई भेजकर अपनी सैंडल मंगवाती थीं. विकिलीक्स के मुताबिक, मायावती को जब भी नए सैंडल की ज़रूरत होती थी, तो वह सरकारी जेट विमान मुंबई भेजती थीं और मनपसंद ब्रांड की सैंडल मंगवाती थीं. महज हज़ार रुपये की सैंडल के लिए विशेष विमान पर 10 लाख रुपये खर्च करना लोकतांत्रिक नैतिकता के किस स्तर पर आता है, यह साफ़-साफ़ समझ में आता है.

feedback@chauthiduniya.com

उम्मीद है, सीबीआई एसटीएफ जैसी ग़लती नहीं करेगी

मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक और व्यापमं प्रकरण के पहले व्हिसिल ब्लोअर पारस सकलेचा ने चौथी दुनिया संवाददाता नवीन चौहान से एक लंबी बातचीत की. उन्होंने प्रकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बड़ी बेबाकी से रोशनी डाली. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:-

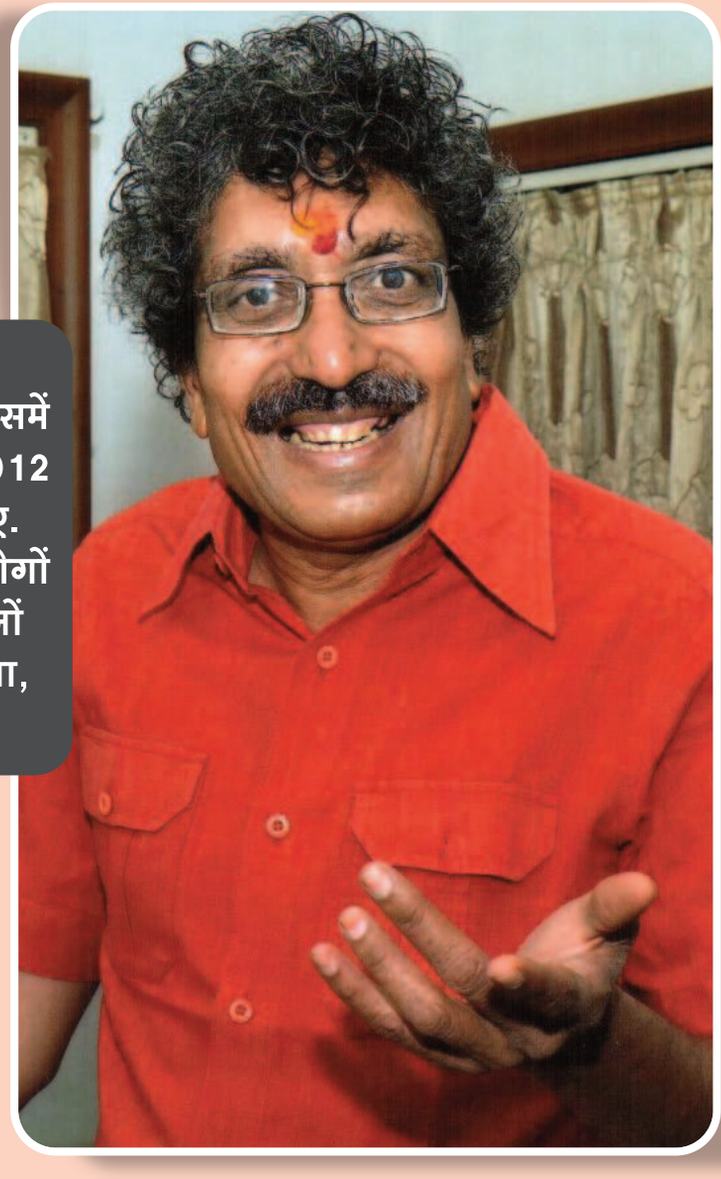

मैं 2009 से आवाज़ उठा रहा हूं. जांच कराई 17 दिसंबर, 2009 में एक कमेटी बनवाकर मुख्यमंत्री से. उसमें 114 लोग फर्जी पाए गए. फिर मैंने 2006 से लेकर 2012 तक की जांच कराई, जिसमें 226 लोग फर्जी पाए गए. जब तक यह मुद्दा चर्चित हुआ, तब तक मैं 410 फर्जी लोगों को गिरफ्तार करा चुका था. कांग्रेस और भाजपा, दोनों इसमें शामिल हैं. जब विधानसभा में आवाज़ उठाता था, तो कांग्रेस के लोग चुप रहते थे.

व्यापमं और डीमेट घोटाले में आपस में क्या संबंध है?

व्यापमं एक सरकारी संस्था है, जो विभिन्न परीक्षाएं कराती है, जिनमें से एक है पीएमटी, जो घोटाले की वजह से चर्चा में है. मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों और निजी कॉलेजों की 42 प्रतिशत सीटों के लिए पीएमटी परीक्षा ली जाती है. निजी कॉलेजों की सीटों के लिए जो परीक्षा होती है, उसे कहते हैं डीमेट. सुप्रीम कोर्ट के 27 मई, 2009 के फ़ैसले के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ कि निजी कॉलेजों की 42 प्रतिशत शासकीय सीटें पीएमटी के माध्यम से भरी जाएंगी और मैनेजमेंट की 43 प्रतिशत सीटें निजी कॉलेज खुद परीक्षा लेकर डीमेट के माध्यम से भरेंगे. 15 प्रतिशत सीटें एनआरआई कोटे के लिए होंगी. निजी कॉलेजों ने अपनी एक बॉडी बनाई, उसे सोसायटी एक्ट के तहत 2007 में पंजीकृत कराया और नाम रखा एपीडीएमसी यानी एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डेंटल एंड मेडिकल कॉलेज. एपीडीएमसी जो परीक्षा कराती है, उसे डीमेट कहते हैं. इसमें फर्जीवाड़ा यह चल रहा था कि दलाल पहले से लोगों से संपर्क कर लेते थे. वे एक सीट तीस से पचास लाख रुपये में बुक करते थे. जो आदमी हां कह देता था, वह फॉर्म भरता था. फॉर्म भरने के बाद जब वह परीक्षा देने जाता, तो उत्तर पुस्तिका में जितने जवाब उसे मालूम होते थे, सिर्फ़ उतने ही गोले वह काला करता था, बाकी छोड़ देता था. और, परीक्षा ख़त्म होने के बाद उस उत्तर पुस्तिका के शेष गोले डीमेट के अधिकारी एक कमरे में बैठकर सही जवाबों के आधार पर काला कर देते थे. इसकी परीक्षा मनिपाल विश्वविद्यालय कंडक्ट कराता है. फिर रिजल्ट बनने मनिपाल चला जाता था. इसके बाद रिजल्ट आता था. एक और पेंच है कि उस समय प्रश्नपत्र बहुत कठिन बनाए जाते थे. जो लोग दलालों से सेटिंग नहीं कर पाते थे, उनके लिए वे सवाल हल करना आसान नहीं होता था. बहुत इंटेलिजेंट अभ्यर्थी भी पचास प्रतिशत सवाल नहीं हल कर पाते थे. रोल नंबर भी इस हिसाब से बनाए जाते थे कि जिन अभ्यर्थियों का धांधली के ज़रिये एडमिशन करना होता था, उन्हें पूर्व निश्चित परीक्षा केंद्रों पर बैठाया जाता था. सरकार की एक बॉडी है, एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी (एएफआरसी), जिसकी ज़िम्मेदारी है कि इस परीक्षा पर निगाह रखे. वह इसके लिए अपने ऑब्जर्वर नियुक्त करती है. लेकिन, 2004 से लेकर 2014 तक उसके सारे ऑब्जर्वर ऐसे नियुक्त, जिन्होंने कहीं कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई. मेरा आरोप योगेश उपरीत के बयान से सिद्ध होता है, जिन्हें बीते पांच जून को एसआईटी ग्वालियर ने गिरफ्तार किया. उन्होंने कहा कि हम हर साल चिकित्सा शिक्षा मंत्री को 10 करोड़ रुपये इस बात के लिए देते हैं कि वह हमारे किसी भी निर्णय पर आपत्ति न उठाएं.

यह सब आपके संज्ञान में कैसे आया?

सबके संज्ञान में था. मैंने 2009 में विधानसभा में यह सवाल उठाया था. 2011 और 2012 में मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिए थे. मैंने विधानसभा से बहिर्गमन भी किया था. डीमेट वाले खुले एसएमएस करते हैं. अगर आपने फॉर्म भरा है, तो आपके पास एसएमएस आएगा कि आप हमसे संपर्क करें, हम आपका दाखिला करा सकते हैं. आप उनके पास जाएंगे, तो फिर निगोशिएशन होगा. अभी हाईकोर्ट के सामने हमने एसएमएस प्रस्तुत किए कि 40 लाख रुपये में सौदे का एसएमएस आया है.

इतनी चीजें सबके संज्ञान में हैं, मुख्यमंत्री खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे और इस दौरान पांच चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे. उन सबकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, खासकर मुख्यमंत्री की?

मुख्यमंत्री ने अपनी ज़िम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई. मैंने कई बार उनके संज्ञान में विधानसभा और आउट ऑफ असेंबली उनसे बात की. मैंने उन्हें बताया कि डीमेट में भारी घोटाला हो रहा है. मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था कि जो लोग डीमेट में सलेक्ट हुए, उनके बारहवीं में कितने नंबर हैं? मुझे उत्तर मिला कि 70 प्रतिशत लड़के जो डीमेट में सलेक्ट हुए, उनके 50 से 60 प्रतिशत अंक हैं. आजकल 50–60 प्रतिशत में आईटीआई में दाखिला नहीं होता, लोग डॉक्टर बन रहे हैं. हमारे आरोप की पुष्टि योगेश उपरीत के बयान से होती है, जो 2004 से लेकर अब तक डीमेट का समन्वयक–परीक्षा नियंत्रक रहा. यह डीमेट का किंग पिन है. उपरीत ने एसआईटी के सामने कहा कि परीक्षा के पहले ही चयनित होने वालों की सूची बन जाती है. 2003 में जब ईओडब्ल्यू ने निजी मेडिकल कॉलेज पीपुल्स पर छापा मारा, तो उपरीत के घर पर भी छापा पड़ा, जहां कई दस्तावेज़ बरामद हुए. 23 जुलाई, 2009 को इनकम टैक्स विभाग ने निजी मेडिकल कॉलेजों पीपुल्स, आरकेडीएफ एवं एलएनसीटी पर एक साथ छापा मारा और साथ ही योगेश उपरीत के घर व डीमेट के कार्यालय पर छापा मारा, तब भी काफी दस्तावेज़ मिले.

तो फिर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

मुख्यमंत्री से हमने कहा कि वह उन दस्तावेज़ों को मंगाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. 2012 में हमने फिर प्रश्न लगाया कि उन्होंने उन दस्तावेज़ों पर क्या कार्यवाही की, तो जवाब मिला कि उन्हें उन दस्तावेज़ों की कोई जानकारी नहीं है.

क्या डीमेट को सीबीआई जांच में शामिल करना चाहिए?

मेरी यह मांग हाईकोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका है. सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका में कहा गया है कि हम जो भोपाल वाले पेटिशनर हैं यानी पारस सकलेचा आदि चाहें, तो अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करा सकते हैं.

तो आप इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं?

अभी मैं अपने वकीलों से राय ले रहा हूं. सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का नोटिस जारी किया है सीबीआई को. दो हफ्ते बाद उसका जवाब आएगा. उसके बाद सुनवाई होगी. हम आशांवित हैं कि डीमेट में सीबीआई जांच की हमारी मांग मंजूर होगी.

मुख्यमंत्री का कहना है कि हर मौत को व्यापमं से जोड़कर मत देखिए, लेकिन आप दावा करते हैं कि उनका संबंध व्यापमं से है. इसके कोई सुबूत हैं?

देखिए, 33 मौतें नोटिफाइड हुईं सरकार द्वारा और हम मानते हैं कि 60 से ज़्यादा मौतें हुईं. ठीक है, संख्या पर विवाद हम न करें. नोटिफाइड संख्या को ही मान लें. मरने वाले सारे लड़के 22 से 25 साल के हैं. वे किसी भी तरह मरे, लेकिन उनकी मौत स्वाभाविक तो नहीं है. बताया गया कि 33 में से 13 लोग सड़क दुर्घटना में मरे, 7 से 8 लोग अधिक शराब पीने से मरे, दो–तीन ब्रेन हैमरेज मरे, एक–दो कैंसर से मरे और एक–दो ने ज़हर पीकर आत्महत्या कर ली. वे लड़के इतने कमजोर तो नहीं थे कि 50 लाख रुपये खर्च करने के बाद आत्महत्या कर लें. ऐसा माहौल बनाया गया और उन्हें इतना डराया–धमकाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. ज़हर पीकर आत्महत्या? ज़हर पिलाया भी तो जा सकता है. केस स्टडी के आधार पर हमें कहने का अधिकार है कि उक्त मौतें सरकार एवं एसटीएफ की लापरवाही और ग़ैर ज़िम्मेदाराना जांच की वजह से हुईं.

भोपाल के कोहेफिजा थाने में 12 जुलाई, 2012 को एक प्रकरण दर्ज हुआ 360/12, महात्मा गांधी गर्ल्स मेडिकल कॉलेज के डीन की ओर से. उसके तहत चार लड़के गिरफ्तार हुए, अनुज उइके, सौरभ सचान और दो अन्य. फिर उनकी जमानत हो गई. सरकार ने मृतकों की जो सूची दी, उसमें चारों का नाम था. चारों मर गए. तीन सड़क दुर्घटना में और एक ज़हर पीने से मरा. चार–पांच जुलाई को मध्य प्रदेश सरकार के एसटीएफ ने अख़बारों में विज्ञापन प्रकाशित कराया तस–वीरों के साथ कि इन लोगों की तलाश है व्यापमं घोटाले में. नाम नहीं थे, पते नहीं थे, सिर्फ़ फोटो थे और प्रत्येक पर दो–दो हज़ार रुपये का इनाम था. जो तस्वीरें विज्ञापन में छपी थीं, उनमें से 28 लड़के इस प्रकरण के बाद 360/12 में आरोपी हैं. अब आप दोनों को लिंक कीजिए. 360/12 में 28 आरोपी फरार हैं. चार आरोपी पकड़े गए. जो फरार हैं, उनके नाम नहीं मालूम, पते नहीं मालूम, सिर्फ़ तस्वीरें हैं. ये चार लड़के उनकी जगह परीक्षा में बैठे थे. स्वाभाविक है कि उनके नाम–निवास का पता किसी को न चले, इसलिए इन चारों को मरवा दिया होगा. हम यही कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए. एक और प्रकरण है 727/09 भोपाल के एमपी नगर थाने में. जो कंप्यूटर कंट्रोलर नितिन महिंद्रा जेल में है, वह इसका किंग पिन है. उसने प्रकरण दर्ज किया था यह. इसमें तीन लोग एक ही दिन 14 जून, 2010 को एक साथ सड़क दुर्घटना में मारे गए. लोग क्यों मर रहे हैं? इसकी जांच होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर अपने अधिकारियों की बैठक की? क्यों नहीं गृह विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि इन मौतों के पीछे वजह क्या है?

जबसे परीक्षाएं शुरू हुईं, आप आवाज़ उठाते रहेलेकिन इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनने या देश स्तर पर आने में इतना वक्त क्यों लगा?

मैं 2009 से आवाज़ उठा रहा हूं. जांच कराई 17 दिसंबर, 2009 में एक कमेटी बनवाकर मुख्यमंत्री से. उसमें 114 लोग फर्जी पाए गए. फिर मैंने 2006 से लेकर 2012 तक की जांच कराई, जिसमें 226 लोग फर्जी पाए गए. जब तक यह मुद्दा चर्चित हुआ, तब तक मैं 410 फर्जी लोगों को गिरफ्तार करा चुका था. कांग्रेस और भाजपा, दोनों इसमें शामिल हैं. जब विधानसभा में आवाज़ उठाता था, तो कांग्रेस के लोग चुप रहते थे. एकमात्र मैं ऐसा आदमी था, जिसके विधानसभा चुनाव क्षेत्र में मुद्दा था पीएमटी घोटाला. कांग्रेस ने इसे मुद्दा नहीं बनने दिया. घोटाला 2000 से हो रहा है. 2000 से 2004 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसमें घोटाले हुए. फिर शिवराज सरकार आई, उसमें भी घोटाले हुए.

कांग्रेस के नेता अब रुचि ले रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, दिग्विजय सिंह हों या कपिल सिब्बल. अचानक इनका प्रेम कैसे जागा?

जब घोड़ा दौड़ता है, तो सभी रेस लगा लेते हैं. डेढ़ साल की सरकार में एक भी मुद्दा वह घेरने का नहीं लाए. हमने जिस मुद्दे को ज़िंदा रखा, लड़कर, संघर्ष करके, उस पर वे दांव लगाने लगे. यह तो विफलता है कांग्रेस की.

अब सीबीआई जांच हो रही है. क्या आपको लगता है कि असली गुनहगार सलाखों के पीछे दिखाई देंगे? खासकर मुख्यमंत्री का नाम है और उनकी पत्नी का नाम मंत्राणी के रूप में लिया जा रहा है. प्रशांत पांडेय आरोप लगाते रहे हैं कि सुबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई. जांच करने वाले एसआईटी के प्रमुख चंद्रेश भूषण शिवराज सिंह के बहुत प्रिय हैं. जब 2006 में डीमेट में धांधली की जांच हुई, तो वह उस कमेटी के अध्यक्ष थे. उसके बाद उप–लोकायुक्त बने. फिर एसआईटी के प्रमुख बन गए. इसके पीछे आप क्या देखते हैं?

यह सारी गड़बड़ी हमारे संज्ञान में थी, तभी हमने सीबीआई जांच की मांग की. एसआईटी ने दो साल में कोई जांच नहीं की. 14 जुलाई को मैंने सीबीआई को 90 पृष्ठों का प्रेजेंटेशन दिया है, इसके साथ ही 240 पृष्ठों के दस्तावेज़ भी सौंपे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यह जांच अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी, उसके सुपर विजन में जांच होगी और जांच की समय सीमा भी होगी. पर एक शंका है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी. सुबूतों के साथ छेड़छाड़ तो हुई है. प्रशांत पांडेय ने जो बात कही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी पिटीशन लगी है. उन्होंने मांग की है कि उनके द्वारा सब्मिट एक्सएल शीट की जांच किसी उच्चस्तरीय प्रयोगशाला से करा ली जाए. इस पर जजमेंट आ जाएगा, तो उसकी जांच हो जाएगी. जांच में अगर सिद्ध हो गया कि वह एक्चुअल है, तो फिर सबको जेल जाना है, कोई बचेगा नहीं. हमारे पास यह भी प्रमाण है कि एक्सएल शीट में टेंपरिंग करने के बाद भी जो नाम आ रहे हैं, उन पर एसटीएफ ने कोई कार्रवाई नहीं की. मेरे पास एक एक्सएल शीट है, जिसमें 23 नाम हैं, जिनमें से केवल 14 पर कार्रवाई हुई और नौ को छोड़ दिया गया. सीबीआई अगर पूरी जांच करेगी, तो एसटीएफ के लोग भी घेरे में आएंगे. हमने तो आरोप लगाकर प्रमाण दे दिए कि एसटीएफ ने इसे पकड़ा, उसे छोड़ा. सीबीआई ने गुलाब सिंह किरार, शक्ति सिंह किरार और सुधींद्र सिंह भदौरिया पर पर प्रकरण दर्ज किया. इन तीनों के ख़िलाफ एक साल पुराना प्रकरण दर्ज है. अब सीबीआई उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है. सुधींद्र सिंह भदौरिया एसजीआईटीएस इंदौर के निदेशक हैं.

गुलाब सिंह किरार तो मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं...

हां उनके क्लोज हैं, उनके समाज के मुखिया हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं. वह न जाने किस–किस चीज से ओब्लाइज्ड हैं. ऐसे कई लोग हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा हैं, उनके पीए हैं प्रेमचंद्र प्रसाद. प्रेमचंद्र प्रसाद ने सौ–दो सौ भर्तियां करा दीं. उसके कहने से तो नहीं की होगी, किसी ने कहा होगा. उनका खास मित्र सुधीर शर्मा अपने एनजीओ जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं.

व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं...

दु:ख तो इसी बात का है कि जो लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, उन्हें बराबर सुरक्षा नहीं मिलती. आशीष चतुर्वेदी पर कई हमले हुए. आनंद राय को सुरक्षा देते नहीं हैं. 11 बजे सुबह सुरक्षा देते हैं, 7 बजे शाम हटा लेते हैं. ख़तरा तो रात को होता है. प्रशांत पांडेय को भी ख़तरा है. शेष अभय चोपड़ा नागदा में हैं, दूसरे डॉ. गोलक तिवारी हैं और तीसरा मैं. हम लोगों ने सुरक्षा की मांग नहीं की.

अगर व्हिसिल ब्लोअर्स एक्ट आ जाता, तो आप लोगों को सुरक्षा मिलती?

यह सरकार की ड्यूटी बनती है कि वह स्वयं सुरक्षा दे. हम नोटिफाइड व्हिसिल ब्लोअर हैं. एसटीएफ ने जब 27 नवंबर, 2014 को विज्ञापन निकाला, आज से सात महीने पहले कि जिस किसी व्यक्ति को व्यापमं घोटाले में किसी बिंदु को शामिल कराना है, वह दस्तावेज़ सहित आवेदन दे. उसमें पूरे प्रदेश में एकमात्र मैं ही था, जिसने आवेदन दिया. मेरे उस आवेदन पर बीते 12 जून को मेरा बयान लिया गया. उन्हें पता है कि नोटिफाइड व्हिसिल ब्लोअर हैं, उन्हें हमारी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए.

क्या सीबीआई जांच से कोई नतीजा निकलेगा?

सीबीआई भी कोई अल्टीमेट नहीं है. अगर सीबीआई ने ईमानदारी से जांच नहीं की, तो हमें दो महीने में पता चल जाएगा. उम्मीद है कि वह वैसी ग़लती नहीं करेगी, जैसी एसटीएफ ने की कि जांच नीचे से ऊपर शुरू की. पहले लड़कों को पकड़ा, फिर मां–बाप को, फिर सॉल्वर को. बड़े अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं की. जबकि ऑर्गनाइज्ड क्राइम में जांच ऊपर से नीचे करनी चाहिए. अगर सीबीआई ने भी नीचे से ऊपर जांच की, तो हम उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.■

रीगा - बेलसंड विधानसभा

कालापानी की समस्या का निदान नहीं, बनेगा चुनावी मुद्दा

अमित कुमार टुन्ना

अवध किशोर प्रसाद

किरण गुप्ता

मोतीलाल प्रसाद

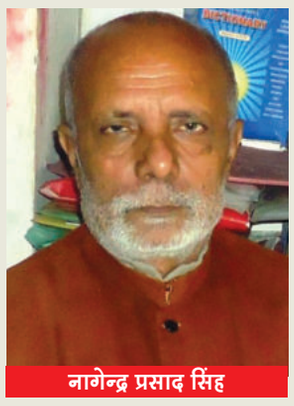

नागेन्द्र प्रसाद सिंह

नगीना देवी

सुनीता सिंह चौहान

सुरेश यादव

बिहार चुनाव विशेष

सीतामढ़ी जिले की एकमात्र औद्योगिक इकाई रीगा चीनी मिल दशकों से क्षेत्रीय किसानों के लिए एक ओर लाभदायक तो दूसरी ओर परेशानी का सबब बनी हुई है. मिठास पैदा करने वाली मिल से निकलने वाला डिस्टलरी का प्रदूषित पानी हजारों किसानों की जमीन में जहर घोलता आ रहा है. साथ ही मनुष्यमारा नदी की धारा में प्रदूषित पानी की निकासी इंसान से लेकर पशु तक के लिए घातक साबित हो रहा है, लेकिन इस गंभीर समस्या के निदान की दिशा में अब तक सार्थक पहल न तो मिल प्रबंधन और न ही जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा सका है. दूसरी ओर बाढ़ व अपराध के लिए सूबे में शुमार बेलसंड क्षेत्र में कई समस्या अब भी गंभीर चुनौती बनी है. इसमें मनुष्यमारा का प्रदूषित पानी की समस्या आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों के लिए मुद्दा बन सकता है. रीगा में भाजपा तो बेलसंड में जदयू का प्रतिनिधित्व है. मगर इस बार दोनों ही सीट के संभावित प्रत्याशियों के लिए चुनावी मुद्दा गंभीर चुनौती बन सकता है.

वाल्मीकि कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही जनमानस में स्थानीय समस्याओं को लेकर चर्चा की जाने लगी है. भले ही चुनाव के समय जाति और पार्टी के चक्रव्यूह में फंस कर लोग मतदान किसी के पक्ष में करें, लेकिन फिलहाल सभी की नजर क्षेत्र की समस्या को टटोलने में है. रीगा विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से गन्ना किसान जहां मूल्य भुगतान को लेकर वर्षों से त्राहीमाम कर रहे हैं, वहीं मिल के डिस्टलरी से निकलने वाला प्रदूषित काला पानी मनुष्यमारा नदी में छोड़े जाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. यह समस्या रीगा के साथ बेलसंड विधानसभा क्षेत्र तक समान बताया जाता है. बेलसंड से तरियानी को जाड़ने वाली कराड़ों की लागत से बागमती नदी पर निर्मित मारडघाट पुल वर्षों से एप्रोच निर्माण के पूर्ण कराये जाने का राह देख रहा है. पुल निर्माण के बाद भी अब तक एप्रोच का निर्माण नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण लोगों के लिए आवागमन की समस्या अब भी गंभीर बनी है. चुनाव का समय करीब आने के साथ ही बेलसंड क्षेत्र में जातीय चुनावी जाल बिछाया जाने लगा है. अब तक के चुनावी इतिहास को खंगाल कर अब नया इतिहास बनाने की कवायद भी शुरू हो गयी है. श्रीकृष्ण चेतना मंच एवं बेलसंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले बेलसंड के कोना-कोना में जातिगत समीकरणों का हवाला देते हुए स्थानीय प्रत्याशी को प्रतिनिधित्व की कमान सौंपने का मुहिम चलाया जाने लगा है. श्रीकृष्ण चेतना मंच के प्रांतीय अध्यक्ष सह अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार विराना उर्फ धीरेंद्र यादव का कहना है कि जातिगत समीकरणों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जायेगी. चल रही चर्चा पर भरोसा करें तो अगर समय रहते इस मुहिम की दिशा नहीं बदली गयी तो प्रत्याशियों के लिए चुनावी राह आसान नहीं होगा.

अब पहले चर्चा करते हैं रीगा विधानसभा क्षेत्र का. गैर सरकारी आंकड़ों पर यकीन करें तो इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन ढाई लाख के करीब है. जिसमें 1 लाख 35 हजार पुरुष एवं 1 लाख 18 हजार महिला मतदाता शामिल हैं. इस क्षेत्र पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है, जहां से मोतिलाल प्रसाद बतौर विधायक हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा

सीतामढ़ी

व जदयू गठबंधन ने इस सीट को भाजपा के पाले में डाली थी, लेकिन वर्तमान में हालात बदले हैं. सूबे की नई चुनावी समीकरण ने पासा उलट दिया है. पिछली बार भाजपा गठबंधन प्रत्याशी ने जिसके खिलाफ जदयू के साथ मिलकर चुनावी समर में ताल ठोंका था, इस बार जदयू ने इसी से चुनावी नाता जोड़ लिया है और अपने पुराने साथी भाजपा को सबक सिखाने को आतुर है. चुनाव के इस मौसम में गठबंधन की राजनीति ने लंबे अर्से से टिकट के लिए परेशान कार्यकर्ताओं को संकट में डाल दिया है. कुछ ने चुनावी तैयारी के साथ पार्टी नेताओं की परिक्रमा शुरू कर दिया है तो कुछ अपने दिल में ही अरमान को दफन किये बैठे हैं. बावजूद इसके, तकरीबन सभी दलों में संभावित प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर गुपचुप तैयारी में लगे हैं. चर्चा चल रही है कि इस बार रीगा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के मोतिलाल प्रसाद को सीधी चुनौती देने के लिए जदयू से नागेंद्र प्रसाद सिंह व किरण गुप्ता तो राजद से पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, रामबाबू यादव, लक्ष्मी प्रसाद यादव चुनावी समर में आने की तैयारी में हैं, जबकि कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके अमित कुमार टुन्ना भी पुन: दावेदारी को लेकर प्रयासरत है. हालांकि राजद-जदयू-कांग्रेस गठबंधन के कारण यह तो तय है कि टिकट किसी एक ही दल के कार्यकर्ता को गठबंधन की खातिर मिलेगा. बताया जाता है कि वैश्य बाहुल्य इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक, राजपूत व यादव मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक है. चुनाव करीब आने के साथ ही दोनों गठबंधन दल के नेतृत्व ने चुनावी अभियान को गति देना शुरू कर दिया है. विधान परिषद चुनाव में मात खा चुकी भाजपा जहां विधानसभा चुनाव में क्षति की भरपाई को लेकर प्रयासरत है, वहीं राजद-जदयू गठबंधन अपनी बढ़त बनाये रखने को लेकर हर घर दस्तक देना शुरू कर दिया है. दोनों ही गठबंधन दल में किसी ने भी अब तक स्थानीय समस्या को चुनावी अभियान में स्थान देना मुनासिब नहीं समझा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है.

अब बेलसंड विधानसभा पर चर्चा भी जरूरी है, जहां चुनावी आहट के साथ ही बाहरी व स्थानीय प्रत्याशी का मामला तूल पकड़ने लगा है. गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन सवा 2 लाख है. श्रीकृष्ण चेतना मंच द्वारा प्रचारित जातिगत आंकडों पर भरोसा करें तो पहले स्थान पर यादव, दूसरे अल्पसंख्यक व तीसरा स्थान राजपूत मतदाताओं का है, जबकि वैश्य बिरादरी अधिक मतदाता होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब तक जातिगत समीकरणों को नजरंदाज कर कई बार राजपूत बिरादरी को प्रतिनिधित्व की कमान मतदाताओं ने सौंपा है. बताया जाता है कि 1972 में कांग्रेस की टिकट पर ठाकुर रामनंदन सिंह, 1977 में जनता पार्टी एवं 1980 व 1985 में लोकदल की टिकट पर डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह, 1990 में कांग्रेस की टिकट पर प्रो दिग्विजय सिंह, 1995 में पुन: राजद की टिकट पर डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह ने बेलसंड का प्रतिनिधित्व किया. 1996 के लोकसभा चुनाव में डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली संसदीय सीट से चुनाव जीत ली थी. तब उप चुनाव में समता पार्टी की टिकट पर वृष्णि पटेल ने राजद प्रत्याशी नागेंद्र प्रसाद सिंह को पराजित कर जीत हासिल किया था. 2000 में राजद के राम स्वार्थ राय एवं 2005 में राजद के संजय गुप्ता ने प्रतिनिधित्व का कमान थामा था. 2010 के चुनाव में भाजपा-जदयू गठबंधन प्रत्याशी के रूप में सुनीता सिंह चौहान ने बाजी मारी थी. अब बारी है 2015 में होने वाले विधानसभा चुनाव की. इस बार राजनीतिक गठबंधन का बदला पैतरा वर्तमान विधायक को नये अंदाज में चुनावी समर में बुलाता प्रतीत हो रहा है. क्षेत्र के परसौनी चौक व भोरहा गांव के चौराहा पर बेलसंड स्वाभिमान मोर्चा का लगाया गया बैनर कुछ ऐसा ही इशारा करता प्रतीत हो रहा है. हालांकि कुछ लोग इसे चुनावी शिगूफा मान रहे हैं. दूसरी ओर श्रीकृष्ण चेतना मंच क्षेत्र में जातीय समीकरणों का हवाला देकर लोगों को स्थानीय प्रत्याशी की मांग उठाने को प्रेरित कर रहा है. चर्चा है कि क्षेत्र में विकास की रफ्तार जिले के किसी भी क्षेत्र की तुलना में सामान्य रही है. चुनावी चर्चा पर यकीन करें तो इस बार चुनाव में जदयू की स्थानीय विधायक सुनीता सिंह चौहान की राजनीतिक घेराबंदी की विरोधी खेमा तैयारी में लगे हैं. बेलसंड की चुनावी फिजा में इस बात की भी चर्चा जोरों पर है कि इस बार विधायक पति राणा रंधीर सिंह चौहान खुद ही चुनावी समर में आने की तैयारी में लगे हैं, जबकि जदयू के ही प्रदेश संगठन मंत्री अवध किशोर प्रसाद भी पार्टी गठबंधन के तहत चुनावी समर में ताल ठोंकने को तैयार हैं. बताया जाता है कि इनकी दावेदारी को लेकर क्षेत्र के मतदाताओं में चर्चा है. जदयू के कब्जा वाली इस सीट पर गठबंधन की राजनीति के कारण भाजपा गठबंधन इस बार नजरें जमाये बैठी है. चर्चा है कि इस सीट पर भाजपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में पूर्व लोजपा विधायक नगीना देवी दावेदारी को लेकर जी जान से लगी हैं. वहीं दूसरी ओर बतौर भाजपा प्रत्याशी अखिलेश सिंह की दावेदारी की चर्चा भी जोरों पर है, जबकि राजद से पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी प्रयासरत हैं. वैसे गठबंधन के तहत टिकट किसके पाले में जायेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर संभावित प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गयी है.

कुल मिला कर दोनों ही विधानसभा सीटों पर दावेदारी करने वालों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गयी है. चुनाव का समय करीब आने तक संभावित प्रत्याशियों की संख्या में इजाफा की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. घात-प्रतिघात के साथ ही चुनाव में वोटों का मोल-जोल की आशंका भी व्यक्त की जा रही है. अब देखना है कि रीगा में डिस्टलरी का कालापानी और बेलसंड का मारडपुल एप्रोच समेत मनुष्यमारा की समस्या चुनावी मुद्दा बनती है अथवा जाति और पार्टी की राजनीति में स्थानीय समस्या गौण हो जाती है.■

feedback@chauthiduniya.com

आलाकमान होगा मेहरबान, तभी युवा होगा पहलवान

विपिन यादव/सहरसा

feedback@chauthiduniya.com

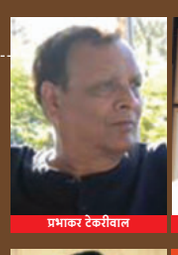

प्रभाकर टेकरीवाल

शशिशेखर झा सम्राट

चंदन सिंह

नीरज गुप्ता

मंजित कुमार सिंह

अंजुम हुसैन

अजय कुमार सिंह

छत्री यादव

रंजीत यादव

शिवशंकर विक्रांत

सीट एक, पार्टी अनेक. सीट एक, सुरमा अनेक. सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं. दल के अंदर ऐसे सुरमाओं की दावेदारी भी बनती है और दल को भी युवा नेताओं की तलाश है. इसलिए दल के अंदर युवा कार्यकर्ताओं की सक्रियता काफी बढ़ी है. आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव में सहरसा विधानसभा सीट पर कई दलों के युवा कार्यकर्ता अभी से ही हाथ-पांव मारने लगे हैं. दल के ऐसे युवा दल के सभी छोटे-बड़े गतिविधियों में न केवल उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, बल्कि क्षेत्र की जनता के बीच दावेदारी को लेकर अपनी खास पहचान बनाने से भी नहीं चुक रहे हैं.

जदयू, राजद व कांग्रेस के महागठबंधन और भाजपा, रालोसपा व लोजपा वाली राजग गठबंधन होने से कई प्रमुख दावेदारों की मानो कमर ही टूट गयी. इनके चुनावी अरमानों पर पानी फिर गया. सभी दलों में चुनाव लड़ने वाले युवा कार्यकर्ताओं की संख्या अधिक है. फिर भी कार्यकर्ताओं की आपसी रेस हम किसी से कम नहीं है. टिकट पाने को आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी कि राजधानी पटना से देश की राजधानी दिल्ली की दूरी इनके लिए महज चंद घंटों की होती है. लेकिन फिर भी सहरसा विधानसभा सीट पर राजद के अजय कुमार सिंह, शिवशंकर विक्रांत, छत्री यादव, रंजीत यादव, कांग्रेस से मनजीत सिंह, नीरज गुप्ता एवं जदयू से अंजुम हुसैन, सोहन झा प्रमुख दावेदार हैं. भाजपा से सीटिंग एमएलए आलोक रंजन व पूर्व विधायक संजीव कुमार झा को छोड़कर प्रभाकर टेकरीवाल, शशि शेखर झा सम्राट, चंदन सिंह, ही प्रमुख दावेदारों में से एक हैं. वैसे कई नाम ऐसे हैं, जिनकी गतिविधि सहरसा में दिखती है, पर वे दावेदारी अन्य विधानसभा सीट के लिए करते हैं.महागठबंधन से राजद के युवा नेता अजय कुमार सिंह इन दिनों सुर्खियों में रहे हैं. लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के चुनाव प्रभारी के रूप में अपनी कुशल रणनीति की बदौलत जीत में भागीदारी का परिचय दे चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए पास हैं और छात्र जीवन से ही राजनीति में न केवल अभिरूचि रखते हैं, बल्कि डीयू में पहली बार राजद के बैनर तले तत्कालीन जनता दल का उम्मीदवार छात्र संघ के चुनाव में खड़ा किया. पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. दिग्विजय सिंह के सानिध्य में दिल्ली प्रवास के दौरान दिल्ली रहकर राजनीतिक ककहरा सीखा. कुछ साल पूर्व चुनाव के दौरान वर्तमान केन्द्रीय मंत्री रामबिलास पासवान को अपने घर दावत देकर राजनीतिक हल्कों में चर्चा का विषय बना दिया. ये सहरसा जिला व्यापार संघ के उपाध्यक्ष हैं और वीर कुंवर सिंह जागरण मंच के अध्यक्ष हैं. इनकी राजनीतिक कुशलता युवाओं में परिचय का मोहताज नहीं है, जबकि प्रदेश युवा राजद के उपाध्यक्ष शिवशंकर विक्रांत की भी गिनती राजद के समर्पित कार्यकर्ता और वैश्य समाज के उभरते युवा नेता में होती है. ये भी सहरसा सीट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं. राजद के किसी भी गतिविधि में ये बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पार्टी में इनकी सक्रियता व कर्मठता ही पहचान है. रंजीत यादव व छत्री यादव की भी अलग चहचान है. रंजीत यादव सोनवर्षा विधानसभा, जब सुरक्षित सीट नहीं थी, से राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं. इसलिए इनकी भी प्रबल दावेदारी बनती है. छत्री यादव अपने दमखम से अपनी मां को जिला पार्षद के रूप में जीत दर्ज करवा चुके हैं. ये एकीकृत जनता दल के कोशी में प्रमुख नेता माने जाने वाले पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव के ही गुरुकुल के शिष्य रहे हैं. एक समय था जब छत्री यादव कुछ बोला तो मानो दिनेश चन्द्र यादव बोला. अब वैसा नहीं है, लेकिन महागठबंधन होने से पुन: राजद में रहते हुए भी दिनेश चन्द्र यादव की सहानुभूति का लाभ इनको मिल सकता है. ये सहरसा सीट से चुनाव लड़ने को प्रयासरत हैं. कांग्रेस के नीरज गुप्ता व मनजीत सिंह के कार्यो में बड़ा फर्क है. नीरज गुप्ता के साथ वैश्य समाज की पहचान है और वे कांग्रेस से चुनाव भी इस सीट से लड़ चुके हैं, जबकि मनजीत सिंह कांग्रेस के नगर अध्यक्ष होते हुए सदर अस्पताल में जिले के बाहर से इलाज के लिए आने वाले गरीबों को मदद करने के लिए रात-दिन मौजूद रहते हैं. इस दिशा में इनकी सार्वजनिक सहायता का प्रयास ही इन्हें दावेदार बना दे रही है. जदयू से अंजुम हुसैन का चेहरा भी साफ दिखाई पड़ रहा है. देखना है कि अल्पसंख्यक होने का लाभ इन्हें पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव दिला पाते हैं या नहीं. भाजपा गठबंधन के शशि शेखर झा सम्राट पूर्व केन्द्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के काफी करीबी माने जाते हैं और पार्टी के प्रदेश स्तर से देश स्तर के नेताओं के बीच भी उनकी पहचान है. संगठन में भी जिला स्तर पर इनकी अलग पहचान है. ये भी अंदर ही अंदर खुद को दावेदार मान रहे हैं.

देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन व महागठबंधन में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, पर गणित के समीकरण में किस दल से कौन सटीक बैठता है. पार्टी आलाकमान किस पर मेहरबान होते हैं. ■

संतोष मांझी लड़ेंगे भाजपा से!

सुनील सौरभ

राजनीति में कब क्या हो जायेगा, यह कहना है मुश्किल है. इसी प्रकार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भी हर दल की ओर से प्रत्याशियों के चयन से लोग चौक उठेंगे, ऐसी संभवना है. गया जिले के दस विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा गठबंधन तथा महागठबंधन के बीच ही मुख्य मुकाबला होना तय है. चुनाव आते-आते वाम दलों का राजनीतिक समीकरण भी साफ हो जायेगा, लेकिन गया जिले के लगभग 45 लाख की आबादी के सामने स्पष्ट रूप से यह तस्वीर सामने आने लगी है कि भाजपा-रालोसपा, लोजपा और हम तथा राजद-जदयू-कांग्रेस गंठबंधन के बीच ही चुनावी संग्राम होना है, लेकिन लोगों को तब आश्चर्य होगा, जब किसी सीटिंग विधायक का पत्ता साफ कर गंठबधन में शामिल पार्टी के नेता टिकट से वंचित किये गये विधायक की पार्टी से प्रत्याशी हो जाये. कुछ ऐसी ही संभावना व्यक्त की जा रही है गया जिले के सुरक्षित बोधगया विधान सभा क्षेत्र के लिए. भाजपा के अंदरखाने से आ रही रिपोर्ट पर विश्वास किया जाये तो बोधगया के वर्तमान भाजपा विधायक श्यामदेव पासवान का इस बार विधान सभा चुनाव में टिकट कटना लगभग तय है. इसका प्रमुख कारण है कि बोधगया विधानसभा क्षेत्र में आने वाले मंडलो (प्रखंडो) के अधिकतर अध्यक्षों तथा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक सुर से विधायक श्यामदेव पासवान के कार्यकलापों से नाराजगी जतायी है. बोधगया में हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी कार्यकताओं की नाराजगी का पता प्रदेश के नेताओं को चला था. कार्यकर्ता की उपेक्षा कर कुछ खास लोगों को ही मदद करने का आरोप विधायक पर लगाया जा रहा है. इन्हीं सब बातों से लोगों को लगता है कि इस बार श्यामदेव पासवान का टिकट कटना निश्चित है. वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष

तथा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष मांझी को भाजपा बोधगया से अपना प्रत्याशी बना सकती है. राजनीतिक गलियारों में चल रही बातों पर विश्वास किया जाये तो इसका प्रमुख कारण है कि संतोष मांझी शुरू से ही भाजपा मे सक्रिय रहे हैं. जीतन राम मांझी जब नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री थे, तब भी संतोष मांझी भाजपा की राजनीति करते थे. जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बन गये ओर इनके परिवार का राजनीतिक रसूख बढ़ गया, तब भी संतोष मांझी भाजपा से न इस्तीफा दिये और न ही भाजपा ने इन्हें पार्टी से निकाला. मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जीतन राम मांझी ने जब नयी पार्टी हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा (हम) का गठन किया, तब भी भाजपा ने संतोष मांझी को पार्टी से नहीं निकाला और न ही इन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया. अब, जब बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल गया तो तब भाजपा भी अपनी राजनीति से लोगों को चौंकाने का प्रयास कर रही है. संतोष मांझी भी बोधगया सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट लेने के लिए सक्रिय हो गये हैं. विरोधी दलों के नेता भी बोधगया से प्रत्याशी देने के मामले में संतोष मांझी को ही सामने रखकर विचार कर रहे हैं. हालांकि श्यामदेव पासवान के समर्थकों का स्पष्ट कहना है कि सीटिंग विधायक को ही पुन: भाजपा से टिकट मिलना तय है. कुछ विरोधी अफवाह उड़ा रहे हैं. इतना तो तय है कि बहुदलीय राजनीतिक परिवार बन चुके जीतन राम मांझी के परिवार के सदस्यों को आने वाले विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों का लाभ मिलना निश्चित है. पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हम के संस्थापक हैं और वे जहानाबाद जिले के ममदुमपुर सुरक्षित क्षेत्र से विधायक हैं तो समधीन ज्योती मांझी बाराचट्टी सुरक्षित सीट से जदयू की विधायक हैं. बेटा संतोष मांझी को भाजपा से बोधगया से टिकट मिलने की बात चर्चा में है.■

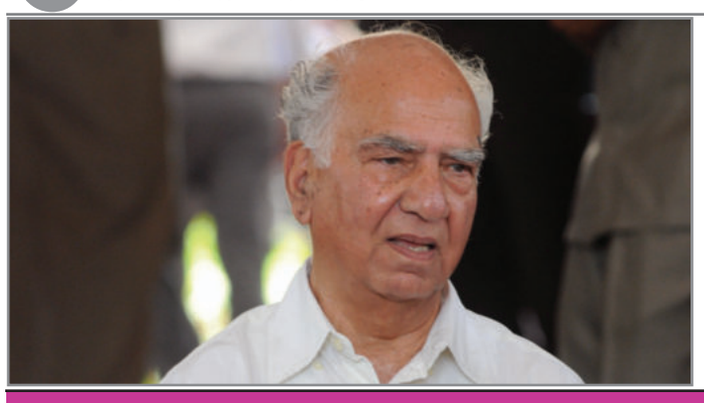

शांता कुमार ने अपने पत्र में जनसंघ का हवाला देते हुए कहा कि तब पार्टी में सबसे ज्यादा जोर मूल्य आधारित राजनीति पर दिया जाता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद मूल्यों की राजनीति से भी कहीं–कहीं सत्ता की राजनीति ने समझौते किये. उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी के अंदर सबकुछ सही नहीं चल रहा है. अपने संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई समिति–आचार समिति का गठन किए जाने की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस समिति में पार्टी के ऐसे अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता रहें, जिन्होंने मूल्यों की रक्षा के लिए कभी किसी प्रकार का समझौता न किया हो. केंद्र और राज्य स्तर पर यह समितियां एक लोकपाल का काम करें.

एनसीईआरटी पेपर खरीद घोटाला

निदेशक की नियुक्ति से पहले जांच पूरी हो

शशि शेखर

नई सरकार के आने के बाद, एनसीईआरटी (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) की निदेशक प्रवीण सिंक्लेयर इस्तीफा दे चुकी हैं. यह इस्तीफा क्यों दिया गया, इस पर कई तर्क दिए जा रहे हैं. लेकिन, इस्तीफे के पीछे पेपर खरीद घोटाले की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है. एनसीईआरटी इस देश की एक महत्वपूर्ण संस्था है. यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत आता है. पेपर खरीद घोटाले की जानकारी सीवीसी को भी है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भी. बकायदा दोनों इसकी जांच भी कर रहे हैं. सीवीसी तो पिछले कई सालों से इसकी जांच कर रहा है, लेकिन दिलचस्प रूप से उससे संबंधित दस्तावेज ही नहीं उपलब्ध करा रहा है. साल 2012 में ही एनसीईआरटी के कुछ कर्मचारियों की ओर से तत्कालीन निदेशक प्रवीण सिंक्लेयर के खिलाफ पेपर घोटाले और अन्य मामलों में शिकायत की गई थी. सीवीसी 2012 से ही मानव संसाधन मंत्रालय के सीवीओ को पत्र लिख कर बार–बार संबंधित दस्तावेज मांग रहा है, लेकिन आज की तारीख तक मानव संसाधन मंत्रालय सीवीसी को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका है. यह अलग बात है कि अब स्मृति इरानी ने मंत्रालय की तरफ से भी एक नई जांच की शुरुआत करवा दी है. यह देखना दिलचस्प होगा कि एनसीईआरटी के नए निदेशक की नियुक्ति से पहले क्या यहां जांच पूरी भी हो पाती है या नहीं. गौरतलब है कि प्रवीण सिंक्लेयर पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं और उनकी जगह एनसीईआरटी के ज्वॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बी के त्रिपाठी कार्यवाहक निदेशक की भूमिका में हैं. प्रोफेसर त्रिपाठी ने सिंक्लेयर के निदेशक रहते हुए विवादास्पद पेपर खरीद मामले में अपनी सहमति दर्ज कराई थी.

यह जानना भी जरूरी है कि आखिर प्रवीण सिंक्लेयर के पीछे क्या विवाद है? दरअसल, सिंक्लेयर के खिलाफ करोड़ों रुपये के मैपलिथो पेपर की खरीद में नियमों की अवहेलना के

आरोप हैं. जनवरी 2012 में, जब वह निदेशक बनीं, तब उन्होंने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग की. इस मीटिंग में उन्होंने कई निर्णय लिए. इसमें एक निर्णय पेपर खरीद से भी जुड़ा हुआ था. पुरानी कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए निदेशक के आदेश पर एनसीईआरटी के सचिव आलोक वर्मा ने टेक्निकल बिड खुलवाने से पहले ही फिनान्शियल बिड खुलवाने का आदेश जारी कर दिया. इसका अर्थ यहां यह हुआ कि जो कम्पनी तकनीकी रूप से अयोग्य थी, वह भी इस बिड के लिए योग्य हो गई. यह कदम नियम के खिलाफ था. इसी मीटिंग में निदेशक ने एनसीईआरटी के 5 कॉलेज में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार भी अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया, जबकि पहले यह अधिकार संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल के पास था. पेपर खरीद के मामले में और भी कई गलत निर्णय लिए गए. जैसे, मैप्लिथो पेपर (किताब की कवर के लिए पेपर) की खरीद के लिए कोई बिड ही नहीं हुआ. एनसीईआरटी के तत्कालीन अधिकारियों, जिसमें निदेशक प्रवीण सिंक्लेयर, सचिव आलोक वर्मा और ज्वॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बीके त्रिपाठी जैसे बड़े अधिकारियों ने समय की कमी का हवाला देते हुए इसके लिए कोई टेंडर ही नहीं निकाला. कहा गया कि

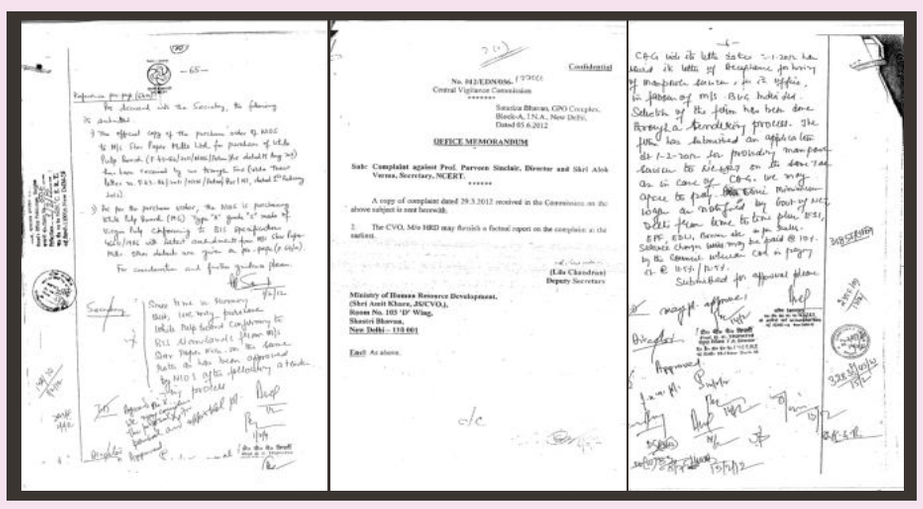

एनआईओएस (एक अन्य संस्था) जिस रेट पर पेपर खरीदता है, उसी रेट पर स्टार पेपर मिल से मैप्लिथो पेपर खरीद लिया जाए. इस पर प्रोफेसर बीके त्रिपाठी ने भी अपनी सहमति जाहिर की और बाकायदा हस्ताक्षर भी कर दिए. दिलचस्प रूप से आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार जिस दिन यह निर्णय लिया गया और यह तर्क दिया गया कि समय की कमी है और इस वजह से बिना टेंडर निकाले पेपर खरीद लिया जए, उस दिन तक एनसीईआरटी के गोदाम में 285 मिट्रिक टन कवर पेपर (मैप्लिथो पेपर) उपलब्ध था. जाहिर है, ऐस निर्णय लेने के पीछे कोई न कोई छुपा हुआ हित जरूर रहा होगा और इसमें पैसे की लेन–देन से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है.

इसके अलावा, एनसीईआरटी में हाउसकीपिंग के लिए (साफ–सफाई के लिए) कम्पनी के चयन के लिए भी कोई टेंडर नहीं निकाला गया है. साल 2012 में कराड़ों रुपये का यह ठेका मेसर्स बीवीजी इंडिया लिमिटेड को दे दिया गया. ऐसा करने के पीछे बहुत ही दिलचस्प तर्क दिया गया है. अपने तर्क में कहा गया कि जिन शर्तों पर कैग कार्यालय ने इस कम्पनी को अपने यहां रखा है, उन्हीं शर्तों पर हम इस कम्पनी को एनसीईआरटी का ठेका दे रहे हैं. यानी, करोड़ों रुपया का ठेका इस कम्पनी को सिर्फ इस आधार पर दे दिया गया कि चूंकि, कैग ने अपने यहां इसे काम दिया है, इसलिए हम भी दे सकते हैं. सवाल है कि क्या करोड़ों रुपये के इस ठेके के लिए कोई टेंडर नहीं निकाला जाना चाहिए था. बाकायदा इसके लिए मौजूदा कार्यवाहक निदेशक और तत्कालीन ज्वॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बीके त्रिपाठी ने भी हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दी थी.

बहरहाल, इन सब की शिकायत एनसीईआरटी के कुछ कर्मचारियों–अधिकारियों ने सीवीसी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी की और कार्रवाई की मांग की, लेकिन सीवीसी पिछले तीन साल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिख कर संबंधित दस्तावेज मंगाने के अनुरोध के सिवाए कुछ नहीं कर सका है. दूसरी तरफ, मई 2014 में नई मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी के आने के बाद ही सितंबर 2014 में प्रवीण सिंक्लेयर इस्तीफा दे चुकी हैं. आलोक वर्मा तबादला करवा कर पहले ही हरियाणा सरकार में जा चुके हैं. यह अलग बात है कि वे अपना काम एनसीईआरटी के कार्यालय से ही करते रहे और बाकायदा इसकी मंजूरी भी दी गई. दूसरी तरफ, ज्वॉइंट डायरेक्टर प्रोफेसर बीके त्रिपाठी अभी कार्यवाहक निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार उन्हें ही नया निदेशक बना देगी. बहरहाल, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी प्रवीण सिंक्लेयर के रहते पेपर खरीद मामले समेत अन्य मामलों की जांच के आदेश दे दिया है. जांच कब तक पूरी होती है, यह देखना बाकी है, लेकिन इसी के साथ यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या जांच पूरी होने से पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर बीके त्रिपाठी की जगह नए निदेशक की नियुक्ती कर देता है या फिर जांच पूरी होने का इंतजार करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शांता कुमार का पत्र कहता है

कई भाजपा नेताओं के मन की बात

चौथी दुनिया ब्यूरो

भाजपा के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को पत्र लिखकर भाजपा में भूचाल ला दिया है. पत्र में शांता कुमार ने लिखा है कि व्यापमं घोटाले और ललितगेट प्रकरण की वजह से पार्टी की साख को धक्का लगा है. भाजपा को लेकर मीडिया में आ रही खबरों से किसी भी भारतीय का हताश–निराश होना स्वाभाविक है. इसे लेकर हमारी तरफ महाराष्ट्र तक उंगलियां उठने लगीं. मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले की खबरों ने हम सबका सिर शर्म से नीचा कर दिया है. देश भर के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है, इन सबके बाद उसे सिर झुकाकर चलना पड़ रहा है.

शांता कुमार ने अपने पत्र में जनसंघ का हवाला देते हुए कहा कि तब पार्टी में सबसे ज्यादा जोर मूल्य आधारित राजनीति पर दिया जाता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद मूल्यों की राजनीति से भी कहीं–कहीं सत्ता की राजनीति ने समझौते किये. उन्होंने इशारों में कहा कि पार्टी के अंदर सबकुछ सही नहीं चल रहा है. अपने संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई समिति–आचार समिति का गठन किए जाने की मांग की है. उन्होंने सुझाव दिया कि इस समिति में पार्टी के ऐसे अनुभवी और समर्पित कार्यकर्ता रहें, जिन्होंने मूल्यों की रक्षा के लिए कभी किसी प्रकार का समझौता न किया हो. केंद्र और राज्य स्तर पर यह समितियां एक लोकपाल का काम करें. सत्ता में बैठे हुए नेताओं को ठीक समय पर उनकी गलती बताने का साहस कर सके. आज जो आरोप कुछ प्रदेशों में हम पर लग रहे हैं, यह सब कुछ एकदम से नहीं हो गया. यह बहुत पहले शुरू हुआ होगा और जरूर समय पर कहीं कहीं पता लगा होगा. कुछ लोगों में चर्चा हुई होगी, लेकिन कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण समय से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी. उस कमी का मूल्य आज देश भर में पूरी पार्टी को चुकाना पड़ रहा है. पूरे भारत की राजनीति छल–कपट, स्वार्थ और केवल वोट व सत्ता की राजनीति बन गई है. देशभक्ति व सेवा की राजनीति बहुत कम दिखती है. इसमें केवल हमारी पार्टी आशा की अंतिम किरण है. यदि हम भी इसमें पूरी तरह सफल न हो पाये तो इतिहास हमें कभी क्षमा नहीं करेगा.

इससे पहले भी शांता कुमार कई बार राजनीतिक भूचाल ला चुके हैं. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान उन्होंने वैंकेया नायडू और राजनाथ सिंह के विभागों पर प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं, इसके बाद वे पार्टी से बर्खास्त भी हो चुके हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते निशाने पर लिया था और कहा था कि मैं गुजरात की लाशों पर राजनीति करने की बजाए तत्काल त्यागपत्र दे देता.

यह पत्र भाजपा के उन लोगों के दिल की आवाज है, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में कुछ कह नहीं पा रहे हैं. शांता कुमार के इस पत्र को भाजपा

शांता कुमार के पत्र को लेकर पार्टी के अंदर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पूर्व सांसद और जनसंघ के संस्थापक सदस्य सारंग ने शांता कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि व्यापमं के आरोपों से नहीं, आपके द्वारा लिखे गए पत्र से कार्यकर्ता का सिर शर्म से झुका है. उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के झूठे आरोपों से पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है.

के कई सांसदों और मंत्रियों का अंदर से समर्थन प्राप्त है. पिछले कुछ समय में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और कलराज मिश्र जैसे लोग शामिल हैं. इस तरह की रह–रह कर बातों का सामने आना पार्टी के अंदर बढ़ती खाई को दर्शाता है. पुराने कार्यकर्ताओं को मोदी–शाह गठजोड़ में घुटन सी महसूस हो रही है, लेकिन इन्हें संघ की ओर से मिल रहे समर्थन की वजह से पार्टी में विद्रोह के स्वर बुलंद नहीं हो पा रहे हैं. वैसे, सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई मंत्री और सांसद इस पत्र का भीतर ही भीतर समर्थन भी दे रहे हैं. ये अलग बात है कि मौजूदा हालात में ये नेता खुल कर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं.

शांता कुमार के पत्र को लेकर पार्टी के अंदर अलग–अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. पूर्व सांसद और जनसंघ के संस्थापक सदस्य सारंग ने लिखा है कि कांग्रेस के झूठे आरोपों से पार्टी का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहा है. आपके पत्र ने इस लड़ाई को कमजोर किया है. कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं. इस पत्र से लगता है कि आप अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं. यही कारण है कि इसे मीडिया में दिया गया है.

केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि शांता कुमार कांग्रेस के दुष्प्रचार में फंस गए हैं. पार्टी शांता कुमार की कही बातों से अपने को पूरी तरह अलग करती है. उन्होंने कहा कि हम शांता कुमार को परिपक्व नेता मानते हैं, लेकिन लगता है कि वे कांग्रेस दुष्प्रचार के जाल में फंस गए हैं. शांता कुमार ने इस पत्र के सार्वजनिक होने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस पत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे. यह गलती से सार्वजनिक हो गया. भाजपा से तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद भी शांता कुमार कह रहे हैं कि वह अपने एक एक शब्द पर कायम हैं. उनका कहना है कि मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते अपनी बात रखने की कोशिश की. अब फैसला पार्टी को करना है और वे क्या करते हैं, मैं उसका इंतजार करूंगा. हालांकि शांता कुमार के तेवर बागी नहीं लग रहे हैं, लेकिन साथ ही वे यह संकेत भी दे गए कि पार्टी के पुराने नेता पार्टी के मौजूदा नेतृत्व की राजनीतिक शैली को बहुत दिन तक नहीं सहने वाले हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत में नीरा का आगमन

नीरा राडिया 1995 में भारत आईं. सबसे पहले वह सहारा समूह में लायजन अधिकारी के रूप में काम करने भारत आई थीं. ऐसा लगता है, भारतीय मिट्टी से सामना होते ही राडिया बदल गईं. उनके पुराने विदेशी सहकर्मी बताते हैं कि राडिया में एक जादुई क्वालिटी थी. वह मोहक व्यक्तित्व की धनी थीं. ट्रैवल बिजनेस और एविएशन (विमानन), सरकारी नीतियों और फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में नीरा राडिया की तकनीकी दक्षता को देख-सुनकर सामने वाला हतप्रभ रह जाता था.

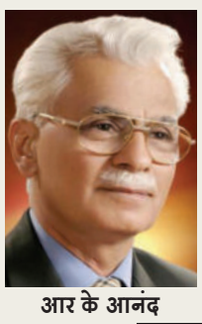

आर के आनंद

1995 का साल था. डिलाइसेंसिंगम प्रोडक्शन कोटा जैसे शब्द पुराने हो रहे थे. आयात और स्टॉक मार्केट का उदारीकरण हो रहा था. सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार ख़त्म हो रहा था. इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलिकॉम सेक्टर का जबरदस्त विस्तार होने जा रहा था. इसी वक्त केन्या में जन्मीं, 1970 में लंदन आईं और अपना लंबा समय बिता चुकीं नीरा राडिया भारत आती हैं. आधुनिक समय की पीआर कंपनी को जैसे लोग चाहिए, उसमें नीरा बमुश्किल फिट बैठती थीं. शायद ही किसी एचआरडी ने नीरा का रिज्यूमे (नौकरी के लिए दिया जाने वाला आवेदन) प्रबंध निदेशक तक पहुंचाया हो. भारत आने के वक्त तक नीरा एक असफल उद्यमी थीं. 1981 में उनकी शादी एक ट्रैवल एजेंट जनक राडिया से हुई थी. उनके तीन बेटे हैं, अक्षय, करण एवं आकाश. वे यात्रा संबंधी कई धधों में कूदे, लेकिन ब्रिटेन के कंपनी लॉ ऑफ डिस्क्लोजर या खस्ताहाल आर्थिक स्थिति की वजह से असफल रहे. लंदन के उपनगरीय इलाके वेंबले, किंग्सबरी और हेंडन में नीरा का जीवन कुछ खास नहीं था. जो लोग उन्हें जानते भी थे, वे सिर्फ़ एक ट्रैवल एजेंट की पत्नी के तौर पर जानते थे.

असफलता का सिलसिला

भारत आने से पहले तक नीरा का बायोडाटा उनके बिजनेस और ज़िंदगी की असफलता से भरा हुआ था. नीरा 1979 में केन्या से लंदन पहुंची थीं. यूनिवर्सिटी ऑफ वार्बिक में पढ़ाई के बाद एक असफल शादी की कहानी और फिर उसके बाद असफल बिजनेस की कहानी. यह सिलसिला लंबा है. लंदन में उनके बिजनेस का ट्रैक रिकार्ड देखिए:-

ट्रैवल नेटवर्क लिमिटेड : 22 जुलाई, 1988 को स्थापित की गई इस कंपनी की सेक्रेटरी थीं नीरा राडिया. उसके पति जनक राडिया कंपनी के निदेशक थे. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा 20 जुलाई, 1993 को यह कंपनी भंग कर दी गई.

पैलेवियन टूर्स लिमिटेड : यह कंपनी सात फरवरी, 1989 को स्थापित की गई. इसके निदेशक जनक राडिया थे. इसका गठन ट्रैवल एजेंट्स से जुड़े कामों के लिए किया गया था. 10 दिसंबर, 1991 को यह कंपनी भी भंग कर दी गई.

सेडगेसरेस्ट लिमिटेड : आठ अक्टूबर, 1990 को यह कंपनी बनी और 26 जुलाई, 1994 को भंग हो गई. नीरा राडिया इस कंपनी की निदेशक थीं. इस कंपनी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.

ट्रैवल फर्स्ट लिमिटेड : 10 सितंबर, 1992 को यह कंपनी बनाई गई. नीरा राडिया इसकी निदेशक थीं. ट्रैवल एजेंट्स एवं टूर ऑपरेटर्स, शिप एयरक्राफ्ट्स, मोटर्स और अन्य वाहनों के काम के लिए यह कंपनी बनी थी. 13 जून, 1995 को यह कंपनी भी बंद हो गई.

हॉलीडे टू ट्रेजर लिमिटेड : 15 नवंबर, 1993 को बनाई गई इस कंपनी की निदेशक नीरा राडिया थीं. इसका उद्देश्य भी टूर ऑपरेटर के तौर पर काम करना था. यह कंपनी भी 12 सितंबर, 1995 को बंद कर दी गई.

क्राउनमार्ट लिमिटेड : यह 19 फरवरी, 1992 को रजिस्टर्ड हुई राडिया की पहली अपनी कंपनी थी. इसमें राडिया के पिता इकबाल नारायण मेनन की हिस्सेदारी एक फ़ीसद और उनके तीनों बेटों अक्षय, करण एवं आकाश की 33-33 फ़ीसद हिस्सेदारी थी. राडिया की बहन करुणा मेनन कंपनी की सचिव थीं. फरवरी 1995 में जब कंपनी की आर्थिक हालत खराब हुई, तब इसकी देनदारी क़रीब एक लाख पाउंड की थी.

डेस्टीनेशन वर्ल्डवाइड लिमिटेड : एक ट्रैवल एजेंसी बिजनेस, जिसमें नीरा राडिया, उनकी बहन, पिता शेयर होल्डर्स थे. 1994 में इसकी देनदारी 8,00,000 पाउंड की थी.

एर्लिंग्टन हॉलीडेज लिमिटेड (पूर्व में माया हॉलीडेज लिमिटेड) : 25 जुलाई, 1989 को स्थापित इस कंपनी में नीरा राडिया और उनके पिता शेयर होल्डर्स थे. 1993 में वे दोनों इस फर्म से निकल गए. राडिया के निकलने के दो महीने बाद ही अगस्त 1993 में कंपनी बंद हो गई.

हेलिकॉप्टर खरीद प्रक्रिया में नीरा राडिया द्वारा दिखाई गई क्षमता से सोफेमा कंपनी प्रभावित थी. सोफेमा ने राडिया को दो और काम ऑफर किए, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार को हेलिकॉप्टर बेचने के. दोनों सरकारों ने अपना इरादा भी जता दिया था. आत्मविश्वास से लबरेज नीरा राडिया सिंह को अपने साथ लंदन ले गईं. वहां वह सोफेमा के साथ इस कांट्रैक्ट पर साइन करने गई थीं.

नया मोड़

नीरा 1995 में भारत आईं. सबसे पहले वह सहारा समूह में लायजन अधिकारी के रूप में काम करने भारत आई थीं. ऐसा लगता है, भारतीय मिट्टी से सामना होते ही राडिया बदल गईं. उनके पुराने विदेशी सहकर्मी बताते हैं कि राडिया में एक जादुई क्वालिटी थी. वह मोहक व्यक्तित्व की धनी थीं. ट्रैवल बिजनेस और एविएशन (विमानन), सरकारी नीतियों और फॉरेन इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के बारे में नीरा राडिया की तकनीकी दक्षता को देख-सुनकर सामने वाला हतप्रभ रह जाता था. यह सही है कि लंदन में रहते हुए नीरा ने काम करने का जो तरीका सीखा, वह भारत में काम करने के लिए मददगार साबित हुआ, जबकि उस सबका लंदन में कोई खास महत्व नहीं था. वेंबले में एक आकर्षक भारतीय नारी का धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना कोई खास बात नहीं है, जबकि दिल्ली के लिए यह एक बहुत बड़ी बात है. उनके दोस्त बताते हैं कि नीरा राडिया की नॉलेज, उनकी भाव-भंगिमा और प्रस्तुति ऐसी थी कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को बैठाकर उनकी (राडिया) बात गंभीरता से सुनने के लिए मजबूर किया जा सकता था.

किसी भी ताकतवर आदमी से आमने-सामने बात करते हुए भी वह बहुत सहज रहती थीं. इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आख़िर क्यों वह अपने मकसद में आसानी से आगे बढ़ने लगीं. उनकी पहली सफलता सुब्रत राय की सहारा एयरलाइंस से जुड़ी हुई है. दिल्ली एयरपोर्ट के कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ इस एयरलाइंस की कुछ समस्या थी. अनुनय-विनय करके मुलाकात का समय हासिल करने की स्थापित परंपरा की जगह नीरा राडिया ने पांच शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग (बैठक) अपने घर पर आयोजित करा दी. इस बैठक में उसने एयरलाइंस की समस्या पर बात कराई और त्वरित समाधान निकलवाए. बैठक में सुब्रत राय के खास एवं वरिष्ठ सहारा अधिकारी राव धीरज सिंह भी मौजूद थे. यह बैठक सिर्फ़ सहारा एयरलाइंस की समस्या का समाधान निकलवाने भर के लिए नहीं थी. इस बैठक का इस्तेमाल नीरा राडिया ने भविष्य के सहयोगियों की तलाश और भविष्य के अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी किया. सहारा जैसी संस्था का इस्तेमाल तो उन्होंने सिर्फ़ अपनी क्षमता का आकलन करने, अपना अनुभव बढ़ाने के लिए किया था. मीटिंग के बाद उन्होंने राव धीरज सिंह को बुलाया और उनकी जमकर तारीफ की. इसके एक महीने बाद ही उन्होंने सिंह को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि वह मुंबई में एक निजी काम शुरू करने जा रही हैं. यह काम था, ऐतिहासिक मरीन ड्राइव पर स्थित सी-रॉक होटल के पुनरुत्थान का. इस पर चंदरू पंजाबी का नियंत्रण था. राडिया ने सिंह से सीधे पूछा कि क्या वह इस काम में उनके साथ आ सकते हैं? सिंह यह जानते थे कि राडिया बहुत चालाक औरत है, लेकिन वह मान गए. मार्च 1996 में सहारा एयरलाइंस की नौकरी छोड़कर सिंह राडिया के साथ आ गए. राडिया ने उन्हें शीर्ष पद से नवाजा. उस वक्त सिंह की शादी अंजुम से हुई थी. अंजुम जेट एयरवेज में काम करती थीं और दिल्ली में ही रहती थीं. सिंह मुंबई आ गए और अंजुम दिल्ली में ही रहीं. नीरा राडिया को अब होटल सी-रॉक के लिए एक वित्तीय योजना बनानी थी और विदेशी होटल मैनेजमेंट कंपनीज को आकर्षित करना था, लेकिन होटल सी-रॉक भी राडिया का पहला प्यार नहीं था.

पहली असल डील

इस दौरान सिंह और राडिया एक साथ बहरीन गए. वहां उन्हें एक अधिग्रहण के सिलसिले में वित्तीय प्रस्ताव पर बात करनी थी. डील में एक भागीदार के रूप में सहारा एयरलाइंस के सीईओ यूके बोस भी उनके साथ थे. इस ट्रिप की वजह से सिंह की निजी ज़िंदगी में भी तूफान आ गया. उनकी पारिवारिक मंडली के बीच उनके और राडिया के बीच संबंध की बातें तैरने लगीं. नतीजतन, सिंह और अंजुम के बीच तलाक हो गया. बहरीन में बिजनेस ट्रिप और बातचीत के बाद नीरा राडिया और सिंह अब बड़ी डील के लिए तैयार थे. सहारा ने यूरोकॉप्टर्स से पांच हेलिकॉप्टर खरीदे थे. दोनों को इसके बदले लंदन की कंपनी सोफेमा के ज़रिये मोटा कमीशन मिला. सिंह ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि इस धन को भारत लाने के लिए उन्हें एवं राडिया को लंदन और दुबई के कई चक्कर लगाने पड़े. इस सफल डील और हाथ में पैसा आने के बाद सिंह एवं राडिया न सिर्फ़ पार्टनर के तौर पर निकट आ गए, बल्कि दोनों भावनात्मक रूप से भी एक-दूसरे के क़रीब होते चले गए. नीरा राडिया सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया के अपने आवास (यह घर पूर्व पहलवान एवं फिल्म अभिनेता दारा सिंह का था) से निकल कर असोला के सुदेश फॉर्म्स आ गईं. यह एक पॉश इलाका है, जो राडिया के सोशल स्टेट्स को बढ़ाता था. इस दौरान वह अपने तीनों बेटों और बहन को भारत ले आईं. उनकी महत्वाकांक्षा उफान पर थी. वह हमेशा से एक शीर्ष बिजनेस हाउस की मुखिया बनना चाहती थीं. इसलिए उन्होंने एक भारतीय कंपनी के रूप में क्राउनमार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की. मार्बल और ग्रेनाइट के एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने एक और कंपनी माउंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड बनाई. नीरा और सिंह ने अपने बढ़ते काम का बोझ सिंह के भतीजों राहुल एवं चेतन के ज़रिये हल्का करने पर सहमति बना ली.

हेलिकॉप्टर खरीद प्रक्रिया में नीरा राडिया द्वारा दिखाई गई क्षमता से सोफेमा कंपनी प्रभावित थी. सोफेमा ने राडिया को दो और काम ऑफर किए, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार को हेलिकॉप्टर बेचने के. दोनों सरकारों ने अपना इरादा भी जता दिया था. आत्मविश्वास से लबरेज नीरा राडिया सिंह को अपने साथ लंदन ले गईं. वहां वह सोफेमा के साथ इस कांट्रैक्ट पर साइन करने गई थीं. इसमें राज्य सरकारों की ओर से एक सख्त बाध्यता थी कि इस खरीद में किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होगी. बावजूद इसके नीरा राडिया ने यह क़दम उठाया. अभी तक किसी भी सरकार ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. व्यक्तिगत स्तर पर सिंह, नीरा राडिया और उनके बच्चे एक परिवार की तरह साथ रह रहे थे. असल में, किसी भी सोशल गेदरिंग (सामाजिक मिलन समारोह) में राडिया अपने आपको राव धीरज सिंह की पत्नी के रूप में पेश करती थीं. नीरा राडिया ने न सिर्फ़ सामाजिक निमंत्रण पर सिंह की पत्नी के तौर पर हस्ताक्षर किए, बल्कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट पर भी उन्होंने इसी हैसियत से हस्ताक्षर किए.

जारी....

feedback@chauthiduniya.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें, तो मराठवाड़ा विकट समस्या का सामना कर रहा है. सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि यहां या तो बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ता है. दोनों ही परिस्थितियों में किसान परेशान होता है. मेरे हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर को उनके खुद के भरोसे छोड़ देना चाहिए, वे अपना ख्याल रख सकते हैं. खराब से खराब दौर में, यहां तक कि नेहरू के या समाजवादी दौर में भी कॉरपोरेट सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर था. जो अच्छा कर रहे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भलाई के लिए रास्ता तलाश लेंगे.

वादों-बयानों के बजाय काम करने की ज़रूरत है

संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू हो चुका है. सत्र के पहले तीन-चार दिनों तक गतिरोध बना रहा. संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इन बातों को लेकर अफवाहें उड़ चुकी थीं कि दोनों पक्ष आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, इसलिए विधेयकों को लाने और पारित कराने की प्राथमिकता ठंडे बस्ते में डाल दी गई है. यहां तक कि भाजपा ने खुद यह निर्णय ले लिया है कि सिर्फ़ विधेयक पारित कराने के लिए अपने मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों के इस्तीफ़े लेना कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि ऐसा करने से कांग्रेस मजबूत होगी और भाजपा ठीक से काम नहीं कर पाएगी. अगर ऐसा है, तो विधेयकों का पारित होना बहुत ही कठिन है. इसलिए भाजपा ने इस सबके बीच यह निर्णय लिया है कि किसी भी क़ीमत पर भूमि अधिग्रहण विधेयक बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने तक पारित न किया जाए.

जीएसटी बिल में कांग्रेस का स्वार्थ निहित है, क्योंकि यह उसका बिल है, इसे वही लाई थी. भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ विचार-विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि वह इस सबसे हटकर एक सीमा तक आगे बढ़ेगी, अगर संसद में काम नहीं होता है या संसद को नहीं चलने दिया जाता है. भाजपा ने सफलतापूर्वक विपक्ष के रुख में थोड़ा परिवर्तन ला दिया है. कांग्रेस और सीपीएम के अलावा कोई अन्य राजनीतिक दल इस्तीफ़े वाली बात पर ज़ोर नहीं दे रहा है. यहां तक तो भाजपा ने सफलता हासिल कर ली है. हर बात पर इस्तीफ़े के लिए कहना, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इस्तीफ़ा हो, यह सही नहीं है. किसी भी स्थिति में मुख्यमंत्री संसद का हिस्सा नहीं हो सकता. आप सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं, उनके इस्तीफ़े के लिए कह सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन आप संसद को ठप्प कैसे कर सकते हैं?

संविधान के मुताबिक, चौहान या राजे नरेंद्र मोदी के अधीन नहीं हैं. वे मुख्यमंत्री हैं. दोनों पक्ष भ्रम की स्थिति में हैं. कांग्रेस इसलिए भ्रम में है, क्योंकि उसे सत्ता में रहने की आदत है और अब वह सिर्फ़ 44 सांसदों के साथ लोकसभा में है. अभी वह हताशा की स्थिति में है. राहुल गांधी ने अभी तक आक्रामक लीडरशिप का संकेत नहीं दिया है, भले ही यहां-वहां कुछ बयान ज़रूर दे रहे हैं. भाजपा में सक्षम लोगों की संख्या बहुत कम है. नरेंद्र मोदी खुद तो सक्षम हैं, लेकिन उनके मंत्री कमज़ोर हैं. वे शासन चलाने में मोदी की मदद नहीं कर सकते. ऐसे में क्या होगा, इसकी उम्मीद आसानी से की जा सकती है. भाजपा ने एक अनौपचारिक निर्णय लिया है कि यदि विधेयक पारित नहीं होते हैं, तो संसद को राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया जाए. बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इसलिए दोनों पक्ष ऐसी बातें करेंगे, जो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रासंगिक हों. इसलिए हो सकता है कि भाजपा अगले कुछ दिनों में लालू यादव के शासनकाल के आंकड़े पेश करने लगे और बताए कि लालू के शासनकाल में क्या हुआ था. चुनाव में होने वाली बात को संसद के भीतर जगह देना सही नहीं है.

जी न्यूज ने बिहार के एक सर्वे में नीतीश-लालू गठबंधन के मुक़ाबले भाजपा को दो फ़ीसद अधिक वोट दिए हैं. जी न्यूज लगातार नरेंद्र मोदी और भाजपा का समर्थन करता रहा है और यदि वह यह मानता है कि अंतर सिर्फ दो फ़ीसद का है, तब भी हमें यह समझना चाहिए कि नीतीश-लालू आगे हैं. सर्वे में यह भी कहा गया है कि 43 फ़ीसद लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को पसंद किया है. यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है. कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बिहार में धर्मनिरपेक्ष ताकतें आगे हैं और वे भाजपा को सत्ता में आने से रोकने में सफल रहेंगी.

प्रशासन दुरुस्त करने के लिए जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र को महत्व नहीं मिल रहा है. हम आज भी वर्षा पर निर्भर हैं. ठीक है, लेकिन अगले कुछ सालों में आक्रामक क़दम उठाने होंगे. नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह किसानों को वर्षा की निर्भरता से मुक्ति दिलाएं. ज़्यादा से ज़्यादा खेतों तक सिंचाई व्यवस्था पहुंचे, ताकि किसानों की वर्षा पर निर्भरता कम हो सके. सिर्फ़ वर्षा आधारित कृषि के लिए आपको सरकार की ज़रूरत नहीं है. सरकार को वहां पानी ले जाना होगा, जहां पानी नहीं है. कृषि मंत्री संवेदनशील हैं. ठीक है, लेकिन उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है. इसका एक कारण है. ऐसे अख़बार, जो कॉरपोरेट घरानों द्वारा चलाए जाते हैं, वे सिर्फ़ कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, जैसे कि कर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, काला धन, स्टॉक मार्केट आदि. वे शायद ही कृषि पर कोई रिसर्च करके स्टोरी करते हों. यह ग़लत है. हमारी जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. अगले दस-बीस सालों में बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी. आज ज़रूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग, जिसके वह खुद अध्यक्ष हैं, के उपाध्यक्ष या किसी अन्य संस्था को एक ठोस योजना बनाने के लिए कहें, ताकि किसानों और किसानी को सूखा और बाढ़ से मुक्ति मिल सके.

महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें, तो मराठवाड़ा विकट समस्या का सामना कर रहा है. सबसे ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि यहां या तो बाढ़ आती है या फिर सूखा पड़ता है. दोनों ही परिस्थितियों में किसान परेशान होता है. मेरे हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर को उनके खुद के भरोसे छोड़ देना चाहिए, वे अपना ख्याल रख सकते हैं. खराब से खराब दौर में, यहां तक कि नेहरू के या समाजवादी दौर में भी कॉरपोरेट सेक्टर का प्रदर्शन बेहतर था. जो अच्छा कर रहे हैं, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी भलाई के लिए रास्ता तलाश लेंगे. हालांकि, सामान्य गणना के अनुसार, एक बड़ा अंतर यह आया है कि वित्त मंत्री को पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी आने की वजह से एक लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल गए हैं. एक लाख करोड़ रुपये काफी बड़ी धनराशि है. यदि नई सरकार ग़रीबों और किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के प्रति वाकई गंभीर है, तो यह धनराशि उनके उत्थान के लिए बेहद मददगार साबित होगी. मैं खुश हूं कि सरकार ने इस बात को समझा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना (मनरेगा) खराब योजना नहीं है. हालांकि, इसमें देश में चलने वाले अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं की तरह कई खामियां हैं, लेकिन मनरेगा के सकारात्मक पक्षों को नकारा नहीं जा सकता. इसकी वजह से ग़रीबी के स्तर में कमी आई है, ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग ग़रीबी रेखा से ऊपर आए हैं. इसलिए सरकार से यह अपेक्षा है कि वह इस एक लाख करोड़ रुपये का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने में करेगी.

मुझे एक शब्द कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा. वह है, उत्पादकता. दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देश भी अपनी उत्पादकता की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए सदैव चिंतित रहते हैं. हमारे निर्यात में कमी आ रही है, क्योंकि हमारे उत्पादन की लागत बेहद ज़्यादा है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मंदी का माहौल है या कहें मांग में कमी आई है, लेकिन हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट तकनीक में आवश्यकतानुरूप सुधार न करने की वजह से आ रही है. एक तरफ़ उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है और प्रधानमंत्री श्रम सुधारों की बात कर रहे हैं. इसका औचित्य मेरी समझ से परे है. मुझे लगता है कि मज़दूरों से जुड़े क़ानून काफी हद तक ठीक हैं, ज़रूरत सिर्फ़ मज़दूर यूनियनों के साथ बातचीत की पहल करने की है. यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, तो ये नौकरियां द्वितीयक क्षेत्र में दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने मज़दूरों को इतनी सुविधाएं दे दी हैं कि रोज़गार देने वाले लोग ज़्यादा लोगों को नौकरी देने में घबराते हैं, क्योंकि उन्हें ये सभी सुविधाएं मज़दूरों को मुहैया करानी होंगी. इसलिए द्वितीयक क्षेत्र का वरीयता के आधार पर सृजन करें. उदाहरण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्ड दें और प्रोविडेंट फंड की तरह वेतन का एक निश्चित प्रतिशत काटकर एकमुश्त देना सुनिश्चित करें. लेकिन, हम ईएसआईसी या अन्य पेंशन फंड लागू करके स्थिति को बेहद पेचीदा बना लेते हैं, जिन्हें लागू कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है. अब समय बदल गया है. ईएसआईसी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि विभिन्न बीमा कंपनियां कई तरह का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करा रही हैं.

आइए, इस देश के हर मज़दूर, हर किसान को बीमा के दायरे में लाएं. जिस तरह किसान देश की अर्थव्यवस्था के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं, उसी तरह हमें भी उनकी भलाई के लिए काम करना होगा. हालांकि, हमने आईएमएफ और विश्वबैंक के मॉडल को अपनाया है, इसलिए हम उनकी बेहतरी के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन, आधे मन से काम करके उनका उद्धार नहीं होगा. मेरे ख्याल से सरकार को जुबानी वादों से परे हटकर गंभीरता से काम करना चाहिए. हर मंत्री एक ऐसा बयान दे देता है, जिसे पूरा कर पाना संभव नहीं होता. उन्हें बयान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए और यह आकलन कर लेना चाहिए कि क्या उसे समय रहते पूरा किया जा सकता है. हालांकि, अगले दो-तीन महीने बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में गुज़र जाएंगे, लेकिन कम से कम उसके बाद चीजों में बदलाव आना चाहिए. खैर, आगे क्या होगा, देखते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंततः छविराम मारा गया-3

सिपाही की शहादत से उबले साथी बन गए यमदूत

कर्मवीर सिंह ने सिपाहियों की चार टुकड़ियां मैनपुरी रोड व करहल-घिरोर रोड पर लगा दीं, ताकि छविराम उस ओर से निकल न सके. मेघ सिंह राणा द्वारा पीछा किए जाने के कारण छविराम कहीं रुक नहीं पा रहा था. उसने मुसाहतपुर में अपने पास का कुछ सामान छोड़ा और केवल गोलियां लेकर आगे बढ़ा कि पुलिस से फिर उसकी मुठभेड़ हो गई. वह फिर पीछे हटा तथा पीतेपुर होते हुए रामताल के पास पहुंचा. ज़ाहिर है, छविराम अपनी गोलियां बचाने की कोशिश में था. उसके साथ इस समय 26 आदमी थे. उन्होंने खेतों से बचते हुए मिलिक के पास सोथरा में पहुंच कर आधा घंटा आराम किया. यहीं उन्होंने आलू भूनकर खाए और पानी पिया. छविराम ने यहां अपनी पुरानी रणनीति के अनुसार अपने गिरोह के दो टुकड़े किए. एक टुकड़े में उसने मथुरा सिंह, कैलाश सिंह, अजंट सिंह, कमांडर तथा बिशना जाटव को रखा तथा उनसे कहा कि वे नए लोगों को लेकर एक तरफ़ से निकलें, वह दूसरी तरफ़ से निकलेगा. उनकी यह रणनीति बन ही रही थी कि पुलिस दल वहां आ पहुंचा और फिर गोलियों का आदान-प्रदान शुरू हो गया.

छविराम के पास एटा के नथुआपुर में शहीद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह से लूटी गई लाइट मशीनगन तथा एसएलआर सहित स्प्रिंगफील्ड राइफलें थीं, लेकिन यही विशिष्ट हथियार उसकी मौत के दूत बन गए. एलएमजी व एसएलआर के फायरों से पुलिस को लगातार पता चलता रहा कि छविराम कहां है. अतः पुलिस वालों ने मथुरा सिंह व कैलाश की टुकड़ी से अपने को उलझने से बचाया. लेकिन, जब तक वे मथुरा सिंह व कैलाश यादव को पीछे ढकेल कर छविराम से मोर्चा लेते, तब तक वह हरैना की तरफ़ बढ़ चुका था. हरैना में छविराम ने फिर पानी पिया और आगे बढ़ा. उसे अंदाज़ नहीं था कि पुलिस इस बार मैन पैक वायरलेस सेट से तालमेल बनाए हुए है. उसने हरैना से चार फर्लांग आगे से जाती करहल-घिरोर सड़क को पार करने का प्रयास किया, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे पीएसी की गाड़ियां खड़ी दिखाई दीं. अपने एक घायल साथी को उसने हरैना के पास के खेत में छोड़ दिया था. अटा का नगला व हरैना के बीच में खड़ी अरहर की आड़ से सुकरमपाल सिंह व कर्मवीर सिंह की टुकड़ी ने छविराम पर फायर किया. हरैना की तरफ़ से मेघ सिंह राणा आ गए. छविराम एक किलोमीटर दूर ठाकुरों के गांव नवाटेढ़ा की तरफ़ बढ़ने के लिए सेंगर नदी की तरफ़ बढ़ा कि बर्नाहर के थानाध्यक्ष एपी सिंह व विजय सिंह ने उसे घेर लिया. छविराम नदी की तलहटी में अपने साथियों सहित मोर्चा लेकर बैठ गया. यहां नदी अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह मुड़ी है. नदी के ऊपर लगभग समतल मैदान है, दाएं-बाएं कुछ खेत अवश्य हैं.

उस समय साढ़े तीन बज रहे थे. छविराम अपने ग्यारह साथियों सहित आराम से सेंगर नदी की तलहटी में बैठा था. यहां बैठकर उसने सिगरेट भी पी. उसके व पुलिस वालों के बीच महज दो सौ गज का फासला था. आधे घंटे बाद अचानक पुलिस वालों ने उस पर गोली चलाई. जवाब में छविराम की ओर से भी गोली चली. छविराम द्वारा सतर्क गोली चलाने के कारण पुलिस वाले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे. किसी की भी राइफल उसे दिखाई दे जाती थी, तो वह तुरंत फायर कर देता था. वैसे पुलिस को पता था कि छविराम कहां है, क्योंकि एसएलआर व एलएमजी के फायरों के कारण उसकी स्थिति का अनुमान कर पाना कठिन नहीं था. ऐसी ही छिटपुट गोलाबारी में एक घंटा गुज़र गया. न पुलिस वाले बढ़ पा रहे थे, न छविराम निकल पा रहा था. पांच बजे के आसपास सिपाही किशनचंद पांडे ने छविराम की जगह समझने के लिए जैसे ही सिर उठाया, एक गोली उसकी भौंह को फोड़ती हुई सिर के पीछे से निकल गई. किशनचंद को गोली लगने से जहां सिपाहियों में बेहद गुस्सा आ गया, वहीं अधिकारियों ने या तो भय से या सावधानी के कारण और सुरक्षित पोजीशन ले ली. बर्नाहर के थानाध्यक्ष एपी सिंह ने हिम्मत की तथा वह कूदकर नवाटेढ़ा की तरफ़ वाले नदी के किनारे की ओर बढ़े कि एसपी कर्मवीर सिंह के कोतवाल युद्धपाल सिंह ने डांटकर वापस बुलाया, लेकिन इसे अनसुनी कर वह डाकुओं के पचास गज नज़दीक चले गए.

यह वह क्षण था, जब छविराम ने अपनी ज़िंदगी की सबसे भयानक फायरिंग की, लेकिन पुलिस का मोर्चा तोड़ने की उसकी यह आख़िरी कोशिश भी बेकार चली गई. किशनचंद की मौत से गुस्से में पागल सिपाहियों ने भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे क्रॉस फायरिंग में सिपाहियों को भी जान का ख़तरा पैदा हो गया. पीएसी के दो सिपाही घायल भी हो गए. फलस्वरूप पीएसी वालों ने आगे बढ़कर गिरोह पर फायरिंग की, तो पहले तीन चीखें आईं तथा फिर एलएमजी व एसएलआर खामोश हो गईं. छविराम मारा जा चुका था. छविराम के मरते ही उसके पास के तीन डाकू नदी के किनारे-किनारे भागे, जिन्हें घिरोर के थानाध्यक्ष की पार्टी ने गिरा दिया. पांच डाकू खेत की ओर भागे. उन पर सबने सामूहिक फायरिंग की, वे वहीं लुढ़क गए. मरने से पहले छविराम चीख रहा था कि अंधेरा होने दो, पुलिस वालों की लाश पर से जाऊंगा. कहना न होगा कि पुलिस वाले भी अंधेरा होने के कारण घबरा रहे थे. पीएसी के एक जवान ने मुझे बताया कि आख़िर में छविराम ने यही कहा था कि वह समर्पण करेगा. लेकिन, तब तक किशनचंद की मौत हो चुकी थी, इसलिए सारे सिपाही चिल्लाए कि उन्हें ज़िंदा छविराम नहीं, खून का बदला चाहिए. इसी कारण अफसरों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे छविराम को ज़िंदा गिरफ्तार करते. बहरहाल, इस मुठभेड़ में छविराम और उसके साथ के ग्यारह डाकू मारे गए. इसके बाद पुलिस की एक टुकड़ी हरैना गई तथा वहां उसने खेत में घायल पड़े बारहवें डाकू को गोली मार दी. इस गोलाबारी में हरैना का एक दस वर्षीय लड़का भी घायल हुआ.

लाशों की तलाशी लेने पर पुलिस को छविराम के पास के झोले में आईपीएस की वर्दी, इंजेक्शन, पट्टियां तथा एक हिंदी साप्ताहिक की एक प्रति मिली. हथियार ये बरामद हुए-एक एलएमजी, एक एसएलआर, दो थ्री नॉट थ्री, चार थर्टी स्प्रिंगफील्ड राइफलें, जिसमें एक चेकोस्लोवाकिया की बनी है, चार एसबीबीएल गन तथा एक शॉट गन. नहीं मिले तो दो लाख रुपये, अंगूठियां, घड़ी तथा सोना, जो वह हमेशा अपने साथ रखता था. यह सब माल कहां गया? इसके बारे में दो मत हैं. पहला यह कि छविराम ने यह सब रास्ते में किसी गांव में ही छोड़ दिया था, ताकि बाद में वापस ले सके तथा दूसरा यह कि इसे पुलिस ने रख लिया. *क्रमशः*

feedback@chauthiduniya.com

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिताः नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

छविराम के पास एटा के नथुआपुर में शहीद इंस्पेक्टर राजपाल सिंह से लूटी गई लाइट मशीनगन तथा एसएलआर सहित स्प्रिंगफील्ड राइफलें थीं, लेकिन यही विशिष्ट हथियार उसकी मौत के दूत बन गए. एलएमजी व एसएलआर के फायरों से पुलिस को लगातार पता चलता रहा कि छविराम कहां है. अतः पुलिस वालों ने मथुरा सिंह व कैलाश की टुकड़ी से अपने को उलझने से बचाया. लेकिन, जब तक वे मथुरा सिंह व कैलाश यादव को पीछे ढकेल कर छविराम से मोर्चा लेते, तब तक वह हरैना की तरफ़ बढ़ चुका था.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

सत्ता पक्ष और विपक्ष में दूरी चिंतनीय

प्रोफेसर मुखर्जी का यह उत्तर राजनीतिज्ञों के लिए आंखें खोलने वाला है. लोकतंत्र का दिशा निर्देशक तत्व विपक्ष है. अगर विपक्ष अपनी बात राजनीति को परे रखकर जनता के हित के लिए उठाता है, तो उसे सत्तारूढ़ दल को सुनना चाहिए और विपक्ष को भी अपने विपक्ष होने की क़ानूनी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ़ सरकार अगर विपक्ष से राय-मशविरा नहीं करती है और विपक्ष से बात नहीं करती है, तो लोकतंत्र से दूर जाती हुई दिखाई देती है. भारत जैसे देश, जहां लोकतांत्रिक परंपराएं कूट-कूटकर भरी हैं और जहां पिछले पैंसठ सालों से लोकतंत्र निर्बाध गति से चल रहा है, अगर वहां पर पक्ष या विपक्ष लोकतंत्र से दूर जाता हुआ दिखाई दे, तो इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना चाहिए.

भारत की राजनीति में एक बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति पिछले 10-12 सालों में बढ़ी है और वह प्रवृत्ति सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में देखी जा रही है. पिछली सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया और अब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं. वह प्रवृत्ति है, विपक्ष के साथ संवाद न करना, किसी भी विषय के ऊपर विपक्ष से राय न लेना. यह मानना कि चूंकि उनके पास बहुमत है, इसलिए वह जो फ़ैसला करेंगे, उसे सबको मानना ही चाहिए. एक औपचारिकता संसद के सत्र से पहले निभाई जाती है, जिसमें संसदीय कार्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं या फिर लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष सदन कैसे सुचारू रूप से चले, इसके बारे में बात करते हैं. बस इतना ही. और, इसका नतीजा यह निकल रहा है कि मनमोहन सिंह के समय महीनों सदन में न काम हुआ, न काज हुआ, न सवाल पूछे गए और जनता का पैसा बर्बाद हुआ. ठीक वही चीज अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय देखी जा रही है. मजे की बात यह कि दलों के प्रवक्ता, खासकर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ताओं से जब यह जानने की कोशिश की जाती है कि क्या सदन को चलाने का मुख्य रोल सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं है, तो उनका एक ही रटा-रटाया जवाब होता है कि सरकार सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुला तो लेती है और फिर सदन में जब सरकार कहती है कि हम बात करना, बहस करना चाहते हैं, तो विपक्ष तैयार क्यों नहीं होता.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में या कहें कि दस साल के कार्यकाल में शायद पांच बार भी सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और उनके साथ देश की किसी समस्या के ऊपर राय-मशविरा नहीं किया. सोनिया गांधी तो यूपीए की अध्यक्ष थीं, लेकिन वह जब अपनी ही पार्टी के लिए सुलभ नहीं थीं, तो विपक्ष के लिए कहां से सुलभ होतीं. अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को निरर्थक मान बैठे हैं और इस निरर्थक विपक्ष से क्यों बात करना, यह शायद उनकी सोच का मुख्य केंद्र बिंदु है.

मैं मौजूदा राजनीतिक दलों के नेताओं को, जिनमें सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल हैं, यह बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू थे और उनके पास विशाल बहुमत था, तब उन्हीं दिनों किसी ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता प्रोफेसर हीरेंद्र नाथ मुखर्जी से पूछा कि संसद में विपक्ष के कौन नेता हैं और उनका रोल क्या है? प्रोफेसर हीरेंद्र नाथ मुखर्जी ने जवाब दिया कि इस समय सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री यानी पंडित जवाहर लाल नेहरू ही विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं. इस पर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ. प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू यह जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का क्या महत्व है और चूंकि दोनों सदनों में विपक्षी दलों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वह स्वयं विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सवालों को उठाते हैं, उनका जवाब देते हैं, उनका हल भी निकालते हैं और इस क्रम में पंडित जवाहर लाल नेहरू को यह पता चल जाता है कि कहां पर चूक हो रही है तथा वह उसे ठीक करने की कोशिश भी करते हैं.

प्रोफेसर मुखर्जी का यह उत्तर राजनीतिज्ञों के लिए आंखें खोलने वाला है. लोकतंत्र का दिशा निर्देशक तत्व विपक्ष है. अगर विपक्ष अपनी बात राजनीति को परे रखकर जनता के हित के लिए उठाता है, तो उसे सत्तारूढ़ दल को सुनना चाहिए और विपक्ष को भी अपने विपक्ष होने की क़ानूनी स्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ़ सरकार अगर विपक्ष से राय-मशविरा नहीं करती है और विपक्ष से बात नहीं करती है, तो लोकतंत्र से दूर जाती हुई दिखाई देती है. भारत जैसे देश, जहां लोकतांत्रिक परंपराएं कूट-कूटकर भरी हैं और जहां पिछले पैंसठ सालों से लोकतंत्र निर्बाध गति से चल रहा है, अगर वहां पर पक्ष या विपक्ष लोकतंत्र से दूर जाता हुआ दिखाई दे, तो इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानना चाहिए.

इसके साथ ही राजनीति में एक और नई ख़तरनाक चीज दिखाई दे रही है कि मंत्री स्वयं को अपने दल का मंत्री मान बैठे हैं. मैं केंद्रीय सरकार की बात कर रहा हूं. जो संसद के सदस्य हैं या वरिष्ठ राजनेता हैं, संसद के सदस्य भले ही न हों, अगर उन्हें किसी बारे में बात करनी हो, तो किससे बात करेंगे? वे बात सरकार के मंत्री से ही करेंगे, क्योंकि सरकार का मंत्री देश का मंत्री होता है. सुषमा स्वराज का यह कहना कि उनके ऊपर कांग्रेस के लोगों ने दबाव डाला, मेरी समझ में नहीं आता. कांग्रेस के लोग कैसे दबाव डाल सकते हैं? क्या उन्होंने सुषमा स्वराज से यह कहा कि आप यह बात मान लीजिए, तो हम आपको सदन में वाकओवर दे देंगे कि आप जैसा चाहें, वैसा करें? ऐसा कभी होता नहीं है. सुषमा स्वराज मंत्री हैं या कोई भी मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं. इन सबके पास लोग जाएंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे. कभी उचित सिफारिश होगी, तो कभी अनुचित सिफारिश होगी. लेकिन, उन तमाम सिफारिशों को मानना या न मानना मंत्री के ऊपर निर्भर करता है. अब अगर कोई मंत्री अपनी किन्हीं चीजों को छिपाने के लिए या विषय को डायवर्ट करने के लिए यह कह दे कि उसके ऊपर दबाव डाला गया, तो उसे बताना पड़ेगा कि दबाव का मतलब क्या? अथवा यह भी सिर्फ़ एक जुमला है. जैसा कि भारतीय जनता पार्टी में इन दिनों जुमलेबाजी शुरू हो गई है और हर नेता किसी भी बात पर कह देता है कि यह तो जुमला था, राजनीतिक जुमला था. क्या वैसे ही भारत की राजनीति में नए सिरे से एक जुमलेबजी शुरू हो रही है?

ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे भैरो सिंह शेखावत, बल्कि उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी या फिर चंद्रशेखर जी. ये ऐसे लोग थे, जिनके दोस्त हर दल में थे और वे कभी औपचारिक मुलाकातें नहीं करते थे, अनौपचारिक मुलाकातें करते थे. उस अनौपचारिक मुलाकात में बहुत सारे मसले हंसी के ठहाकों के बीच हल हो जाते थे और सदन सुचारू रूप से चलता था. इसलिए जब कोई ऐसा नेता सदन में खड़ा होता था, तो सदन ध्यान से उसकी बात सुनता था. आज तो सदन में एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो खड़ा हो और पूरा सदन उसे ध्यान से सुने. आज लोकसभा और राज्यसभा में अनौपचारिक बैठकों के लिए जगह नहीं है. आज तो हालत यह हो गई है कि अगर कोई किसी के यहां शादी-ब्याह में भी चला जाए, तो सवाल खड़ा हो जाता है कि वह उसके यहां क्यों गया था. यह राजनीति की वह ख़तरनाक प्रवृत्ति है, जो लोकतंत्र के ख़िलाफ़ मानी जाती है. इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि भारत की राजनीति में फिर से उस परंपरा का सूत्रपात हो. जितने भी सफल संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं या जितने भी सफल अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा या राज्यसभा के, उनके दरवाजे अपनी पार्टी के अलावा विपक्ष के लिए हमेशा खुले रहते थे और वे बातचीत करके मसलों का हल निकाल लेते थे. राजनीति में शत्रुता, राजनीति में मित्रता और राजनीति में आत्मीयता ज़रूरी है, वरना लोकतंत्र और तानाशाही में फ़र्क़ क्या रह जाएगा? भारत की राजनीति में फिर से उन लोगों के आगे आने की ज़रूरत है, जिनकी दोस्ती हर दल में है और जो अनौपचारिक रूप से लोगों को बुलाकर दोस्ती का एक नया सिलसिला शुरू कर सकें.

ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग आज कम हो गए हैं. लोग हैं, लेकिन उनमें हिम्मत समाप्त हो गई है. अटल जी, चंद्रशेखर जी और भैरो सिंह जी जैसे लोग राजनीति में हमेशा इसीलिए याद किए जाते हैं, क्योंकि कभी वे एक दल के नहीं होते, वे हर दल के होते हैं, हर दल में उनके दोस्त होते हैं और वे कभी किसी के यहां जाने से गुरेज नहीं करते. यही तत्व भारत की राजनीति से गायब हो रहा है. यह जितनी जल्दी पुनर्स्थापित हो, लोकतंत्र के लिए शुभ होगा. ■

editor@chauthiduniya.com

क्या यूरोपीय संघ का अंत शुरू हो गया है

जर्मन राष्ट्र फ़ासिज्म के तौर पर विकृत हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध क्षतिपूर्ति वाले अध्याय का नतीजा बताया गया. यहां जर्मनी ग्रीस पर एक असहनीय बोझ थोपने के लिए आगे जा रहा था. जर्मनी एक ऐसा देश है, जिसने बहुत प्रतिरोध का सामना करते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीत के लिए कोशिश की थी. यूरोपीय संघ बनाने का मकसद यह तो नहीं था. यह एकजुटता, लोकतंत्र एवं उदार स्वतंत्रता की आशाओं पर बनाया गया था.

मेघनाद देसाई

बीस साल पहले यूरोपीय राजनीति के तीन दिग्गज-एडवर्ड हीथ, गिस्कार्ड डी इस्टेनिंग एवं हेल्मुट शिमट यूरोप के लिए एक एकल मुद्रा के मुद्दे पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में छात्रों को संबोधित करने के लिए आए थे. ये तीनों क्रमशः ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से थे. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि यदि एकल मुद्रा अपनाई जाती है, तो यह यूरोप को बेहतर ढंग से एकजुट करने में मददगार साबित होगा. बाद में दोपहर के भोजन पर मैंने हेल्मुट शिमट से पूछा कि आप कम स्थिर जर्मन डचमार्क को एक एकल मुद्रा में मर्ज (शामिल) करने की बात क्यों कर रहे हैं? उनका जवाब चौंकाने वाला था. उन्होंने मुझसे कहा कि डचमार्क जैसा शक्तिशाली था, वैसा ही रहता, तो जर्मनी एक बार फिर यूरोप में नापसंद किया जाने वाला देश होता. जर्मनी के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वह एक यूरोपीय मुद्रा के तहत अपने डचमार्क को दफना दे.

पिछले सप्ताह ग्रीक को बेल आउट के लिए वार्ता समाप्त हुई. कोई भी यह कह सकता है कि हेल्मुट शिमट ने जो जुआ खेला था, उसमें वह असफल रहे. एंजेला मार्केल को एक बार फिर यूरोप भर में बहुत क्रोध का सामना करना पड़ा. लोग मान रहे थे कि यह एक बहुत ही क्रूर और बेरहम बातचीत थी. लोग ग्रीस की अधीनता की बात करने लगे. दरअसल, यह शर्त कि ग्रीस यूरोपीय नियंत्रण के तहत 50 बिलियन की अपनी सार्वजनिक परिसंपत्तियों को रखे, बताती है कि ग्रीक संप्रभुता की सीमाएं क्या हैं. विडंबना यह है कि लोग याद कर रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय संधि में युद्ध शुरू करने के अपराध के लिए जर्मनी पर क्षतिपूर्ति का एक असहनीय बोझ डाला गया था. यह किस तरह का बोझ था, इसे दुनिया जानती है.

जर्मन राष्ट्र फ़ासिज्म के तौर पर विकृत हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध क्षतिपूर्ति वाले अध्याय का नतीजा बताया गया. यहां जर्मनी ग्रीस पर एक असहनीय बोझ थोपने के लिए आगे जा रहा था. जर्मनी एक ऐसा देश है, जिसने बहुत प्रतिरोध का सामना करते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीत के लिए कोशिश की थी.

यूरोपीय संघ बनाने का मकसद यह तो नहीं था. यह एकजुटता, लोकतंत्र एवं उदार स्वतंत्रता की आशाओं पर बनाया गया था. एकल मुद्रा शुरू करने का उद्देश्य सबको एक संघ में एक साथ लाना था. एकल मुद्रा से एक संघीय यूरोप आना था और यह समृद्ध एवं एकीकृत होता. यूरोप अपने हिंसक अतीत को भूलता और उसे शांति का स्वर्ग बनना था. यूरो का प्रयोग दुनिया में एक सफलता की कहानी थी, तब जबकि दुनिया कर्ज के बोझ से दबी थी, लेकिन 2008 के बाद से धन सूखता गया. यूरो जोन सोने के मानक पर मॉडल किया गया था और देश का अपने पैसों की आपूर्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है. वे अपने बजट घाटे को नहीं चला सकते हैं.

विनिमय दर एक है, इसलिए कोई भी देश अन्य देशों के ख़िलाफ़ अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं कर सकता. यदि कर्ज चुकाया जाना है, तो एक ही जवाब है कि जीवन स्तर को यथावत बनाए रखें, मज़दूरी में कटौती करें और उत्पादकता बढ़ाएं. जैसा कि कई लोगों ने आगाह किया था. वह प्रयोग समस्याओं से भरा था. एक मौद्रिक संघ राजकोषीय संघ के बगैर आय का हस्तांतरण मजबूत से कमज़ोर की ओर करने की अनुमति नहीं देता है. कल्पना कीजिए कि वित्त आयोग के बिना भारत कैसे केंद्र की तरफ़ से राज्यों के लिए राजस्व का हस्तांतरण करने के लिए फॉर्मूला बनाएगा? समृद्ध हरियाणा के मुक़ाबले बिहार को कितना राजस्व मिले, यह कैसे तय होगा? अब जर्मनी और ग्रीस के बारे में सोचिए. उत्तरी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है और उन्हें राजकोषीय अनुशासन के लिए जाना जाता है. उन्होंने यूरो से अच्छा प्रदर्शन किया है. दक्षिणी यूरोपीय देश निर्यात को बढ़ावा देने की खातिर मुद्रा का मूल्य कम करने की अपनी स्वतंत्रता पसंद करते हैं. पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस एवं स्पेन को इससे नुक़सान उठाना पड़ा है. उधार आसान था, इसलिए मिल गया, लेकिन वापस भुगतान नहीं हो सका. कर्ज बड़ा हो गया. ग्रीस को सबसे अधिक मुसीबत का सामना करना पड़ा है. यहां भारत की तरह ज़्यादातर लेन-देन नगद होता है और कर संग्रह अथॉरिटी बहुत ही ढीली है. बहुत से लोग सरकार में काम करते हैं और जल्दी सेवानिवृत्त हो जाते हैं. यदि ग्रीस अभी अपने मौजूदा सकल घरेलू उत्पाद का 200 प्रतिशत हो चुका कर्ज चुकाता है, तो वह 40 वर्षों के लिए अप-स्फीति के हालात में जा सकता है. ग्रीस इस सबसे बाहर निकल सकता है. वह अपना कर्ज चुकाए, अवमूल्यन कर सकता है. वह उधार लेने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन खुद से मुद्रण के ज़रिये पैसे प्राप्त कर सकता है. वह यूरोपीय संघ से भी बाहर निकल सकता है. यह इस संघ के अंत की शुरुआत होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिर्गी रोग दो प्रकार का हो सकता है आंशिक तथा पूर्ण. आंशिक मिर्गी में मस्तिष्क का एक भाग अधिक प्रभावित होता है. पूर्ण मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार विश्व मस्तिष्क दिवस को मिर्गी रोग पर समर्पित किया है. भारत में करीब 1.20 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं. मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को घर के लोग ही अलग–थलग करने लगते हैं. पढ़े–लिखे लोगों में भी इस बीमारी के प्रति अज्ञानता है. यही वजह है कि यह बीमारी आम बीमारी की तुलना में ज्यादा खराब मानी जाती है.

अंधविश्वास नहीं इलाज से दूर होगी मिर्गी

मस्तिष्क के किस भाग में असामान्य रूप से विद्युतीय तरंग का संचार होने की वजह से दौरा पड़ा और मस्तिष्क का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ और कितने समय के लिए, यह सारे कारक दौरे के प्रकार और एक व्यक्ति पर इसके प्रभाव का निर्धारण करते हैं. इसलिये ही मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे नहीं होते. अलग–अलग रोगियों में इसके लक्षण भी भिन्न होते हैं. जब मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युतीय तंरगों का संचार होने लगता है तो व्यक्ति को विशेष प्रकार के झटके लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है.

मोनिशा भटनागर

मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसॉर्डर है, जो एक जीर्ण विकार है. जिसमें रोगी को बार–बार दौरे पड़ते हैं. मिर्गी की मुख्य पहचान बार–बार अकारण दौरे पड़ना है. इन दौरों की विशेष बात यह होती है कि रोगी को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है. मिर्गी मस्तिष्क संबंधी चौथा सबसे आम विकार है और सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है. यह विकार अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा कर सकता है. मिर्गी से पीड़ित कई लोगों को एक से अधिक प्रकार के दौरे पड़ते हैं और साथ ही मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं. मानव मस्तिष्क का विकार ही मिर्गी का स्रोत है. एक दौरे के लक्षण शरीर के किसी भी हिस्से को जैसे चेहरे, हाथ या पैर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसके लक्षण पैदा मस्तिष्क में ही होते हैं. मस्तिष्क के किस भाग में असामान्य रूप से विद्युतीय तरंग का संचार होने की वजह से दौरा पड़ा और मस्तिष्क का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ और कितने समय के लिए, यह सारे कारक दौरे के प्रकार और एक व्यक्ति पर इसके प्रभाव का निर्धारण करते हैं. इसलिये ही मिर्गी के सभी मरीज एक जैसे नहीं होते. अलग–अलग रोगियों में इसके लक्षण भी भिन्न होते हैं. जब मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युतीय तंरगों का संचार होने लगता है तो व्यक्ति को विशेष प्रकार के झटके लगते हैं और वह बेहोश हो जाता है. इस प्रकार के मिर्गी के दौरे में बेहोशी की अवधि चंद सेकंड से लेकर पांच मिनट तक की हो सकती है. मिर्गी का दौरा समाप्त होते ही व्यक्ति सामान्य हो जाता है.

मिर्गी के दौरे मस्तिष्क की चोट या परिवार की प्रवृत्ति से संबंधित हो सकतें हैं, लेकिन अक्सर इसका कारण पूरी तरह से पता नहीं होता है. अनेक बीमारियों में मिर्गी जैसे दौरे आ सकते हैं. जन्म के समय बच्चे के दिमाग में ऑक्सीजन की कमी होने, मस्तिष्क में चोट लगने, ब्रेन ट्यूमर, मेनिनजाइटिस और जापानी बुखार यानि इंसेफेलाइटिस होने के बाद भी मिर्गी का खतरा रहता है. दो से तीन फीसदी मरीजों में आनुवांशिक कारण भी देखा गया है. मिर्गी रोग दो प्रकार का हो सकता है आंशिक तथा पूर्ण. आंशिक मिर्गी में मस्तिष्क का एक भाग अधिक प्रभावित होता है. पूर्ण मिर्गी में मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बार विश्व मस्तिष्क दिवस को मिर्गी रोग पर समर्पित किया है. भारत में करीब 1.20 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं. मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को घर के लोग ही अलग–थलग करने लगते हैं. पढ़े–लिखे लोगों में भी इस बीमारी के प्रति अज्ञानता है. यही वजह है कि यह बीमारी आम बीमारी की तुलना में ज्यादा खराब मानी जाती है. मिर्गी के बारे में ज्यादा जानकारी न होने के कारण इस बीमारी को लेकर कई तरह के मिथक हैं. जैसे मिर्गी के समय मरीज के हाथों में लोहे की कोई चीज या चाबियों का गुच्छा पकड़ा देने से मिर्गी का दौरा तत्काल बंद हो जाना अंधविश्वास है. ऐसे ही दिमाग पर जोर पड़ने से या मानसिक तनाव से मिर्गी नहीं होती. मिर्गी के झटकों के दौरान व्यक्ति को जोरों से पकड़ कर रखना भी ठीक नहीं होता. इसी तरह बेहोशी की अवस्था में मुंह में पानी या अन्य कोई तरल पदार्थ डालना भी खतरनाक हो सकता है.

मिर्गी रोग साध्य है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इसका उपचार पूरी तरह और सही ढंग से कराया जाए. मिर्गी रोग को ठीक करने के लिये डॉक्टर से परामर्श बहुत जरूरी है, इसके साथ ही दवाओं का नियमित सेवन उससे भी ज्यादा जरूरी है. यदि मरीज लगातार दवा खाए तो बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है. बीमारी से पीड़ित लोग भी दूसरे लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं और अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं. लेकिन मिर्गी के रोगी को कार, स्कूटर आदि वाहन नहीं चलाने चाहिए और साथ ही खतरनाक मशीनों का संचालन से भी नहीं करना चाहिए. मिर्गी जैसी बीमारी के इलाज में धैर्य रखना आवश्यक होता है क्योंकि इसका इलाज़ काफी लम्बे समय तक चलता है.■

feedback@chauthiduniya.com

जासूसी कर मुक्त कराए सैकड़ों अश्वेत

अरुण तिवारी

मैरी एलिजाबेथ बोउजर का जन्म सन 1839 में अमेरिका में हुआ था. उन्हें अमेरिकी सिविल वार के दौरान यूनियन की तरफ से जासूसी करने के लिए याद किया जाता है. इसके अलावा उन्होंने अश्वेतों की अवस्था को लेकर भी उस दौरान बहुत काम किया था. बहुत सारे बंधुआ अश्वेतों को को उन्होंने मुक्त कराया था. अमेरिकी अश्वेत आंदोलन में उनका नाम प्रमुख हस्तियों में शुमार किया जाता है. मैरी ने अश्वेतों के हित में जो काम किया वह कई मायने में विशिष्ट किस्म का था. याद रखने वाली बात है कि अमेरिकी सिविल वार जिन कारणों से हुआ उन्हें अश्वेतों पर हो रहे जुल्म सबसे प्रमुख थे. इस दौरान जिन राज्यों ने विद्रोह किया ऐसा माना जाता है कि वे अश्वेतों की ही लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन ऐसे समय में मैरी ने अमेरिकी संघ का साथ दिया न कि उन राज्यों का जो अश्वेतों की लड़ाई लड़ रहे थे. मैरी ने संघ के लिए काम कर संघ के नेताओं और अधिकारियों का दिल जीत लिया. इसके बाद उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए हजारों बंधुआ अश्वेतों को तत्काल प्रभाव से मुक्त करवाया. बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मैरी के इन कामों की आलोचना करते हैं. उनकी आलोचना का आधार यह है कि अगर मैरी वाकई में अश्वेतों की मदद ही करना चाहती थीं तो उन्हें विद्रोही राज्यों का साथ देना चाहिए था लेकिन मैरी ने ऐसा नहीं किया. इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए मैरी ने कहा था कि निश्चित रूप से मुझे उनका साथ देना चाहिए था लेकिन मुझे यह बात मालूम थी कि संघ शासित देश विद्रोही राज्यों के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन की तरह है. और यह बात मुझे स्पष्ट तौर पर दिख रही थी कि आने वाले दिनों में इन राज्यों में अश्वेतों के हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले है. इस वजह से खुद एक अश्वेत महिला होने के नाते मैंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और संघ की मदद की जिससे मैं बंधुआ अश्वेत मजदूरों की सीधे तौर पर मदद कर पाउं. और मैंने किया भी वही. मैं अपने काम के बारे में जानती थी और यह भी जानती थी कि संघ के लिए जासूसी कर मैं भले ही विद्रोही राज्यों को हराने के लिए काम कर रही हूं लेकिन इसके प्रतिफल के तौर पर न जाने के कितने बंधुआ मजदूरों को मैं उनकी गुलामी से मुक्त कराकर एक बेहतर जीवन जीने के लिए दूंगी.

मैरी का जन्म वर्जिनिया में हुआ था. उनके पिता समृद्ध व्यवसायी जॉन वैन लिउ के घर बंधुआ मजदूर के तौर पर काम किया करते थे. जब साल 1843 में जॉन की मौत हो गई तो उनके परिवार वालों ने सारे बंधुआ मजदूरों को आजाद कर दिया. उन्होंने सिर्फ मजदूरों को ही नहीं आजाद किया बल्कि मजदूरों के परिवार से संबंधित लोगों को भी आजाद कराया. लेकिन आजाद होने के बाद भी मैरी एक स्वतंत्र नौकर के रूप में उनके घर काम करती रहीं. जॉन के बाद परिवार की जिम्मेदारी एलिजाबेथ वैन लिउ ने संभाल ली. उन्होंने मैरी के भीतर मौजूद काबिलियत को पहचाना. उन्होंने महसूस किया कि एक साधारण नौकर होने के बावजूद भी मैरी में जासूसी की विलक्षण प्रतिभा मौजूद थी. एलिजाबेथ ने उन्हें पढ़ाई करने के लिए फिलाडेल्फिया भेज दिया. मैरी ने अपनी शिक्षा पूरी की. और वापस एक बार फिर एलिजाबेथ वेन लिउ के पास वापस लौट गईं. इस दौरान उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा पूरी कर ली थी. उनके वापस लौटकर वापस आने की प्रमुख वजहों में से एक वजह विवाह भी था. वापस लौटकर मैरी ने विल्सन बोजर से विवाह किया. विल्सन भी एक अश्वेत पुरुष थे. विवाह सिविल वार शुरू होने के ठीक चार दिन पहले शुरू हुआ था. हालांकि यह विवाह दो अश्वेत लोगों का था लेकिन इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर मेहमान श्वेत ही थे. इसका कारण यह था कि मैरी एलीजाबेथ वेन लिउ के घर में रहती थीं और उनके साथ रहने के कारण उनके भी ज्यादातर जानने वाले श्वेत ही थे. सिर्फ इतना ही नहीं मैरी का झुकाव भी एलीजाबेथ के साथ रहने के कारण अमेरिकी संघ की तरफ ही था.

एलीजाबेथ वर्जिनिया में रहती थीं जो विद्रोही राज्य के इलाकों में आता था. एलीजाबेथ के संबंध अमेरिकी यूनियन में थे इस वजह से उन्होंने विद्रोही राज्यों में यूनियन का जासूसी नेटवर्क तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की. वे अक्सर उन जेलों में खाने की वस्तुएं लेकर जाया करती थीं जहां यूनियन के सिपाही कैदी के तौर पर बंदी बनाए गए थे. उन्होंने मैरी बाउजर को भी इन इलाकों में जासूस बनाकर तैनात कर दिया. मैरी पर अश्वेत होने के कारण जल्दी कोई शक भी नहीं करता था. बाउजर की तीक्ष्ण याददाश्त की वजह से वेन लिउ ने यह फैसला किया. मैरी ने एक ऐसे नौकर का रूप धारण कर लिया जो बोलने में असक्षम थी. एलीजाबेथ ने अपने संबंधों का इस्तेमाल कर मैरी को विद्रोही राज्यों के राष्ट्रपति जेफरसन डेविड के महल में नौकर बनवा दिया. उस समय ऐसा माना जाता था कि नौकर पढ़ लिख नहीं पाते और राजनीतिक चर्चाओं की कठिन भाषाओं को समझ नहीं पाते थे. इस वजह से विद्रोही नेताओं की राष्ट्रपति के घर होने वाली बैठकों की ज्यादातर जिम्मेदारी मैरी के कंधों पर ही होती थी. सारे नेता यही समझते थे कि मैरी एक अनपढ़ महिला है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई. मैरी सारी बातें सुनती थीं और समझती भी थीं. इसके अलावा कार्यालय की सफाई करते हुए दस्तवेजों को पढ़कर उनकी जानकारी भी आसानी से हासिल कर लिया करती थीं. मैरी के रूप में संघ को ऐसा बेहतरीन जासूस मिल गया था जो विद्रोही राज्यों की किसी भी साजिश को आसानी के साथ धूमिल कर सकता था.

उसी समय एक और जासूस था जो संघ के लिए काम कर रहा था. उसका नाम था थॉमस मैकनिवेन. मैकनिवेन की अपनी बेकरी थी और वह अपनी बेकरी में बनी खाने की वस्तुएं राष्ट्रपति आवास में पहुंचाने के लिए जाता था. वह भी संघ का जासूस था. मैरी सारी जानकारी उसे बता दिया करती थीं. उसने अपनी किताब में मैरी के बारे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि वह सही दिशा में काम कर रही थीं व उनके पास एक फोटोग्राफिक याददाश्त थी जिसकी वजह से उन्हें सारी बातें याद रहा करती थीं. वे राष्ट्रपति आवास में जो कुछ भी घटते हुए देखती थीं वह सारी बातें वह मुझे हुबहू बता दिया करती थीं. शायद ही कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उनके छूटती थी.

हालांकि विद्रोही राज्यों के राष्ट्रपति डेविस को यह बात जल्द ही महसूस हो गई कि कोई उनके घर में रह कर ही खुफिया सूचनाएं लीक कर रहा है. शुरुआत में उन्हें मैरी पर कोई संदेह नहीं हुआ लेकिन जब मैकनिवेन की गिरफ्तारी जासूसी में हो गई तो सीधा शक मैरी पर गया. इस बात की जानकारी मिलते ही कि उन्हें पकड़ा जा सकता है, मैरी वहां से भाग निकलीं. ऐसा बताया जाता है कि मैरी ने आखिरी प्रयास विद्रोही राज्यों के व्हाइट हाउस को जलाने का किया था. उन्होंने यह कोशिश की थी पूरे राष्ट्रपति भवन को ही जलाकर खाक कर दिया जाए.

मैरी के वहां से भागने के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी यूनियन की सिविल वार में जीत घोषित हो गई. अब समय आ गया था जब मैरी अपने जासूसी के समय के बारे में जर्नल लिखना चाह रही थीं. उन्होंने इसके बारे में विस्तार से लिखा. लेकिन कुछ समय बाद ये सारे दस्तावेज मिटा दिए गए क्योंकि रिचमंड में यूनियन के समर्थकों के प्रति बहुत ही खराब माहौल था. इसके बाद यूनियन सरकार ने मैरी की जासूसी से संबंधित सारे दस्तावेज भी मिटवा दिए क्योंकि मैरी अपना आगे का जीवन आसानी के साथ जी सकें. यहां तक की उनकी मौत कब हुई, इसके बारे में भी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है.

सिविल वार के बाद मैरी ने अश्वेत लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया और यूनियन जेलों में बंद बहुत से अश्वेतों को बाहर निकलवाने में मदद की.■

feedback@chauthiduniya.com

आईएसआईएस

भारत को सतर्क रहने की जरूरत है

आईएसआईएस (आईएस) पूरी दुनिया के लिए चुनौती बन चुका है. इस संगठन के दहशत का आलम देखिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इसे अल कायदा से भी बड़ी चुनौती मानने लगा है. भारत के लिए चिंता इस बात की है कि कश्मीर के कुछ हिस्सों में समय-समय पर आईएस के झंडे लहराये जा रहे हैं. दूसरी तरफ भारतीय युवाओं में भी आईएस के प्रति हाल के दिनों में आकर्षण देखने को मिला है. भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी ने भी पहली बार देशभर में आईएस के हमले का अलर्ट जारी किया है. एजेंसी ने भारत के कुछ शहरों में आईएस के हमदर्दों के होने की भी बात कही है. इस्लामिक स्टेट समर्थक के सोशल मीडिया अकाउंट पर जो फोटोज पोस्ट की गई हैं, उसमें भारतीय लड़ाकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है. ये वो वाकये हैं, भारत के प्रति आईएस के खतरे को आगाह कर रहे हैं. जरूरी है कि समय रहते भारत अपने देश में पनप रही ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए. देश में आईएस के प्रति युवाओं में हमदर्दी के कारणों की पड़ताल करे, अन्यथा किसी आफत का सामना करना पड़ सकता है.

राजीव रंजन

कुछ ही दिनों बाद भारत 15 अगस्त को आजादी की 69वीं वर्षगांठ मना रहा होगा. हर बार की तरह आतंकवादियों का मुख्य निशाना लाल किला होगा. इंटेलीजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा अलर्ट जारी भी कर दिया है. अलर्ट के मुताबिक 5 आतंकी 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री को निशाना बना सकते हैं. फोन कॉल इंटरसेप्ट होने से सुरक्षा एजेंसियों को इस संभावित हमले की जानकारी मिली है. बताया जा रहा है कि आतंकी मुंबई हमले के दोषी याकूब मेमन को फांसी की सजा से बौखलाए हुए हैं और प्रधानमंत्री और लाल किले पर हमला करके बदला लेना चाहते हैं.

याकूब मेनन तो एक बहाना है, बल्कि वास्तविकता यह है कि हर बार लाल किला आतंकवादियों के निशाने पर होता है. हर बार इसे लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट भी जारी करती हैं. सेना, पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से आतंकवादियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली काली करतूतों को असफल भी किया जाता है, लेकिन खतरा टलता नहीं, वह बदले हुए रूप में हमेशा सामने होता है. कभी पाक प्रायोजित आतंकवाद के रूप में, कभी अलकायदा की धमकियों के रूप में तो कभी दहशतगर्दी का नया रूप आईएसआईएस के रूप में. आज हम बात कर रहे हैं इसी आईएसआईएस के बारे में, जिसकी जद में भारत के युवा बहुत तेजी से आ रहे हैं, जो भारत में आईएसआईएस के प्रति आकर्षण या बढ़ते प्रभाव या दुनिया के अन्य देशों में दहशत मचाते आईएसआईएस में भारतीयों के शामिल होने के रूप में सामने आ रहा है.

आईबी के इस अलर्ट के मायने भी हैं. कश्मीर में जिस तरह से समय-समय पर कुछ अलगाववादी तत्व पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस के झंडे लहराते रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आईएसआईएस के हमदर्द भारत में भी पनप रहे हैं या हम कह सकते हैं कि आईएसआईएस के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है. पिछले दिनों श्रीनगर के अधिकारियों ने बताया कि शहर के नोहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद में नमाज के बाद युवाओं के एक समूह ने विवादित झंडा लहराया और अलगाववादी समर्थक और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए.

दुनिया में दहशत मचाने वाला आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक और सीरिया के कई भागों पर कब्जा कर चुका है और उसकी फितरत अभी और कई देशों पर कब्जा या कह सकते हैं कि दहशत मचाने की है. दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका भी आईएस की हिंसात्मक गतिविधियों से दहशत में है. यही कारण है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) के प्रमुख ने आगाह किया है कि इस्लामिक स्टेट उनके देश के लिए अलकायदा से बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इस आतंकी समूह ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में अमेरिकियों पर असर डाला है और उन्हें पश्चिम एशिया में बुलाने की बजाय अमेरिका में हमले का निर्देश दिया है. आईएसआईएस अथवा आईएस अलकायदा से अलग हो चुका एक समूह है और इसने इराक एवं सीरिया में सैकड़ो किलोमीटर के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है. अमेरिका से इतर, अगर भारत की बात करें तो आईएसआईएस का मन इतना बढ़ गया है कि वह अब भारत में हमला करने के फिराक में है. यह हम नहीं कह रहे, बल्कि पिछले महीने भारतीय खुफिया एजेंसी आईबी द्वारा पहली बार देशभर में आईएसआईएस (इस्लामिक स्टेट) के हमले का अलर्ट जारी करने से पता चलता है. खुफिया एजेंसी ने देशभर में आईएसआईएस से सहानुभूति रखने वाले 35 से ज्यादा कट्टर जिहादियों की पहचान भी की है. ये लोग मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में सक्रिय हैं. खुफिया एजेंसी ने देश में आईएसआईएस से सहानुभूति रखने वाले लोगों की लिस्ट बनाकर रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है. ऐसे लोगों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग मेट्रो सिटीज में आईएसआईएस के लिए लड़ाके भर्ती करने की योजना बना रहे हैं. इससे पहले एजेंसी ने देश में मौजूद आतंकी संगठन से प्रभावित सक्रिय आतंकी समूहों के बारे में ही आगाह किया था. दूसरी तरफ आईबी का यह अलर्ट कई मायनों में वजन भी रखता है. आईबी ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि कल्याण (महाराष्ट्र) के चार लड़कों के अलावा, भारत से सात अन्य लोग इस्लामिक स्टेट से जुड़ने के लिए इराक और सीरिया जा चुके हैं. इनमें से पांच भारतीयों की संघर्ष के दौरान मौत हो गई है. कल्याण का रहने वाला लड़का अरीब मजीद भारत लौट चुका है और एनआईए की कस्टडी में है. वहीं, पांच अन्य भारतीय अभी आतंकी संगठन के साथ हैं.

दुनिया में दहशत मचाने वाला आतंकी संगठन आईएसआईएस इराक और सीरिया के कई भागों पर कब्जा कर चुका है और उसकी फितरत अभी और कई देशों पर कब्जा या कह सकते हैं कि दहशत मचाने की है. दुनिया का ताकतवर देश अमेरिका भी आईएस की हिंसात्मक गतिविधियों से दहशत में है. यही कारण है कि अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) के प्रमुख ने आगाह किया है कि इस्लामिक स्टेट उनके देश के लिए अलकायदा से बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इस आतंकी समूह ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में अमेरिकियों पर असर डाला है और उन्हें पश्चिम एशिया में बुलाने की बजाय अमेरिका में हमले का निर्देश दिया है.

आईबी के इस अलर्ट के मायने भी हैं. कश्मीर में जिस तरह से समय-समय पर कुछ अलगाववादी तत्व पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस के झंडे लहराते रहे हैं, उसको देखते हुए इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आईएसआईएस के हमदर्द भारत में भी पनप रहे हैं या हम कह सकते हैं कि आईएसआईएस के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ा है. पिछले दिनों श्रीनगर के अधिकारियों ने बताया कि शहर के नोहट्टा इलाके में जामिया मस्जिद में नमाज के बाद युवाओं के एक समूह ने विवादित झंडा लहराया और अलगाववादी समर्थक और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ को तितर-बितर करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े. अधिकारियों ने बताया कि युवकों ने नोहट्टा चौक से खनयार चौक की ओर जाने से पहले तिरंगे में आग लगा दी. उन्होंने बताया कि हालांकि वहां पर मौजूद पुलिस और सीआरपीएफ कर्मियों की बड़ी टुकड़ी ने उन्हें रोक दिया, जिससे झड़प हो गयी. हालांकि उपद्रवियों के इन करतूतों की हर तरफ आलोचना हुई और जम्मू के नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा एक खतरनाक संकेत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. खैर, जो भी हुआ, उससे कश्मीर घाटी में अशांति पैदा हो सकती है. इसलिए शासन और प्रशासन को इस पर सतर्क रहना चाहिए.

महज एक सप्ताह हुए हैं कि पिछले दिनों राजौरी शहर में आईएस का झंडा जलाए जाने से तनाव भड़क गया. हालात को काबू में करने के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया. यहां तक कि कुछ इलाकों में पुलिसवालों पर पथराव भी किया गया. हालात इतने बिगड़ गए कि सेना को बुलाना पड़ा. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का आरोप है कि जलाए गए झंडों पर धार्मिक लाइनें लिखी थीं. यहां एक सवाल उठता है कि धार्मिकता की आड़ में भारत की सरहद में आईएस या अन्य अलगाववादी या आतंकवादी संगठनों का झंडा लहराना कहां तक उचित है. अगर इस तरह की छूट दे दी गई तो वह दिन दूर नहीं जब हर तरफ ऐसे देश विरोधी गतिविधियों को हवा मिल जाए और फिर उसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि वह सरकार और प्रशासन के वश में नहीं रहेगी और आईएस भारत में जो करना चाहता है, वह उसे अंजाम देने में पूरी तरह से सफल हो जाएगा. जरूरत है समय रहते देश को तोड़नेवाली ऐसी गतिविधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रोक लगाने की.

इस्लामिक स्टेट समर्थक के सोशल मीडिया अकाउंट पर पिछले दिनों कुछ फोटोज पोस्ट की गई हैं, जिसमें दो नावों पर कई हथियारबंद आतंकी दिख रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि बोट पर आईएसआईएस में शामिल भारतीय लड़ाके भी मौजूद हैं. ये फोटोज आईएसआईएस की मीडिया विंग अल हयात द्वारा जारी ताजा वीडियो से ली गई हैं. संगठन का दावा है कि नावों पर सवार दिख रहे आतंकी भारतीय हैं. आईएसआईएस के मुताबिक, उनमें से एक आतंकी अबु तुरब अल हिंदी है, जो इंडियन मुजाहिदीन का सरगना रह चुका है. उसकी पिछले साल सीरिया में मौत हो चुकी है. लळहरवलळ2 के ट्वीट में लिखा है, किसी ने कुछ पहचाना? अल हयात मीडिया के लेटेस्ट नाशीद वीडियो में भारतीय लड़ाकों से भरी नावें दिख रही हैं. आईएसआईएस के एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि इनमें से एक शेर पूर्व इंडियन मुजाहिदीन ग्रुप का लीडर है, जो कोबानी में शहीद हो गया था. इसका नाम है अबु तुराब अल हिंदी. दूसरे ट्वीट में लिखा है कि अल्लाह करे यह बोट तब तक न रुके, जब तक कि सभी भारतीय हमारे साथ न आ जाएं. हम आपको आमंत्रित करते हैं. आईएसआईएस समर्थित अकाउंट से वीडियो का एक स्टिल भी शेयर किया गया है, जिसमें एक कथित भारतीय मुजाहिदीन उंगली उठाए दिख रहा है. ट्वीट में लिखा है कि अबु काका अल हिंदी, भारत से एक मुजाहिदीन. माना जा रहा है कि यह ट्विटर अकाउंट थाने के फहाद शेख का है, जो पिछले साल आईएसआईएस में भर्ती हो गया था.

कुल मिलाकर देखा जाए तो आईएस की नजर भारत में अपनी जाल बिछाने की है, जहां से वह आसपास के देशों में अपनी धाक जमा सके. अगर आईएस भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या आसपास के किसी भी पड़ोसी देश में अपनी जमीन तैयार कर लेता है तो वह भारत में बहुत आसानी से दहशत फैला सकता है. यही कारण है कि वह भारतीय युवाओं को हर तरीके से लुभाने में लगा हुआ है. भारत को सतर्क रहना होगा, अन्यथा जिस तरह से पड़ोसी देश पाकिस्तान या अन्य देशों से आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से भारत को परेशान किया जाता रहा है, आतंकवाद की वह जमीन आईएस के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्राचीन काल से ही गुरुकुल इस दिन को महोत्सव के रूप में मनाते रहे हैं. गुरुकुलों में इसी पावन अवसर पर नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, सभी जिज्ञासु छात्र इस दिन अपने हाथों में समिधा लेकर गुरु के समक्ष आते थे और प्रर्थना करते थे कि–हे गुरुवर हमारे भीतर ज्ञान–ज्योति प्रज्जवलित करें, हम इसके लिए स्वयं को समिधा के रूप में अर्पित करते हैं. इसी पर्व की मंगल बेला में जो छात्र गुरु द्वारा प्रदत्त सभी शिक्षाओं को दक्षता पूर्वक ग्रहण कर लेते थे, उन्हें गुरुकुल द्वारा प्रमाण प्रत्र भी जारी किया जाता था.

करुणा का ही रूप सदगुरु हैं

चौथी दुनिया ब्यूरो

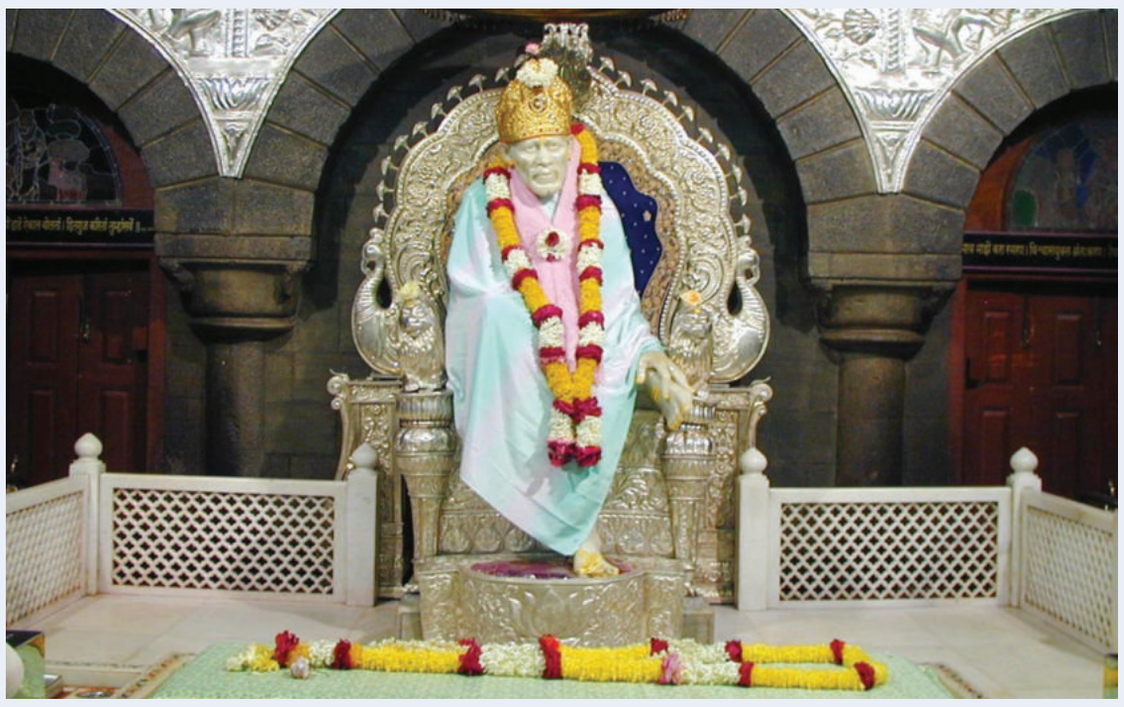

साई शब्द का अर्थ क्या है?

साई शब्द का मूल अर्थ है–स्वामी. विभिन्न भारतीय भाषाओं में साई शब्द के अलग–अलग अर्थ किए गए हैं, जैसे कि ईश्वर, मालिक, रक्षक, पति, धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला, पिता आदि.

बाबा को ईश्वर, मालिक और पिता के रूप में पूजना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम अनेक रूपों में प्रकटित है, जैसे कि अपनी संतान के प्रति पिता के प्रेम के कितने ही रूप होते हैं.

साई–मंत्र

ऊं साई श्री साई जय जय साई का क्या अर्थ है?

वस्तुत: यह बाबा का आह्वान है. ऊं ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है. जय का अर्थ है : महिमा. कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्रोच्चारण के द्वारा बाबा का महिमा मंडन किया जाता है कि श्री साई की ब्रह्मांड की आदि ध्वनि हैं. उनका आह्वान करने के लिए ही यह मंत्रोच्चारण किया जाता है.

बाबा प्रकृति हैं या पुरुष

बाबा प्रकृति या पुरुष? क्या इन दोनों का कोई पारस्परिक संबंध है ?

बाबा प्रकृति और पुरुष दोनों हैं. पुरुष ईश्वर है और प्रकृति उनकी व्यक्त शक्ति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में प्रकट है. अभिप्राय यह है कि बाबा ही सूक्ष्म रूप से व्याप्त ईश्वर हैं. वे ही ईस ब्रह्मांड के कारण हैं. अत: पुरुष हैं. और वे ही प्रकृति भी हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में उन्हीं की सत्ता है. इन दोनों का पारस्परिक संबंध इसी रूप में चरितार्थ होता है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह हैं.

बाबा जीवनमुक्त–परामुक्त

सद्गुरुओं को किस अवस्था में रखा जा सकता है?

उत्तर सद्गुरु मनुष्य हैं, जो ईश्वर के सदृश हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सभी गुणों को संपूर्णता से स्वयं में उतार लिया है. वासुदेव कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे, जिन्होंने मनुष्य की देह ग्रहण की थी. साई बाबा वास्तव में क्या हैं? अभी यह निश्चित रूप से कहने में मैं असमर्थ हूं. बाबा के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना कृत्रिम तथा भावात्मक रूप से मैं गुणारोपण करना नहीं चाहता. जब बाबा के वास्तविक स्वरूप का मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा, तो मैं अवश्य बताऊंगा पर इतना निश्चित है कि बाबा एक पूर्णत: जीवनमुक्त तथा परामुक्त अवस्था में थे.

उत्तर सद्गुरु मनुष्य हैं, जो ईश्वर के सदृश हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सभी गुणों को संपूर्णता से स्वयं में उतार लिया है. वासुदेव कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर थे, जिन्होंने मनुष्य की देह ग्रहण की थी. साई बाबा वास्तव में क्या हैं? अभी यह निश्चित रूप से कहने में मैं असमर्थ हूं. बाबा के प्रत्यक्ष अनुभव के बिना कृत्रिम तथा भावात्मक रूप से मैं गुणारोपण करना नहीं चाहता.

शिवरूपी सद्गुरु

बाबा को शिवरूप क्यों माना जाता है?

हमारी कल्पना ने शिव के जिस रूप का निर्माण कर रखा है, बाबा उस संदर्भ में शिव–रूप नहीं हैं. जब हम शिव कहते हैं, तो उसका कोई आकार नहीं है बल्कि वह एक माहन आदि शक्ति है, जो कि बहुत सुक्ष्म है. इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या अदृश्य है– चाहे वह जड़ पदार्थ हों, प्राणी हों, ग्रह नक्षत्र हों या अन्य सूक्ष्म जीव हों.

सब उसी से उत्पन्न हुए हैं. इसीलिए जो कुछ भी इनमें घटित होता है सब कुछ उन्हें छूता है. यही सब प्राणियों के दु:खों एवं पीड़ा को स्वयं अपने पर झेलकर उन्हें शांति एवं अफरिमित आनंद प्रदान करता है. यह एक शाश्वत सत्य है.

चरम करुणा का ही मूर्त रूप सद्गुरु होते हैं. प्राकृतिक नियम के भीतर रहकर भी कृपा स्वरूप उसके परे जाकर प्राणियों के दु:ख को अपने ऊपर झेलतें हैं– बदले स्वयं के बिना कुछ चाहे. दूर कहीं बच्चे को आग से बचाने के लिए बाबा का द्वारकामाई की जलती धूनी में हाथ डालकर स्वयं अपना हाथ जला लेना, श्री खापर्डे के बेटे बेटे की प्लेग की पीड़ा निर्मूल करने के लिए प्लेग की उन गिल्टियों को स्वयं अपने शरीर पर झेलना इसके कुछ प्रत्यक्ष उदाहरण हैं. इससे भी अधिक सुक्ष्म स्तर पर जो उन्होंने किया और वे जो कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को इसका अनुभव हो रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दु:ख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

अतिउत्साह सही नहीं है

कवर स्टोरी-रक्षा मंत्रालय और सेना की सबसे बड़ी चूक(20 जुलाई -26 जुलाई 2015) पढ़ा. बहुत जानकारी परक है. मनीष कुमार से मैं सहमत हूं कि अनुभवहीनता की वजह से बड़े-बड़े राजनेता कभी-कभी अति उत्साह वश कुछ ऐसा कर जाते हैं, जिसके भविष्य में विपरीत नतीजे देखने को मिलते हैं. हमारी खुफिया एजेंसिया यह पता लगाने में कई बार पर नाकाम साबित हुई हैं कि देश या सेना पर हमले होने वाले हैं. यह भी सही है कि रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो दुर्दशा हुई है, वह माफी के योग्य नहीं है. सेना पर इतना बड़ा हमला होता और इन खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता यह नाकामियों का ही नतीजा है. म्यामार सीमा के भीतर आतंकवादियों पर की गई कार्रवाई का अतिउत्साह में जितना प्रचार-प्रसार किया वह नहीं होना चाहिए था. हमारी खुफिया एजेंसियों को जिम्मेदार और सेना को मजबूत बनाने की जरूरत है.

-रविकांत तिवारी, बक्सर, बिहार.

सीबीआई के लिए चुनौती

आलेख-व्यापमं की व्यापक कहानी, महाघोटाले के आईटी दस्तावेज की जुबानी, सीबीआई की राह बहुत कठिन होगी(20 जुलाई -26 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. नवीन चौहान की एक्सक्लयूसिव स्टोरी में वो सारी जानकारी पढ़ने को मिली, जो अभी तक किसी समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं हुई थी. यह बिल्कुल सही सवाल है कि क्या इतने बड़े घोटाले के दोषियों को सीबीआई सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी, क्योंकि कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिनकी जांच सीबाआई ने की है. लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला. इस आलेख से पता चलता है कि किस प्रकार दोषियों ने सारे सबूत मिटाएं हैं और मिटाने की कोशिश की है. यह भी सही सवाल है कि आखिर इस सच को जाने बगैर सही-गलत का पता कैसे लगाया जा सकता है. लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या सीबीआई व्यापमं घोटाले के दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है?

-प्रदीप सिंह, लखनऊ, उत्तर प्रदेश.

मुलायम की कवायद

आलेख-आडवाणी से मुलायम की मुलाकात के मायने(20 जुलाई -26 जुलाई 2015)पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक है. प्रभात रंजन दीन ने बिल्कुल सही कहा है कि शिष्टाचार भेंट कोई दो-ढाई घंटे तो चलती नहीं, सो साफ़ है मुलायम सिंह और आडवाणी में राजनीति के किसी गंभीर समीकरण पर घंटों चर्चा हुई. भाजपा के खिलाफ विरोध दल एक जुट हो रहे हैं और मुलायम सिंह यादव उन विरोधी दलों का नेतृत्व कर रहे हैं. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता समय-समय पर मोदी सरकार की आलोचना करने से नहीं चुकते हैं. यह बिल्कुल सही है कि नरेंद्र मोदी के व्यवहार और उपेक्षा से क्षुब्ध वरिष्ठ भाजपाई हस्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पक्ष में लाने की कवायद मुलायम सिंह ने शुरू कर दी है. भाजपा के क्षुब्ध वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बयानों से विपक्षी दलों को मोदी सरकार पर हमला करने का मौंका मिलता है. अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को व्यापमं के बारे में खत लिखा था, जिसे लेकर मोदी सरकार और भाजपा की किरकिरी हुई और कांग्रेस के हाथ एक हथियार लग गया.

-रमाशंकर यादव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश.

केन्द्रीय मंत्री की साजिश

जब तोप मुकाबिल हो- यह वसुंधरा के ख़िलाफ़ साजिश है(20 जुलाई -26 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है कि वसंधरा राजे के ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने साजिश रची. वसुंधरा राजे ही नहीं सुषमा स्वराज के खिलाफ भी साजिश रची गई. इस साजिश के तहत ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने टीवी चैनलों के पास सारे डॉक्यूमेंट पहुंचाए, जिसे एक अंग्रेजी चैनल ने ललित मुद्दे को अपना एजेंडा बना लिया. उस चैनल के पास प्रतिदिन ललित मोदी और वसुंधरा राजे से जुड़े नए डॉक्यूमेंट पहुंच रहे थे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को इन साजिशों से भाजपा को बचाना होगा, नहीं तो इससे मोदी सरकार और भाजपा की ही छवि को खराब होगी और नेताओं को किनारे लगाने के चक्कर में अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा ही किनारे लग जाएगी.

-बबीता कुमारी, बक्सर, बिहार.

सार्क मजबूत बने

आलेख-मजबूत सार्क से होगा क्षेत्र का विकास(20 जुलाई -26 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहतरीन आलेख है. कमल मोरारका से सहमत हूं कि गतिरोध से किसी भी पक्ष को कोई फायदा नहीं होता है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नवाज शरीफ की मास्को में मुलाकात दोनों देशों के लिए अच्छी बात है. दोनों देशों के बीच जब तक तल्खी खत्म नहीं होगी, तब तक कोई रास्त नहीं निकल सकता. किसी भी मुद्दे पर अडियल रवैये से कोई हल नहीं निकलता. इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा. यह बिल्कुल सही है कि अपने पड़ोसियों को यह सन्देश देना चाहिए कि आपसी संबंध में न सिर्फ भारत का, बल्कि सबका हित छुपा हुआ है. यह बिल्कुल सही है कि मजबूत सार्क से क्षेत्र का विकास होगा.

-रुपम श्रीवास्तव, पालम, दिल्ली.

पढ़कर खुशी होती है

मैं चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें नई जानकारियां प्रदान करती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में राजनीति से लेकर फिल्म तक सभी खबरें पढ़नें में आनंद आता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित तोप मुकाबिल और कवर स्टोरी (13 जुलाई -19 जुलाई 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावति किया. चौथी दुनिया निष्पक्ष समाचार प्रकाशित करता है, उम्मीद है कि ऐसे आगे भी निष्पक्षता और तथ्यों के साथ इसमें खबरें प्रकाशित होंगी.

-बिमल कुमार, दरभंगा, बिहार.

गुरूपर्व पर विशेष

साधक की आत्मोन्नति का दिन है गुरुपुर्णिमा

राजकुमार शर्मा

मानव के जीवन में उत्सव नहीं महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले गुरु पर्व को गुरुपूणिमा के नाम से जाना जाता है. शताब्दियों पूर्व हिन्दी महीने के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था, जिन्होंने वैदिक रचनाओं का संकलन कर इसका चार वेदों के रूप में वर्गीकरण किया. 18 पुराणों, 18 इप पुराणों, इपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, महाभारत आदि अतुलनीय ग्रन्थों को लेखनी बद्ध करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिनके लिए प्रसिद्ध है कि व्यासोच्छिष्ठम् जगत सर्वम् ऐसा कोई विषय नहीं है, जो व्यास जी का जूठन न हो. गुरु के अवतरण के मंगल दिन को ही गुरु के पूजन का दिन चुना, इसी कारण इस पूर्णिमा को व्यासपूर्णिमा भी कहा जाता है. आगे चल कर इसे महान साधक अपनी आत्म उन्नति का दिन मानने लगे. यह दिन विश्व के वैज्ञानिकों की कसौटी पर भी खरा उतरा है. विश्व के महान वैज्ञानिक आर्थर चाल्स स्टोक अपनी पुस्तक विस्डम ऑफ ईस्ट में लिखते हैं–वर्ष भर में अनेकों पूर्णिमाएं आती है–शरदपूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा आदि. लेकिन आषाढ़ पूर्णिमा भक्ति और ज्ञान के पथ पर चल रहे साधकों के लिए एक विशेष महत्व रखती है. इस दिन गगन मंडल में अल्ट्रावॉयलेट रेडिएशन(पैराबैगनी विकिरण)फैल जाती है .इस कारण व्यक्ति का शरीर व मन एक विशेष स्थिति में आ जाता है. इससे भूख, नींद व मन का विखराव कम हो जाता है. इनके लेखन का निष्कर्ष यह है कि यह स्थिति साधक के लिए बेहद लाभदायक है. वह इसका लाभ उठाकर अधिक ध्यान साधना कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है, इस तरह विश्व के वैज्ञानिक भी आत्मोत्थान और जन कल्याण के लिए गुरु पुर्णिमा को साधक की आत्मोन्नति का दिन होने पर अपनी सहमती व्यक्त करते हैं. इस पर कई शोध भी हुए जिस पर यह मान्यता पूरी तरह से सच साबित हुई है.

प्राचीन काल से ही गुरुकुल इस दिन को महोत्सव के रूप में मनाते रहे हैं. गुरुकुलों में इसी पावन अवसर पर नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता था, सभी जिज्ञासु छात्र इस दिन अपने हाथों में समिधा लेकर गुरु के समक्ष आते थे और प्रर्थना करते थे कि–हे गुरुवर हमारे भीतर ज्ञान–ज्योति प्रज्जवलित करें, हम इसके लिए स्वयं को समिधा के रूप में अर्पित करते हैं. इसी पर्व की मंगल बेला में जो छात्र गुरु द्वारा प्रदत्त सभी शिक्षाओं को दक्षता पूर्वक ग्रहण कर लेते थे, उन्हें गुरुकुल द्वारा प्रमाण प्रत्र भी जारी किया जाता था.

जैनधर्मावलम्बि भी इस पर्व को अपने सौभग्य पर्व के रूप में मनाते हैं. इसी पुण्यमय दिन को ही भगवान महावीर अपापा के महासेन उद्यान में विराजमान हुए थे. इनके दिव्य प्रभाव से मानव व देव इनके पास एकत्र हो रहे थे, ज्यों ही वेद विद्वान ब्राह्मण गौतम को पता लगा, उसके अहम को चोट लगी और वह इस उद्यान में पहुंचा, ज्यों ही उसने महावीर स्वामी के मुखचन्द्र को देखा, उसके भीतर का

अहम पिघल उठा, उसकी हृदय की धरा पर आस्था– श्रद्धा की गंगा उतर आई. वह एक प्रतिमा बन कर महावीर स्वामी को निहारता रहा. महावीर स्वामी ने कहा आओ इन्द्रभमति. हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे. आओ गौतम झाड़ दो अपने संशयों को, पाण्डित्य के भार से मुक्त हो जाओ. तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है. इन्द्रभूति गौतम श्री महावीर स्वामी के चरणों में गिर गया. भगवान श्री ने उसे अपने प्रथम शिष्य के रूप में दिक्षा दिया. इसी घटना को अंगीकार कर जैन सम्प्रदाय के लोग इस दिन को अहोभाव से मनाते है कि इस दिन ही उन्हें भगवान गुरु रूप में मिले. सारनाथ(काशी)की धरा धन्य हो उठी कि इसी दिन(आषाढ़ पूर्णिमा)महाबुद्ध सारनाथ पहुंचे और इन पाचों परिव्राजकों को धम्मोपदेश दिया. इसी पावन पर्व पर बौद्ध सम्प्रदाय की मौलिक शिक्षाएं–चार आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग इसी दिन अस्तित्व में आया. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

इतिहास लेखन की धुंध पर विमर्श

अनंत विजय

हाल के दिनों में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के पुनर्लेखन को लेकर खासा बवाल मचा है. केंद्र में नई सरकार के गठन और फिर भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अन्य संस्थाओं में नई नियुक्तियों को लेकर इस बात पर खूब विमर्श हो रहा है कि सरकार भारत का इतिहास बदलना चाहती है. इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, तब भी ऐसे आरोप उछले थे और इस बार भी उछल रहे हैं. भारत के इतिहास के पुनर्लेखन को सांप्रदायिकता से जोड़ने का खेल फिर से शुरू हो गया है. तर्कों के आधार पर बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास फिर से लिखा जाना चाहिए? इतिहास पुनर्लेखन के ख़िलाफ़ बात करने वालों का एक ही तर्क होता है कि यह पुराने धर्मनिरपेक्ष लेखन को दरकिनार करने की साजिश है. तर्क तो यह भी दिया जाता है कि जबरदस्ती हिंदू राजाओं एवं हिंदू शासकों के बहाने हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जाती रही है. इन तर्कों के समर्थन में सबसे आसान होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को शामिल करना. बहुधा यह कहा जाता है कि संघ के इशारे पर ही सरकार पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को बदलने की कोशिश कर रही है.

यही तर्क तब भी दिए गए थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे. जब मशहूर इतिहासकार बिपान चंद्रा की अगुवाई में चल रहे शोध टूवर्ड्स फ्रीडम का प्रोजेक्ट रोक दिया गया था, तब भी इन्हीं तर्कों के सहारे तत्कालीन सरकार को कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई थी. दरअसल, इतिहास लेखन पर जिस तरह से राजनीति होती है और जिस तरह से पक्ष–विपक्ष एक–दूसरे के आमने–सामने आ जाते हैं, उसमें असली मुद्दा दबकर रह जाता है. तर्क राजनीतिक बयानबाजी का शिकार होकर रह जाते हैं. एक पक्ष इतिहास लेखन की बात करता है या फिर उसे फिर से लिखवाने की मंशा जाहिर करता है, तो विरोधी उस पर सांप्रदायिकता या धर्म विशेष का पक्षधर होने का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं. बजाय इन आरोपों में उलझने के पाठ्य पुस्तक इतिहास पुनर्लेखन की ज़रूरतों और पूर्व की ग़लतियों या कमियों को सामने रखना चाहिए. किस तरह से पूर्व के इतिहासकारों ने कुछ पक्षों की जानबूझ कर या फिर अज्ञानतावश अनदेखी कर दी, उसके बारे में जनता को बताना चाहिए. होता यह है कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी छवि की आड़ में तर्कों को दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं. नतीजा यह होता है कि इतिहास लेखन की खामियों की ओर ध्यान नहीं जा पाता और सारा हल्ला–गुल्ला सांप्रदायिकता एवं धर्मनिरपेक्षता की भंवर में फंस जाता है.

भारतीय इतिहास लेखन को देखें, तो पाते हैं कि इसमें कई तरह की खामियां हैं. हमारे अब तक के इतिहास लेखकों ने इस बात पर खासा ज़ोर दिया कि भारत में कौन–कौन से आक्रमणकारी आए, किसने हमारे देश को कितना लूटा और किसने कितने लोगों की हत्या की वगैरह–वगैरह. मोटे तौर पर छात्रों को आक्रमणकारियों और युद्ध का इतिहास पढ़ाया जाता है. क्या इतिहास लेखन में सिर्फ़ युद्ध का ही उल्लेख होना चाहिए? क्या बाहर से आए उन कारोबारियों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे समाज को गहरे तक प्रभावित किया? आक्रमणकारियों का इतिहास लिखने में हम यह भूल जाते हैं कि पारसी और यहूदी कारोबारियों का भी हमारे देश के इतिहास में कोई स्थान है. क्या हमारे अब तक के इतिहासकारों ने उनके बारे में, उनके योगदान के बारे में सोचा? नहीं सोचा. अब अगर हम इससे थोड़ा अलग हटकर बात करें, तो सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी भी देश का इतिहास सिर्फ़ उसके शासकों के इर्द–गिर्द घूमता है?

अब हम उन तर्कों को सामने रखते हैं, जिनके आधार पर इतिहास पुनर्लेखन पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं. भारतीय विज्ञान का इतिहास लिखते वक्त क्या हमने अपनी गौरवशाली परंपरा की अनदेखी नहीं की? गणित से लेकर आयुर्वेद तक में भारत की जो उपलब्धियां रहीं, उन्हें जानबूझ कर या फिर एक साजिश के तहत अनद–ेखा नहीं किया गया. जिस देश में वैदिक गणित का लंबा इतिहास रहा है, उसे दरकिनार किया गया.

इस सवाल से मुठभेड़ करते हुए मशहूर इतिहासकार राम शरण शर्मा की अगुवाई में कई इतिहासकारों ने हाशिये के लोगों को भी इतिहास लेखन के केंद्र में रखा. यह ठीक क़दम था. सबाल्टर्न का इतिहास लिखा गया. फिर से वही सवाल उठता है कि क्या किसी देश का इतिहास सिर्फ़ राजा एवं प्रजा, शासक एवं शासित या फिर राजा के जुल्म और प्रजा की जुल्म सहने की दास्तां होता है या फिर इससे इतर भी कुछ होता है? दरअसल, हमारे देश के इतिहास लेखकों ने अपना दायरा काफी छोटा रखा. मुख्य रूप से आक्रमणकारियों, राजाओं और बाद में मार्क्सवादी इतिहासकारों की वजह से आम लोगों को इतिहास का अंग माना गया और उसके आधार पर ही इतिहास लेखन किया गया. क्या कभी हमने यह सोचने की कोशिश की कि हमारे इतिहास में नदियों की धारा बदलने का कोई प्रभाव पड़ा या नहीं? नदियों की धारा बदलने से एक तरफ़ जहां गांव ख़त्म हुए, वहीं दूसरी तरफ़ ज़मीन के बाहर आने से वहां नए गांव बसे. इन सबका जिक्र हमारी इतिहास की किताबों में क्यों नहीं है? यह सवाल तो उठाया ही जाना चाहिए और इसके आधार पर शोध करते हुए इतिहास को दुरुस्त भी किया जाना चाहिए.

अब हम उन तर्कों को सामने रखते हैं, जिनके आधार पर इतिहास पुनर्लेखन पर सांप्रदायिक होने के आरोप लगते हैं. भारतीय विज्ञान का इतिहास लिखते वक्त क्या हमने अपनी गौरवशाली परंपरा की अनदेखी नहीं की? गणित से लेकर आयुर्वेद तक में भारत की जो उपलब्धियां रहीं, उन्हें जानबूझ कर या फिर एक साजिश के तहत अनदेखा नहीं किया गया. जिस देश में वैदिक गणित का लंबा इतिहास रहा है, उसे दरकिनार किया गया. जब इस तरह के इतिहास लेखकों पर सवाल उठे, तो पुष्पक विमान जैसी मिथकीय चीजों को आगे कर उनका मज़ाक उड़ाया गया. अपनी कमी ढंकने के लिए यह कहा गया कि प्राचीन भारत में विज्ञान की बात करने वाले पुष्पक विमान और राक्षसों के हवा में उड़ने आदि की बात करते हैं. पौराणिक विज्ञान की बात करने वाले कुछ अज्ञानी किस्म के बाबाओं ने भी अनजाने में इन तर्कों को बढ़ाया और मूल प्रश्न दबे रह गए. अब अगर हम ऐतिहासिक चरित्रों की बात करें, तो वहां भी वस्तुनिष्ठता के साथ लेखन का साफ़ अभाव दिखता है. जिन चरित्रों को उभारना था, चाहे वह अशोक हो या अकबर, उनके सिर्फ़ अच्छे कारनामों को आगे किया गया.

सम्राट अशोक के चरित्र को अहिंसा का पुजारी और महान शासक के तौर पर गढ़ने में कलिंग युद्ध में उनकी सेना द्वारा किया गया नरसंहार भी उनके हृदय परिवर्तन से जोड़ दिया गया है. बगैर किसी ऐतिहासिक सुबूत के यह बात गढ़ी गई कि अशोक को उस नरसंहार के बाद बेहद अफ़सोस हुआ था. ठीक है, हम एक मिनट के लिए इतिहास के इस अध्याय को मान भी लें. लेकिन, क्या इतिहास कल्पना के आधार पर लिखा जाने वाला फिक्शन है या इतिहास सुबूतों एवं शिलालेखों पर मिले अवशेषों और संकेतों पर लिखा जाता है? यह बात अब तक सामने नहीं आई है कि किस शिलालेख या दस्तावेज़ में अशोक के इस हृदय परिवर्तन की चर्चा है. सिर्फ़ एक कहानी प्रतिपादित कर दी गई, जो पीढ़ियों से पढ़ाई जा रही है. क्या यह ज़रूरी नहीं है कि इस कहानी की पड़ताल की जाए? भारत में इतिहास लेखन में एक और बात मुख्य रूप से देखने को मिलती है कि यहां इतिहासकार तथ्यों में अपनी राय जोड़ते हुए उनका विश्लेषण करता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ भारत के इतिहासकारों ने इस पद्धति का इस्तेमाल किया है, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहासकार इतिहास लेखन के वक्त तथ्यों के साथ अपनी राय भी थोपते हुए चलते हैं. लेकिन, भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस छूट का बेजा इस्तेमाल किया और बहुधा तथ्यों पर अपनी राय हावी कर दी.

क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि इतिहास लेखन में इतिहासकारों की राय तथ्यों से अलग रखकर देखी जाए? तथ्यों की व्याख्या ज़रूरी है, लेकिन व्याख्या के बोझ तले तथ्यों को दबा देना अपराध है. अंत में हम बात करते हैं, इतिहास पुनर्लेखन पर लगने वाले सांप्रदायिकता के आरोप की. दरअसल अगर हम देखें, तो यह तर्क भी ग़लत है. हम पूरे परिदृश्य पर नज़र डालते हैं, तो पाते हैं कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर पूर्व तक के राजाओं को उतनी अहमियत नहीं दी गई, जितनी मध्य और उत्तर भारत के शासकों को दी गई. क्या सिर्फ़ मध्य और उत्तर भारत के शासकों पर विस्तार से लिखकर भारत के इतिहास को समझा जा सकता है? हमारे इतिहास में अशोक और अकबर की तुलना में चोल वंश से लेकर सातवाहन या फिर अहोम राजवंश के बारे में कितना उल्लेख मिलता है? इन तर्कों की कसौटी पर इतिहास लेखन को कसने की ज़रूरत है, तो फिर सारी धुंध खुद–ब–खुद साफ़ होती चली जाएगी. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

समय की परतों को भेदकर निकलता उपन्यास

संध्या द्विवेदी

कहानी हो या उपन्यास, कविता हो या किसी भी प्रकार का गद्य उसमें समसामायिकता का झलकना लेखन का जरूरी हिस्सा है. इस लिहाज से हा! हा! पंचकुमारी उपन्यास एक बेहतर लेखन का उदाहरण पेश करता है. एक राज्य और बलशाली राजा के बनने से लेकर उसके खत्म होने तक की पूरी कथा बिना हिचकी या गांठ के चलती है. लेखन में तारतम्यता और पाठक को बिना बोर किए उसे पूरी कहानी खत्म होने तक जोड़ कर रखना, लेखन की दूसरी बड़ी कला है. इस कसौटी पर भी यह किताब खरी उतरती है. जितने दिनों तक आप इस किताब को पढ़ेंगे आगे क्या होगा का सवाल दिमाग में हलचल पैदा करता रहेगा. पहले ही अध्याय के पहले ही पैराग्राफ इसका उदाहरण है–जी हां, यही वह प्रपात है, जो इतिहास के आईने में हा! हा ! पंचकुमारी के नाम से जाना जाता है. क्या आप जानते हैं कि युगों से बहता हुआ इसका पानी आज भी लाल है? अंजुलि से उलीचिए लाल दिखेगा, पात्र में उठाइए लाल दिखेगा, उस पानी को कहीं कुएं, किसी तालाब में डाल दीजिए यकीन मानिए वह भी लाल दिखेगा, बस देखने की दृष्टि चाहिए.

यहीं से शुरू होती है उत्सुकता. यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उपन्यास का शीर्षक भी एसा है जो पाठक के भीतर उत्सुकता जगाने में कामयाब साबित होता है. तीसरी, जो इस उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि इतिहास के कुछ अनकहे पहलुओं को बेहद खोज और तर्कों के साथ पेश किया गया है. ज्यादातर शोध आधारित उपन्यास या फिर किताबें कहानी कहने की कला पर भारी पड़ जाती हैं. मतलब ऐसा लेखन तर्क और तथ्यों के आधार पर तो मजबूत होता है मगर यहां किस्सागोई की कला को बचाकर रखना चुनौती होता है. मगर इस उपन्यास में तर्क, तथ्य और किस्सागोई तीनों समानांतर चलते हैं. अगर कुछ अखरता है तो भाषा की कठिनाई. इसका कारण शायद यह है कि राजाओं की सत्ता दिखाने और अतीत में झांकने के लिए उस वक्त की भाषा ही हम चुनते हैं. मगर इसे सरल भाषा में लिखने का प्रयास इसे आमजन तक पहुंचा सकता था. यह किताब मुगलकालीन इतिहास का एक बेजोड़ किस्सा कहती है. जो मौजूदा इतिहास की बखिया उधेड़ने वाला है. ऐसे में यह किस्सा केवल बुद्धिजीवियों, लेखकों और समीक्षकों से भी आगे छात्र–छात्राओं या किसी भी पेशे से जुड़े लोगों की पहुंच में होना चाहिए. कठिन भाषा इसके पाठकों को सीमित कर सकती है.

उपन्यास का ताना–बाना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर बुना गया है तो इसमें उस वक्त देश–काल में छाया तिलिस्म भी दिखाई देता है. एक जगह एक तांत्रिक मां काली का कंगन लेकर अमावस्या में पूरनमासी का चांद दिखा देता है तो ग्यारहवें अध्याय में एक भोला भाला ग्रामीण कालीचरण जो बोलचाल की भाषा में कलुआ हो गया है, एक तांत्रिक बाबा से भयभीत होकर

उपन्यास का ताना–बाना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर बुना गया है तो इसमें उस वक्त देश–काल में छाया तिलिस्म भी दिखाई देता है. एक जगह एक तांत्रिक मां काली का कंगन लेकर अमावस्या में पूरनमासी का चांद दिखा देता है तो ग्यारहवें अध्याय में एक भोला भाला ग्रामीण कालीचरण जो बोल–चाल की भाषा में कलुआ हो गया है, एक तांत्रिक बाबा से भयभीत होकर काली मां की जीभ से खून टपकने की रहस्यमयी घटना बता रहा है. वह कहता है–बाबा आज तो वह हुआ, जो कभी नहीं हुआ. जब मैं पानी लेने जा रहा था, तभी कुछ लोगों को यह कहते सुना कि सिंघिया मसान की मसानी काली के जीभ से टप–टप खून रिस रहा है.

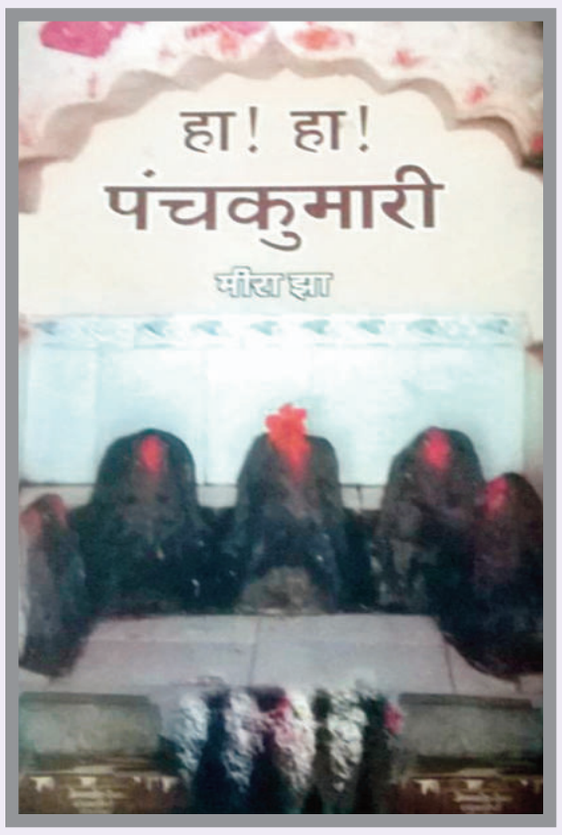

काली मां की जीभ से खून टपकने की रहस्यमयी घटना बता रहा है. वह कहता है–बाबा आज तो वह हुआ, जो कभी नहीं हुआ. जब मैं पानी लेने जा रहा था, तभी कुछ लोगों को यह कहते सुना कि सिंघिया मसान की मसानी काली के जीभ से टप–टप खून रिस रहा है. ऐसे उदाहरण इस उपन्यास में कई जगह मिल जाएंगे.

राजा संग्राम सिंह जिस तरह से हमेशा गुणवान व्यक्ति की खोज और उन्हें अपने राज्य में बसाने को आतुर रहते थे उससे तो यही पता चलता है कि पहले के राजा राज्य को समृद्ध बनाने में माहिर थे. राजा संग्राम सिंह राज्य बसाते वक्त कुशल चिकित्सक, बढ़ई बसाने, शिल्पकार बसाने की सलाह को यथावत मानते हुए हर तरह के गुणों के धनी लोगों के कुनबे को बसाते हैं. यहां तक कि करतब दिखाने वाले नट से राजा इतने खुश होते हैं कि उसे भी अपने राज्य में बसने का विनयपूर्वक आमंत्रण देते हैं.

उपन्यास में केवल वीर राजा की ही कथा नहीं है, इतिहास जानता है कि वीरांगनाओं ने भी अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्ध लड़े और जीते हैं. अपनी कुल देवी के आगे राजा साहब के मस्तक से अचानक फूट निकले खून के फव्वारे को देखकर रानी चंद्रज्योत किसी साधारण स्त्री की तरह विलाप नहीं करतीं बल्कि काली के सामने रखी तलवार उठाकर कहती हैं– यहां की पूर्णाहूति हो गई, वहां की पूर्णाहूति के लिए मुझे स्वयं जाना होगा. मृत राजा के रक्त से अपने माथे पर तिलक लगाकर वह अपने घोड़े में बिजली की गति से बैठकर अपनी सेना के बीच कुशल नेतृत्व की बागडोर संभालकर चल पड़ती हैं युद्ध करने. युद्ध लड़ती है जीतती भी है–मगर छल के आगे हार जाती है. छल से दूसरी तरफ का सेनापति उनके बेटे को बंदी बना लेता है. अभी–अभी योद्धा के रूप में गरज रही रानी चंद्रज्योत बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है.

दूसरी तरफ उनकी पांच बेटियां मुगलों के हाथों में न जाकर एक विशाल झरने में कूद पड़ती हैं. जिस तरह से राजा संग्राम सिंह बादशाह की हुकूमत स्वीकार करने से बचते हैं और आखिर में गुलामी की जगह युद्ध चुनते हैं. ठीक वैसे ही उनकी पांचों बेटियां आन–बान–शान की खातिर मुगलों की दासी बनने से बेहतर मौत को गले लगाती है. बस यहीं इस उपन्यास का शीर्षक अपने अंजाम पर पहुंचता है. महातांत्रिक भीषण मिश्र पूरे परिवार की अकाल मौत होने की बात कहकर बिना किसी वंश के व्यक्ति के श्राद्ध करने की परंपरा अन्य पंडितों और ग्रामवासियों के साथ पूरी करते हैं. राजा रानी का श्राद्ध जहां कुश के प्रतीक बनाकर किया गया वहीं पांचों कुमारियों की आत्मा की शांति के लिए सिंदूर की पांच रेखाएं खींचकर उनका श्राद्ध हुआ. यही पांच रेखाएं पंचकुमारियों के रूप में लोक में पूजी जाती हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

फेसबुक पेज पर जल्द ही ई–कॉमर्स शॉपिंग साइटों तक पहुंच बनाई जा सकेगी. इसके साथ ही चुने गए सामान की खरीदारी करने के लिए एक बाय (खरीदें) बटन भी होगा, जिसकी मदद से आप अपने मनपसंद सामान को चुन सकेंगे व खरीद सकते हैं. कंपनी का कहना है कि फेसबुक पेज पर शॉपिंग वर्ग होने के साथ हम उनके उत्पादों को सीधे यूजर्स के पेज पर दिखाएंगे.

श्याओमी का बेहतरीन है यह हेडफोन

श्याओमी इंडिया एमआई ने अपने हेडफोन्स को लॉन्च किया है. कंपनी ने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किसी वेबसाइट के साथ टाईअप नहीं किया है, बल्कि इन्हें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही लिस्ट किया है. एमआई का यह हेडफोन सेमी ओपन हेडफोन है. इसमें 50एमएम का बेरिलियम डायफ्राम के स्पीकर दिए गए हैं. इसके साथ इसमें आपस में बदले जा सकने वाले (इंटरचेंजेबल) ओवर–ईयर और ऑन–ईयर कवर भी दिए गए हैं. यह फोन ब्लैक और गोल्ड कलर में उपलब्ध होगा. इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन से हेडफोन को शानदार लुक मिलता है. इसके साथ ही इसमें 3डी ऑडियो रियलिस्टिक सराउंड साउंड क्वालिटी दी गई है. इसके अलावा इस हेडफोन में जो केबल दिया गया है वह सिल्वर प्लेटेड है. केबल में केवलर (Kevlar) फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, जो केबल को टूटने से बचाता है. हेडफोन के बाकी फीचर्स की बात की जाए तो इसमें माइक्रोफोन दिया गया है. इससे यूजर को कॉल करने और रिसीव करने में आसानी होती है. इसका वजन 220 ग्राम है. कंपनी ने इस हेडफोन की कीमत 5,499 रुपये रखी है. ■

रेनो की क्विड है दमदार

रेनो ने भारत में अपनी कार रेनो क्विड लॉन्च की है. यह कार इस साल त्योहारों के मौसम में भारतीय बाजार में आएगी. कंपनी का कहना है कि रेनो ने भारतीय बाजार में पांच फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है और नई कार की इसमें बड़ी भूमिका होगी. उनका मानना है कि रेनो क्विड इस वर्ग में पहले से स्थापित मारुति सुजुकी और हुंदै जैसी कंपनियों से मुकाबला करेगी. कंपनी भारत को इस नई कार के निर्यात का क्षेत्रीय केंद्र बनाने पर विचार कर रही है. करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित एसयूवी के आकार की इस छोटी कार में 800 सीसी का पेट्रोल इंजन होगा. इसक कार की कीमत देश में चार लाख रुपये तक होगी. ■

कंपनी का कहना है कि रेनो ने भारतीय बाजार में पांच फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है और नई कार की इसमें बड़ी भूमिका होगी. उनका मानना है कि रेनो क्विड इस वर्ग में पहले से स्थापित मारुति सुज़ुकी और हुंदै जैसी कंपनियों से मुकाबला करेगी. कंपनी भारत को इस नई कार के निर्यात का क्षेत्रीय केंद्र बनाने पर विचार कर रही है.

फेसबुक से अब शॉपिंग भी होगी

आप शॉपिंग के लिए विभिन्न साइट का इस्तेमाल करते ही होंगे. आपको बता दें कि फेसबुक पर अब जल्द ही शॉपिंग का लुत्फ भी उठाया जा सकेगा. फेसबुक पेज पर जल्द ही ई–कॉमर्स शॉपिंग साइटों तक पहुंच बनाई जा सकेगी. इसके साथ ही चुने गए सामान की खरीदारी करने के लिए एक बाय (खरीदें) बटन भी होगा, जिसकी मदद से आप अपने मनपसंद सामान को चुन सकेंगे व खरीद सकते है. कंपनी का कहना है कि फेसबुक पेज पर शॉपिंग वर्ग होने के साथ हम उनके उत्पादों को सीधे यूजर्स के पेज पर दिखाएंगे. लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि ये नए फीचर्स कब से शुरू होंगे. क्योंकि अभी इनका परीक्षण चल रहा है. ■

सैमसंग का 4जी धमाका

सैमसंग को देश में 4जी स्मार्टफोन की बढ़ती मांग से बड़ी उम्मीदें हैं. इसलिए कंपनी ने दो 4जी स्मार्टफोन पेश किए हैं. कंपनी के मुताबिक उनके पास 10 एलटीई(4जी) स्मार्टफोन थे. इसलिए नये स्मार्टफोन ला रहे हैं. आगे चलकर और अधिक 4जी स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे. कंपनी ने कहा कि देश में 4जी को 3जी की अपेक्षा तेजी से अपनाया जाएगा. गैलेक्सी जे5 में पांच ईंच का डिस्प्ले,

आगे चलकर और अधिक 4जी स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे. कंपनी ने कहा कि देश में 4जी को 3जी की अपेक्षा तेजी से अपनाया जाएगा. गैलेक्सी जे5 में पांच ईंच का डिस्प्ले, 8जीबी रोम, 13एमपी कैमरा है और 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर है.

8जीबी रोम, 13एमपी कैमरा है और 1.2 गीगाहर्ट्ज क्वाडकोर प्रोसेसर है. गैलेक्सी जे7 में 5.5 ईंच डिस्प्ले, 16जीबी रोम व 13एमपी कैमरा है. 1.5 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है. कंपनी ने 4जी सर्विस के लिए एयरटेल से गठजोड़ किया है. इनमें गैलेक्सी जे5 की कीमत 11999 रुपये जबकि गैलेक्सी जे7 की कीमत 14999 रुपये रखी है. ■

स्पीड किंग है ब्लैक बुलेट स्काउट

इस बाइक का नाम ब्लैक बुलेट स्काउट है. यह बाइक 2015 इंडियन स्काउट पर बेस्ड है. इस बाइक को बनाने वाले जेब स्कोलमैन है. स्कोलमैन ने ही मुनरो की स्पिरिट को डिजाइन किया था, जिसे 2014 में थंडरस्ट्रोक 111 के लॉन्चिंग को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था.

इंडियन मोटरसाइकिल की बाइक्स अपने मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. इसकी स्काउट बाइक तो कई बाइकर्स की फेवरिट बाइक्स में से है. उसी स्काउट को बॉनविले सॉल्ट फ्लैट्स पर दौड़ाने के लिए कस्टम मेड किया गया है. इस बाइक का नाम ब्लैक बुलेट स्काउट है. यह बाइक 2015 इंडियन स्काउट पर बेस्ड है. इस बाइक को बनाने वाले जेब स्कोलमैन है. स्कोलमैन ने ही मुनरो की स्पिरिट को डिजाइन किया था, जिसे 2014 में थंडरस्ट्रोक 111 के लॉन्चिंग को सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था. जेब को 2015 इंडियन स्काउट का एक इंजन दिया गया और साथ ही उन्हें पूरी आजादी दी गई कि वह जो कुछ भी बनाना चाहें, उस इंजन से बना सकते हैं. जेब ने 1950 और 1960 की स्पीड मोटरसाइकल्स से प्रेरणा लेकर ब्लैक बुलेट स्काउट को बना डाला. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

यदि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो तो उसका असर मैदान में खिलाड़ियों के खेल में भी नज़र आता है. साल 1996 में जब श्रीलंका ने विश्वकप पर कब्जा किया था, उस वक्त श्रीलंकाई टीम का माहौल भी अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में कुछ इसी तरह का था. उनकी उस टीम को डेव वॉटमोर जैसे कोच का साथ मिला तो उस श्रीलंकाई टीम ने अनहोनी को होनी कर दिखाया. आज की बांग्लादेशी टीम भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है. धीरे-धीरे टीम संतुलित होती जा रही है.

बंगाल टाइगर का बढ़ता कद

हाल के दिनों में बंगाल टाइगर्स ने जिन टीमों का शिकार किया है, उनमें से कोई भी टीम दोयम दर्जे की नहीं थी. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बांग्लादेशी क्रिकेट का नया दौर और नया अध्याय शुरू हो गया है. भारत के बांग्लादेश दौरे के समय टीवी पर दिखाया जाने वाला विज्ञापन बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया है पूरी तरह सही साबित हो रहा है. बांग्लादेश को हर देश अब गंभीरता से लेने लगा है, उसे कमजोर आंकने की गलती कोई नहीं करना चाहता है और सभी उससे डरने भी लगे हैं.

नवीन चौहान

बंगाल टाइगर की दहाड़ आजकल क्रिकेट की दुनिया में हर जगह सुनाई पड़ रही है. ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी क्रिकेट 0का कायाकल्प हो गया है. श्रीलंका की तरह बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का उदय एक दिवसीय क्रिकेट की एक बड़ी टीम के रूप में हो रहा है. बांग्लादेश की इस टीम ने पिछले आठ महीनों में दुनिया की टॉप पांच टीमों को एकदिवसीय मैचों में पटखनी दी है. जीत का यह सिलसिला पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था. बांग्लादेश ने उस सीरीज में जिंबाब्वे को 5-0 के अंतर से मात दी थी. यह जीत जिंबाब्वे जैसी छोटी टीम के सामने थी, इसलिए इस पर उस वक्त लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस वाकये को भूल गए. लेकिन यह चिंगारी धीरे-धीरे आग में बदल गई. बांग्लादेश की इस आग की लपेट में आने वाली पहली टीम इंग्लैंड की थी. बांग्लादेश नें विश्वकप में इंग्लैंड को मात देकर उसकी ग्रुप स्टेज के बाद ही घर वापसी करा दी. लीग मैच के इस अहम मुक़ाबले में इंग्लैंड को 15 रनों से मात देकर बांग्लादेश ने पहली बार विश्वकप के नॉकआउट दौर में प्रवेश किया. विश्वकप में 5 लीग मैचों में से 3 में जीत हासिल करने बांग्लादेश अंतिम आठ में पहुंची. लेकिन वहां बांग्लादेश का मुक़ाबला गत विजेता भारत से हुआ. इसके बाद उसका विश्वकप में सफर खत्म हो गया. हालांकि बांग्लादेश की टीम ने इस हार के लिए खराब अंपायरिंग को जिम्मेदार ठहराया था. इसके विरोध में बांग्लादेश के मुस्तफा कमाल ने आईसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.

विश्व कप के बाद बांग्लादेश दौरे पर पहुंची पाकिस्तानी टीम का बांग्लादेश ने सूपड़ा साफ कर दिया और 3-0 के अंतर से जीत दर्ज की तो लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए. इसके बाद विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची टीम इंडिया बांग्लादेश दौरे पर पहुंची. विश्वकप में केवल एक मैच हारने वाली टीम इंडिया पाकिस्तान की हार को ध्यान में रखकर अपनी पूरे दल बल के साथ बांग्लादेश दौरे पर पहुंची. सीरीज के पहले ही मैच में टीम इंडिया को 79 रनों से पटखनी देकर बांग्लादेश ने विश्वकप के क्वार्टर फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया और हर किसी को एक बार फिर सकते में डाल दिया. टीम इंडिया के खिलाफ जीत के हीरो रहे नये गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान. उन्होंने अपने पदार्पण मैच में 50 रन देकर पांच भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. इसके बाद बांग्लादेश ने टीम इंडिया को संभलने का मौका नहीं दिया और दूसरे मैच में 6 विकेट से जीत दर्ज कर पहली बार भारत के खिलाफ सीरीज जीतने में कामयाब हुई. इस मैच में भी मुस्ताफिजुर भारतीय गेंदबाजों के लिए अबूझ पहेली बने रहे. 19 वर्षीय मुस्ताफिजुर ने इस बार 6 खिलाड़ियों को पैवेलियन का रास्ता दिखाया. तीसरे मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल कर अपनी थोड़ी बहुत साख बचाने में कामयाब रही, लेकिन सीरीज 2-1 के अंतर से गंवा बैठी.

इसके बाद विश्वकप के सेमी-फाइनल तक पहुंचने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम बांग्लादेश के दौरे पर आई. दौरे की शुरूआत में खेले गए दो टी-20 मुकाबलों में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दिवसीय मैचों की शुरूआत होते ही टीम की भाव-भंगिमा पूरी तरह बदल गई. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में बांग्लादेश को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने जोरदार वापसी करते हुए दूसरे मैच में जीत दर्ज कर पहले बराबरी की और तीसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा कर लिया. यह बांग्लादेश की घरेलू सरजमीं पर लगातार चौथी एकदिवसीय श्रृंखला की जीत है. पिछले बीस एक दिवसीय मैचों में बांग्लादेश ने 15 मैचों में जीत हासिल की है. केवल 5 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. घरेलू सरजमीं पर उन्हें केवल दो मैचों में हार मिली है.

हाल के दिनों में बंगाल टाइगर्स ने जिन टीमों का शिकार किया है, उनमें से कोई भी टीम दोयम दर्जे की नहीं थी. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बांग्लादेशी क्रिकेट का नया दौर और नया अध्याय शुरू हो गया है. भारत के बांग्लादेश दौरे के समय टीवी पर दिखाया जाने वाला विज्ञापन बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया है पूरी तरह सही साबित हो रहा है. बांग्लादेश को हर देश अब गंभीरता से लेने लगा है, उसे कमजोर आंकने की गलती कोई नहीं करना चाहता है और सभी उससे डरने भी लगे हैं. बांग्लादेश के हालिया प्रदर्शन के आधार पर उनका डर जायज है. इसी प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश आईसीसी की वन-डे टीम रैंकिंग में टॉप 8 टीमों में शामिल रहते हुए 2017 में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई भी कर लिया है.

जिंबाब्वे के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक के बांग्लादेश का गेंदबाजी कोच बनने के बाद से बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी में अप्रत्याशित परिवर्तन आया है. बांग्लादेशी गेंदबाज अब ज्यादा खुलकर और अनुशासित तरीके से गेंदबाजी करते दिखाई दते हैं. जो कद विश्व क्रिकेट में जिंबाब्वे का था अमूमन कुछ वैसा ही हाल बांग्लादेश का भी है. जिंबाब्वे का कप्तान रहते हुए उन्होंने जीत और हार के बीच के कुछ कदम के फासले को कई बार देखा है. वह बतौर बांग्लादेशी कोच इस कमी को पूरा होते देखना चाहते हैं. इसलिए गेंदबाजों के साथ अपने करियर का पूरा अनुभव बांट रहे हैं. इसके अलावा मुशरफे मुर्तजा के कप्तान बनने के बाद तेज गेंदबाजी वाली आक्रामकता पूरी टीम में नज़र आने लगी है. हालांकि हर कप्तान की कप्तानी का अंदाज जुदा होता है. उसी जुदा अंदाज का सीधा असर बांग्लादेश की टीम के प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है. मैदान पर टीम एकजुट नज़र आती है और विकेट मिलने का सेलिब्रेशन भी बड़े ही आक्रामक अंदाज में होता है. यह टीम की सफलता का एक प्रमुख कारण है.

टीम के कई पूर्व कप्तान और वर्तमान कप्तान साथ-साथ खेल रहे हैं लेकिन इन सभी के बीच अहम का टकराव जैसी कोई चीज नज़र नहीं आती है. यदि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा हो तो उसका असर मैदान में खिलाड़ियों के खेल में भी नज़र आता है. साल 1996 में जब श्रीलंका ने विश्वकप पर कब्जा किया था, उस वक्त श्रीलंकाई टीम का माहौल भी अर्जुन रणतुंगा की कप्तानी में कुछ इसी तरह का था. उनकी उस टीम को डेव वॉटमोर जैसे कोच का साथ मिला तो उस श्रीलंकाई टीम ने अनहोनी को होनी कर दिखाया. आज की बांग्लादेशी टीम भी उसी ट्रैक पर आगे बढ़ रही है. धीरे-धीरे टीम संतुलित होती जा रही है. टीम के बल्लेबाजों के पास आज अनुभव भी है और खेल की सही तकनीक भी. मोहम्मदुल्लाह और तमीम इक़बाल बल्लेबाजी की रीढ़ हैं. वहीं शाकिब अल हसन अपनी धारदार फिरकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से टीम को संतुलित करते हैं. कप्तान मशरफे मुर्तजा के नेतृत्व में तेज़ गेंदबाज विरोधी टीमों पर कहर ढा रहे हैं, उसमें मुस्ताफिजुर जैसे नए गेंदबाज सोने पे सुहागा जैसे हैं.

बांग्लादेश के खिलाड़ी अब जीत-हार के डर के बिना मैदान पर उतरते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं. टीम हार के डर से ऊपर उठ चुकी है. लेकिन उसे अभी सफलतायें घरेलू सरजमीं पर ही मिल रही है. विदेशी धरती पर उनकी इम्तिहान होना अभी बाकी है. हाल ही में जिन टीमों के खिलाफ बांग्लादेश ने जीत हासिल की है उन सभी के खिलाफ उसके खेलने का अंदाज तकरीबन एक जैसा आक्रामक था. बांग्लादेश के क्रिकेटर जिस तरह एक जुट होकर खेल रहे हैं, वह अन्य टीमों के लिए मिसाल है. टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है. टीम में जहां चार ऑलराउंडर(महमुदुल्लाह, शाकिब अल हसन, नासिर हुसैन और मशरफे मुर्तजा) खिलाड़ी है, जो किसी भी समय अपनी गेंदबाजी या बल्लेबाजी या फिर दोनों की बदौलत मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं. मुश्फिकुर रहीम जैसा विकेटकीपर बल्लेबाज टीम को और संतुलित बनाते हैं. यदि गेंदबाजी टीम की ताकत है तो बल्लेबाज भी अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रहे हैं. टीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टीम किसी एक खिलाड़ी पर पूरी तरह निर्भर नहीं है. हर खिलाड़ी अपने दिन मैच जिताऊ प्रदर्शन कर जाता है. इसके साथ ही टीम की बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत है, किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर टीम में शामिल किया गया खिलाड़ी उसकी कमी महसूस नहीं होने देता है.

सौम्य सरकार जैसे युवा बल्लेबाज जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी के कारण विरोधी गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं. इससे दूसरे बल्लेबाजों का मनोबल बढ़ता है और वह इसका फायदा उठा पाते हैं. सौम्य ने अब तक खेले 16 एकदिवसीय मैचों में 50 से भी अधिक के औसत से रन बनाये हैं. उनका स्ट्राइक रेट भी 100 से ज्यादा है. उनकी वजह से तमीम इक़बाल और मुश्फिकुर रहीम जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का दबाव और टीम की निर्भरता भी कम हुई है.

बांग्लादेश क्रिकेट लीग में विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है, इस वजह से युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आ रहा है. विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने की वजह से खिलाड़ियों के आत्मविश्वास में भी बढ़ोत्तरी हुई है.वे घरेलू क्रिकेट में खेलते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर का अनुभव हासिल कर रहे हैं. इसके अलावा बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड दुनिया का पांचवा सबसे अमीर बोर्ड है. यह पैसा क्रिकेट के विकास में खर्च हो रहा है. यदि ऐसा होता रहा तो बांग्लादेश क्रिकेट की कायापलट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा.मशरफे मुर्तजा टीम को सामने से लीड कर रहे हैं, आक्रामक होने के साथ वह चतुर कप्तान भी हैं, उनमें क्रिकेट की अच्छी समझ है और वह उनकी कप्तानी में झलकती है वह प्रयोग करने से भी नहीं हिचकते हैं. फील्ड प्लेसमेंट से लेकर बैटिंग ऑर्डर में वह जरूरत के अनुरूप बदलाव करते हैं. यह सबकुछ उन्हें एक बेहतर और सफल कप्तान बनाता है. उनकी सफलता सीरीज दर सीरीज टीम की जीत के रूप में दिखाई पड़ रही है. यदि ऐसा ही रहा तो बंगाल टाइगर जल्दी ही दुनिया की टॉप 5 टीमों में शुमार हो सकती है, लेकिन इसके लिए इनके लिए विदेशी धरती पर जीत हासिल करना जरूरी होगा. ■

navinonline2003@gmail.com

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

कॉमेडी के बादशाह की वापसी

कादर ख़ान ने कहा हो गया दिमाग़ का दही

भारतीय सिनेमा जगत में क़ादर ख़ान को एक ऐसे बहुआयामी कलाकार के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने डायलॉग लेखक, खलनायक, सहनायक, और हास्य अभिनेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई. क़ादर ख़ान के अभिनय की एक विशेषता यह है कि वह किसी भी तरह की भूमिका के लिए उपयुक्त हैं. फिल्म कुली एवं वर्दी में एक क्रूर खलनायक की भूमिका हो या फिर, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी और प्यार का देवता जैसी फिल्मों में हास्य अभिनय, इन सभी चरित्रों में उनके अभिनय का कोई जवाब नहीं है. बाप नंबरी–बेटा दस नंबरी, तक़दीरवाला, दूल्हे राजा, जुदाई, कुली नं.–1 और राजा बाबू जैसी कई फिल्में लोगों को अगर अभी भी गुदगुदाती हैं तो उसका एक बड़ा कारण क़ादर ख़ान ही हैं. तकरीबन 9 साल तक क़ादर ख़ान फिल्मों से दूर रहे लेकिन सारा बॉलीवुड और प्रशंसक उनकी वापसी की राह देख रहे थे. डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड (डीएमएल) द्वारा निर्मित और फौजिया अर्शी द्वारा निर्देशित फिल्म ***हो गया दिमाग़ का दही*** से किंग ऑफ कामेडी रुपहले पर्दे पर वापसी कर रहे हैं.

पिछली बार क़ादर ख़ान मीडिया की सुर्खियों में हज यात्रा की वजह से आए थे. तबीयत खराब होने के बावजूद वह व्हील चेयर पर हज यात्रा पर गए थे. वहां उनके साथ उनकी पत्नी और दोनों बेटे सरफराज और शहनवाज भी थे.

क़ादर ख़ान को जिस तरह की डॉयलाग डिलेवरी के लिए जाना जाता है, उनका वही रूप फिल्म ***हो गया दिमाग़ का दही*** में एक बार फिर से दिखाई देगा. क़ादर ख़ान 22 अक्टूबर को 79 वर्ष के हो जायेंगे, लेकिन फिल्मों को लेकर उनके जुनून में कोई कमी नहीं आई है. वह आगे भी डेली मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ 2 अन्य फिल्मों परछाई और शमा में भी नज़र आयेंगे.

क़ादर ख़ान ने कहा कि मुझे दस साल तक सारी दुनिया ने मिस किया. मैंने काम करना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मुझे मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे लोग और उनके जैसा पैशन किसी और में नज़र नहीं आता था. मैंने काम तो बहुतों के साथ किया लेकिन मेरे मन को कुछ कचोट रहा था. यही मेरे काम बंद करने की वजह थी. जब मेरे पास हो गया दिमाग़ का दही का प्रोजेक्ट आया, तो मुझे लगा कि इसमें वही बात है जो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मों में होती थी. इसमें न द्विअर्थी संवाद थे और न ही उल–जुलूल हरकतें. मुझे यह एक साफ सुथरी परिवार के साथ देखी जा सकने वाली फिल्म लगी. इसके साथ ही मुझे निर्देशक पर भरोसा हुआ कि वह इसे निभा ले जायेंगी. आज मुझे लगता है कि मेरा आकलन सही साबित हुआ.

79 वर्ष की उम्र में भी क़ादर ख़ान के मन कुछ नया सीखने के ललक है, उन्होंने एक नये निर्देशक के साथ काम करने के अनुभव के बारे में कहा कि मैं खुशनसीब हूं कि मुझे फौजिया अर्शी की सरपरस्ती में कुछ सीखने का मौका मिला. कोई डायरेक्टर नया नहीं होता है उसका काम करने का तरीका पुराने किसी न किसी डायरेक्टर से मिलता–जुलता होता है. फौजिया अर्शी का काम मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा दोनों से मिलता जुलता है. एक कॉमेडी का बादशाह था तो दूसरा स्क्रीन–प्ले और डायलॉग्स में महारथ रखता था, ये दोनों ही चीजें ***हो गया दिमाग़ का दही*** में देखने को मिलेंगी. साथ ही नई पीढ़ी के कॉमेडियन्स के बारे में उन्होंने कहा कि वे क़ादर ख़ान और आसरानी के कॉम्बीनेशन को याद रखें. बॉलीवुड में कॉमेडी का नया अध्याय यहीं से शुरू होता है.

क़ादर ख़ान ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के तौर पर की थी. वह मुंबई में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में बतौर शिक्षक काम करते थे. फिल्मों में अभिनय का पहला मौका उन्हें दिलीप कुमार ने दिया था. खलनायक के रूप में उनकी खौफनाक मुस्कान वक्त के साथ हंसी के फुहारों में बदल गई. डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा के साथ उन्होंने दर्शकों को खूब लोट–पोट किया. हालांकि समय के साथ वह रुपहले पर्दे से दूर होते गए और अपना ज्यादातर वक्त लेखन में ही गुजारने लगे. क़ादर ख़ान नई पीढ़ी के साथ काम करने में ज्यादा सहज महसूस नहीं करते. उनका कहना है कि आज की पीढ़ी कम्प्यूटर साइंस, तकनीक और बिजनेस मैनेजमेंट पर ज्यादा निर्भर है.

30 साल तक हिंदी सिनेमा पर राज करने वाले क़ादर ख़ान के डॉयलाग लेखन में सबसे बड़ा योगदान थिएटर का है. उन्होंने अनेक नाटकों के लिए संवाद लिखे. इसके अलावा कई नाटकों का निर्देशन भी किया. उन्होंने जिन नाटकों का निर्देशन किया उसके हर कैरेक्टर का अभिनय करके अन्य कलाकारों को दिखाते थे. ऐसा करते–करते उनके अंदर का कलाकार समय के साथ परिपक्व होता गया. अमिताभ बच्चन की आवाज और क़ादर ख़ान के डायलॉग की जोड़ी बेहद अदभुत थी. क़ादर ख़ान के डायलाग्स को अमिताभ बच्चन ने आवाज दी. मुंबई की टपोरी भाषा को फिल्मों में जगह दिलाने वाले क़ादर ख़ान ही थे.क़ादर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी कलम को अमिताभ बच्चन के गले की तलाश होती थी.

सत्तर–अस्सी के दशक में फिल्म इंडस्ट्री क़ादर ख़ान की कलम की दीवानी थी. अफगानिस्तान में पैदा हुए और मुंबई के कमाठीपुरा में पले–बढ़े क़ादर ख़ान ने अपने आसपास के वाकयों को अपने लेखन में जगह दी. अमर अकबर एंथनी का, एंथनी हो या अग्निपथ का विजय दीनानाथ चौहान या फिर सत्ते पे सत्ता के किरदार, इन सभी के लिए डायलॉग क़ादर ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर ही लिखे. प्रकाश मेहरा उनके लिखे डायलॉग्स के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी फिल्मों में उन्हें विलेन का काम देना शुरू कर दिया. उस समय विलेन की बड़ी कमी थी, इसलिए जिन फिल्मों के लिए वे डायलॉग्स लिखते उन फिल्मों में विलेन का किरदार भी अदा करते थे. उन्होने अपने करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में अभिनय किया है और 150 फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे.

क़ादर ख़ान एक संपूर्ण कलाकार हैं. उन्होंने फिल्मों में हर तरह की भूमिकाएं अदा कीं. उन्होंने बॉलीवुड को अपनी कलम, डायलॉग्स और अभिनय से एक नई दिशा दी. और प्रशंसकों के दिल में अपनी अलग छाप छोड़ी. प्रशंसक पिछले कई सालों से प्रशंसक उनका इंतजार कर रहे हैं. मशहूर फिल्म निर्देशक राज सिप्पी ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा था कि कोई अच्छा रोल मिले तो क़ादर ख़ान को फिल्मों में वापसी करनी चाहिए. शायद उन्होंने सही कहा था क्योंकि उनके बिना उनके बॉलीवुड अधूरा है.■

इंटरनेट पर *हो गया दिमाग़ का दही* की धूम

डीएमएल के बैनर तले फौजिया अर्शी के निर्देशन में बनी कॉमेडी फिल्म ***हो गया दिमाग़ का दही*** का ट्रेलर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. ट्रेलर के लॉन्च होते ही इस फिल्म को यू–ट्यूब पर लाखों लोग देख चुके हैं. पहले ही दिन यू–ट्यूब और अन्य इंटरनेट साइट्स पर फिल्म का ट्रेलर देखने वालों की संख्या एक लाख के आंकड़े को पार कर गई. गौरतलब हो कि इस फिल्म से क़ादर खान बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं. इस फिल्म में क़ादर खान के अलावा ओम पुरी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, रज्जाक ख़ान, विजय पाटकर और सुभाष यादव जैसे मंझे हुए कॉमेडियन हैं. इनके अलावा फिल्म में चित्रांशी रावत, अमिता नागिया, बंटी चोपड़ा, अमित जे, दानिश भट्ट, नेहा कराड आदि कलाकारों ने काम किया है, फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा है. यह फिल्म 25 सितंबर को रिलीज होगी.■

बजरंगी भाईजान ने किंग ख़ान को पीछे छोड़ा

बॉक्स ऑफिस की पटरी पर रफ्तार पकड़ चुकी सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए रोज नए–नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है. ईद पर रिलीज हुई दबंग खान की इस फिल्म ने महज 5 दिनों में शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया है. पहले वीकेंड यानी पहले तीन दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. इसके बाद भी लगातार वह बेहतरीन कारोबार कर रही है. शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस ने जहां फर्स्ट वीकेंड पर करीब 94 करोड़ रुपये की कमाई और शुरुआती 5 दिनों में करीब 118 करोड़ का कारोबार किया था. वहीं इसकी तुलना में बजरंगी भाईजान मानों सुपरफास्ट की स्पीड से इससे कहीं ज्यादा आगे निकल गई है और वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ की कमाई कर चुकी है. बजरंगी भाईजान ने एक सप्ताह में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 185 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और ओवरसीज 115 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. इसके साथ ही सलमान ने बाहुबली के 9 दिनों में 300 करोड़ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अपने ही कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं.■

करीना अभी मां नहीं बनना चाहती हैं

बेशक, मैं एक दिन मां बनूंगी लेकिन अगले दो तीन सालों में नहीं, इसके बारे में मैंने फिलहाल कुछ सोचा नहीं है. सैफ अली खान और करीना तकरीबन 5 साल तक प्रेम संबध में रहे.

पटौदी खानदान की बहु और फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर मां तो बनना चाहती हैं, लेकिन अभी नहीं. वह मां दो–तीन साल बाद बनना चाहती हैं. इस पर करीना ने कहा कि इस समय कोई योजना (बच्चे को लेकर) नहीं है और इसे लेकर मैं बहुत स्पष्ट हूं. बेशक, मैं एक दिन मां बनूंगी लेकिन अगले दो तीन सालों में नहीं. इसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं सोचा है. सैफ अली खान और करीना तकरीबन 5 साल तक प्रेम संबध में रहे. 5 साल संबध में रहने के बाद उन्होंने 2012 में शादी की. तब से लेकर अब तक करीना सभी तरह की फिल्मों में लगातार काम कर रही हैं. करीना ने कहा कि शादी होने के बावजूद उन्होंने व्यवसायिक फिल्मों सहित कई अच्छी और मनोरंजक फिल्मों का चुनाव किया है. संतुलन बनाना मुश्किल है. एक अभिनेत्री के रूप में सब कुछ करना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि जब वह अपने करियर में पीछे मुड़ कर देखती हैं तो अब तक के अपने फिल्मी सफर को लेकर गौरान्वित महसूस करती हैं.■

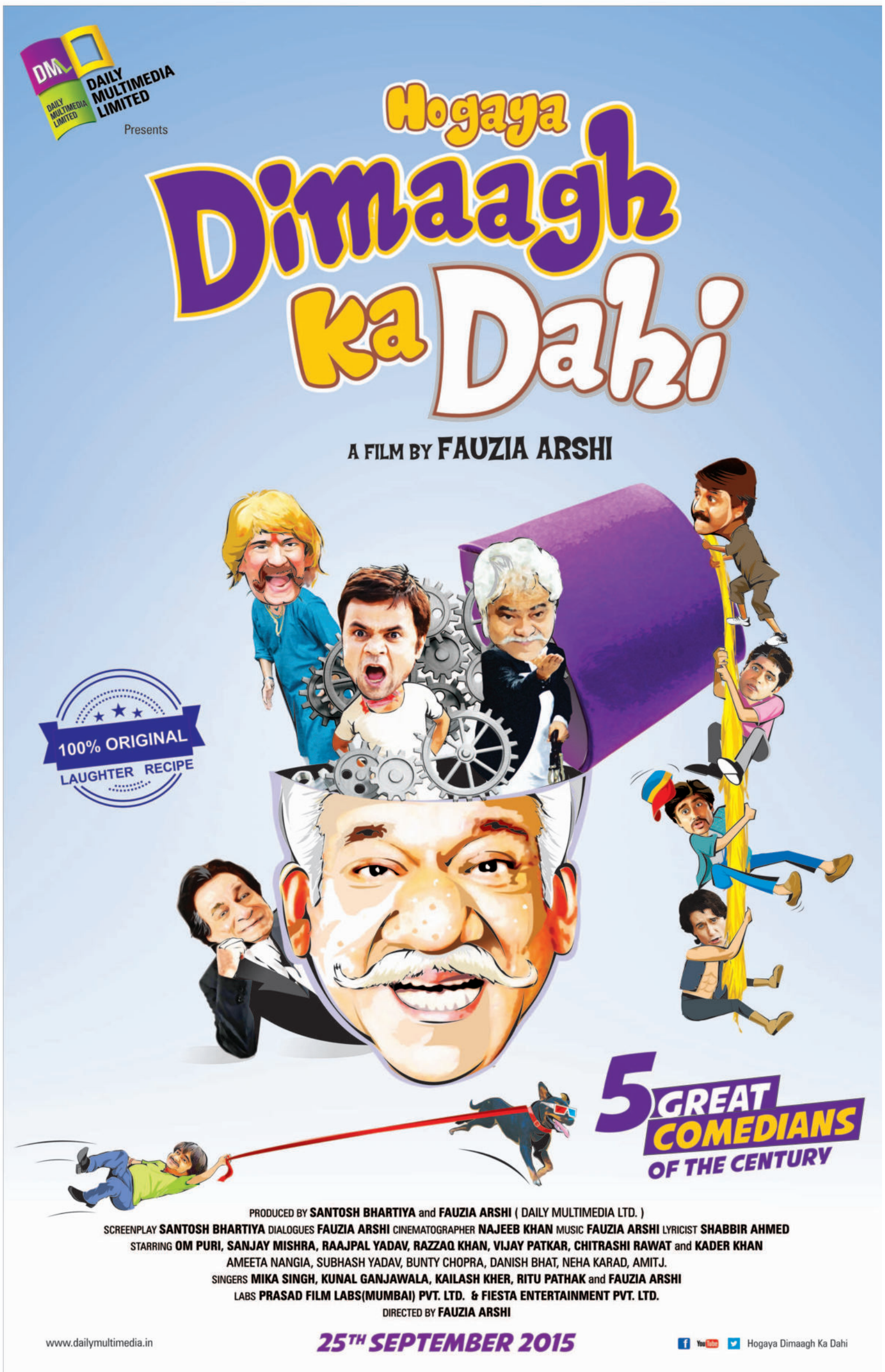

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

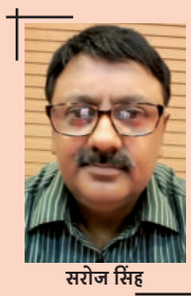

03 अगस्त-09 अगस्त 2015   Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

CRM
TMT BAR
ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178
भूकम्प रोधी
जंग रोधी

Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश
Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY
The Most Cost Effective Builder in India
4 से 50 लाख तक में घर
Customer Care : 080 10 222222
www.vastuvihar.org

राज रहा न ताज, क्या करे भूमिहार

सरोज सिंह

सत्ता की राजनीति वक्त के साथ बनती और बिगड़ती रहती है और इस दौरान न जाने कितनों का सितारा बुलंद होता है और न जाने कितने गर्दिश की दुनिया में चले जाते हैं. लालू-राबड़ी के शासन के ख़िलाफ या साफ तौर पर कहें तो तथाकथित जंगलराज के खिलाफ लड़ाई में नीतीश कुमार को सिर-माथे पर बिठाने वाला भूमिहार समाज आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है. 2005 में जब सुशासन की स्थापना के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार बनी तो एक नारा बड़ी जोर से उछला. नारा था कुर्मी को ताज और भूमिहार को राज. नीतीश कुमार की सरकार जैसे-जैसे रफ्तार पकड़ने लगी वैसे-वैसे भूमिहार समाज की हनक भी बढ़ने लगी. सत्ता से लेकर शासन तक भूमिहार समाज के लोगों का दबदबा अपना रंग दिखाने लगा और यह आभास कराने लगा कि ताज भले नीतीश कुमार के माथे पर है पर राज की बागडोर तो भूमिहार समाज के हाथ में है. कमोवेश बिहार की जनता और सामाजिक और राजनीतिक राय बनाने वाले लोगों ने भी यह स्वीकार कर लिया कि राज व ताज वाला यह समीकरण अब बिहार की सत्ता और शासन की हकीकत बन गया है.

डॉ. अरुण कुमार और ललन सिंह जैसे इस बिरादरी के बड़े नेता इस दौरान नीतीश से अलग हुए पर मौटे तौर यह राय कायम रही कि भूमिहारों का दबदबा बदस्तूर बना हुआ है. लेकिन इस मजबूत राय को करारा झटका लगना उस समय शुरू हुआ जब जदयू ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर लालू प्रसाद और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना डाली. इसके बाद यह संकेत मिलने शुरू हो गए कि राज पर भूमिहार बिरादरी की पकड़ कमजोर पड़नी शुरू हो गई है. सवर्णों साखकर भूमिहारों ने भाजपा को अपना मजबूत समर्थन जारी रखा. लेकिन नीतीश कुमार इस सच्चाई को नहीं भाप पाए और लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा. लोकसभा चुनाव में जदयू की करारी हार और भाजपा की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद नीतीश कुमार के रणनीतिकारों को यह साफ दिख गया कि भाजपा के अलग होने के बाद से ही भूमिहार समाज का अब पहले जैसा समर्थन जदयू के पक्ष में नहीं है. यहीं से बात उल्टी पड़नी शुरू हो गई. भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार के चुनाव को अगड़े और पिछड़े की लाइन पर ले जाना चाहते हैं. जातीय जनगणना के मामले में लालू प्रसाद तो मंडल पार्ट टू की बात करने लगे हैं. हुलास पांडेय को स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट नहीं दिया गया. बाहुबली विधायक अनंत सिंह और सुनील पांडेय की गिरफ्तारी ने इसको और बल दिया. यह तीनों जीतनराम मांझी को हटाकर नीतीश सरकार बनवाने में अगुवा रहे थे.

सबसे अधिक सुनील पांडेय की गिरफ्तारी हैरतंगेज़ है. विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होते ही उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है. सूत्र बताते हैं कि जिस चांद मियां और लंबू शर्मा जैसे अपराधियों के इक़बालिया बयान पर विधायक सुनील पांडेय को जेल में डाल दिया गया. उन्होंने अपने बयान में एक सांसद का भी नाम लिया है. इस पर राजद से निष्कासित बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने भी उंगली उठाई. उनका कहना है कि अपराधियों पर कार्रवाई में भेदभाव क्यों? अगर सुनील पांडेय पर आपराधिक आरोप है तो सांसद पर भी वही मामला बनता है. फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बताया जाता है कि उपरोक्त अपराधियों का संरक्षक उक्त सांसद एक ऐसी बिरादरी से आता है जिस समाज का मत महागठबंधन का मुख्य आधार वोट माना जाता है. उस पर कार्रवाई कर चुनाव के समय इस बिरादरी की नाराज़गी मोल लेने को दोनों दलों राजद-जदयू के नेतागण तैयार नहीं हैं. इससे स्पष्ट होता है कि जदयू और राजद के रणनीतिकार भूमिहार समुदाय को अपने ख़िलाफ उकसा कर वोट का जातीय गणित बदलने का मन बना चुके हैं. उनकी हार्दिक मंशा है कि भूमिहार जाति से आने वाले ऐसे आपराधिक छवि के नेताओं पर कार्रवाई कर अपने कानून के राज का इक़बाल स्थापित करने का प्रचार किया जाए. वहीं अगर इस जाति में इन कार्रवाईयों पर प्रतिक्रिया होती है तो इसे अगड़ा-पिछड़ा की लड़ाई में प्रचारित कर सियासी लाभ लिया जाए. यह रणनीति पहले से ही तय है. यही वजह है कि दोनों की गिरफ्तारी पर सबसे पहले लालू प्रसाद ने तत्परता के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी थी. मकसद स्पष्ट है.

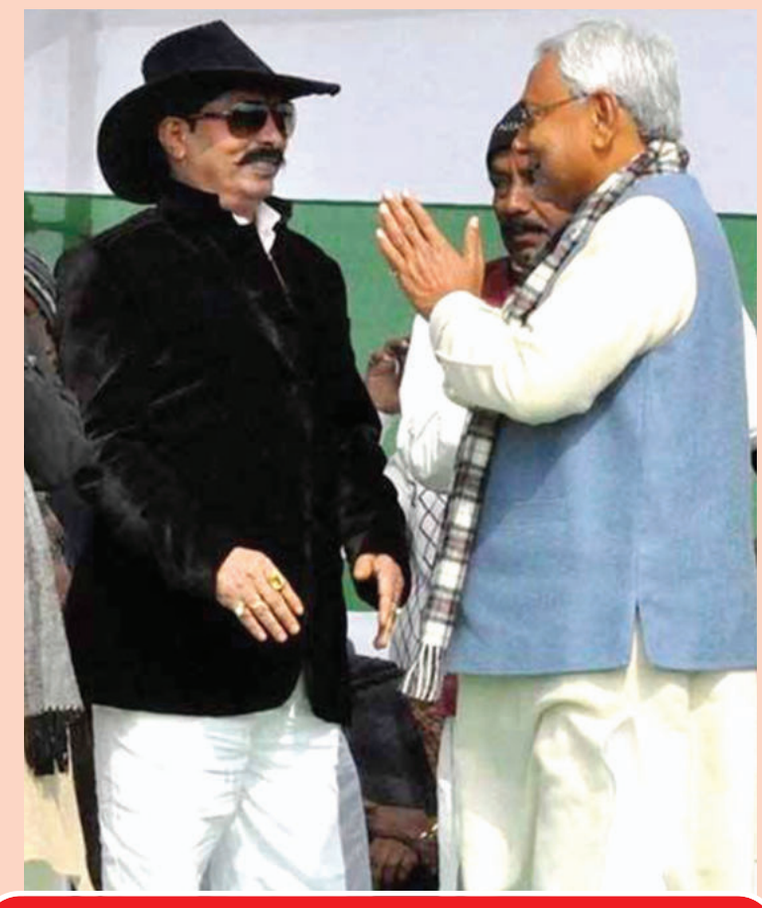

लोजपा में कभी बेहद सक्रिय रहे रोहित सिंह कहते हैं कि मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं पर पार्टी के लिए जी जान लगाने वाले कार्यकर्ताओं की अब कहां पूछ है? दुर्भाग्य से इस श्रेणी में भूमिहार बिरादरी से आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. एक जाति से समाज नहीं बनता पर कुछ

मंडल आंदोलन के पहले बिहार की ग्रामीण सत्ता पर भूमिहार बिरादरी का जबर्दस्त प्रभाव था. वहां से मिलने वाली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकत के बूते यह बिरादरी बिहार की सियासी दशा-दिशा तय करती थी. बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के उभार के दौर में वंचित समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण से उनका प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण होता चला गया.

सुनील पांडेय

सूरजभान सिंह

महाचंद्र प्रसाद

रोहित कुमार

अरुण कुमार

ललन सिंह

पी के शाही

नेता इस परिकल्पना को अपने राजनीतिक फायदे के लिए मजबूत करते रहे हैं. इसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम लेने से मुझे परहेज नहीं है.

हालांकि, जदयू के भूमिहार नेता ऐसा नहीं मानते हैं. पार्टी के बरबीघा विधायक गजानंद शाही उर्फ मुन्ना शाही मानते हैं कि आज भी इस तबके के लिए सबसे मुफीद राजनीतिक गठजोड़ महागठबंधन ही है. अभी लालू प्रसाद की पार्टी से एक भूमिहार उम्मीदवार संजय प्रसाद मुंगेर-जमुई-लखीसराय-शेखपुरा स्थानीय निकाय विधान परिषद सीट से जीते हैं. सभी दल के समर्थकों ने उन्हें जीत दिलाने में जी-तोड़ मेहनत की. लेकिन इस बात को पूरा सच नहीं माना जा सकता है. बारीकी से इन बातों को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना जरूरी है. मंडल आंदोलन के पहले बिहार की ग्रामीण सत्ता पर भूमिहार बिरादरी का जबर्दस्त प्रभाव था. वहां से मिलने वाली सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताकत के बूते यह बिरादरी बिहार की सियासी दशा-दिशा तय करती थी. मंडल के बाद बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के उभार के दौर में वंचित समुदाय के सामाजिक सशक्तिकरण से उनका ग्रामीण समाज पर प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण होता चला गया.

सामाजिक सत्ता के इस क्षरण के बाद तमाम हनक के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में पंचायतीराज व्यवस्था में एकल पदों पर आरक्षण के बाद उनके हाथ से बड़ी तादाद में गांव की सियासी कुर्सी निकल गई. इससे इस समुदाय में बड़ी बेचैनी काफी पहले से थी. लेकिन समय के साथ यह गुबार मजबूत हो गया. रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की आरा में हत्या और कई अन्य सियासी कदम से भूमिहार समाज का एक बड़ा तबका नीतीश कुमार से काफी ख़फ़ा हो गया. नाराज़गी का आलम यह था कि नीतीश कुमार ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद दो बार राज्यव्यापी यात्रा पर निकले पर, आरा अर्थात भोजपुर जिला नहीं जा सके. इसका स्पष्ट प्रभाव महाराजगंज उपचुनाव में देखने को मिला था. इसमें इस समुदाय के जदयू उम्मीदवार पीके शाही के चुनावी अखाड़े में होने के बावजूद भूमिहार बाहुल्य एकमा और गोरियाकोठी क्षेत्र में इस समुदाय का एक बड़ा तबका जदयू से दूर रहा. इस कारण इन क्षेत्रों में जदयू उम्मीदवार भारी मतों से पिछड़ गए. 2010 के चुनावोपरांत उनके बदलते मनोभाव का पहला प्रकटीकरण था. इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भूमिहार मतदाता सबसे मुखर होकर भाजपा और नरेन्द्र मोदी का समर्थन कर रहे थे. हालांकि, चुनावोपरांत केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार में बिहार से किसी भूमिहार को मंत्री नहीं बनाये जाने से नाराज़गी पैदा हुई थी. इसी समय विधानसभा उपचुनाव हुआ. इसमें दस में से छह पर महागठबंधन को जीत मिली. इस छह में दो विजयी उम्मीदवार इसी बिरादरी से आते थे. इसके बावजूद राजद-जदयू के रणनीतिकारों ने माना कि भाजपा के कथित सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब जातीय ध्रुवीकरण से ही दिया जा सकता है.

लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में भी यह समुदाय सत्ता में अवश्य हाशिये पर था. लेकिन, उस समय भी सियासत के केन्द्र में यही बिरादरी थी. लालू प्रसाद अथवा उनका कुनबा इस समाज पर मौखिक प्रहार कर अन्य पिछड़े, दलित आदि समुदाय को अपने पाले में गोलबंद करता था. उस समय भी लालू-राबड़ी शासन के ख़िलाफ निरंतर लड़ने-भिड़ने वाला समुदाय सिर्फ भूमिहार ही था. इस विरोध के बूते उसे जुझारू होने का तगमा मिला. हालांकि, इस समुदाय से आने वाले एकमात्र और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के विरोध में भी इस समुदाय के ही राजनीतिज्ञ लामबंद थे. उस समय समाजवादी नेता पूर्व मंत्री कपिलदेव सिंह, दुमका इलाके के कामदेव सिंह, बहुचर्चित मजदूर नेता बसावन सिंह, प्रख्यात साहित्यकार राजनीतिज्ञ रामवृक्ष बेनीपुरी, रामजन्म ओझा, कम्युनिस्ट नेताओं चंद्रशेखर सिंह, किशोरी प्रसन्न सिंह, कार्यानंद शर्मा, बागी कांग्रेसी रामचरित्र प्रसाद सिंह, प्रभुनारायण राय और महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह सदन और सड़क पर संघर्ष के बूते उनकी नाक में दम किए रहते थे. इस बिरादरी के बारे में एक और कहावत है- बिना पंख के उड़ाए, बिना लासा के सटाए , वहीं भूमिहार कहलाए. अर्थात यह समुदाय जनमत की दिशा तय करने में अहमतरीन किरदार अदा करता है. लिहाजा, निसंदेह नीतीश कुमार को बिना सियासी पंख के भी परवाज करवाने में इस समुदाय की बड़ी भूमिका रही. अर्थात, ऐसे में अगर इनमें नाराजगी फैलती है तो नफा होगा या नुकसान इसका आकलन बहुत मुश्किल नहीं है. वहीं एक पहलू यह भी है कि भूमिहार समुदाय के एकतरफा विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य समुदाय उनके पक्ष में गोलबंद भी हो सकते हैं. 1991 से 2004 तक लालू प्रसाद को इसका ही लाभ मिलता रहा था. हालांकि, गंगा में पिछले ढाई दशक में बहुत पानी बह चुका है. आज राजनीति के सिरमौर बनने की जंग पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित नेताओं के बीच है. 1991 के प्रतिक्रियावादी दौर के सबसे मुखर पिछड़े-अति पिछड़े दलित-महादलित नेता आज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजद-जदयू विराधी खेमे की शोभा बढ़ा रहे हैं. भूमिहार समाज तो सिर्फ सहायक की भूमिका में है. लेकिन यह समाज लड़ कर अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए जाना जाता है. इसलिए राज और ताज वाले नारे में खुद को फिट करने का अभियान जारी है.■

(साथ में अमित कुमार)

एक नज़र
चुनावी हलचल

धमदाहा में रालोसपा मजबूत : निरंजन

रालोसपा के युवा नेता निरंजन कुशवाहा ने कहा है कि धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है. पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह जनसम्पर्क कर गरीबों, अतिपिछड़े, अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच अपना मजबूत दावेदारी पेश की है, इससे एनडीए गठबंधन की जीत तय है.निरंजन ने आगे बताया की गरीबों,अतिपिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और दलितों को यहां केवल वोट देने की मशीन समझा जाता था. लेकिन रालोसपा के नेता व कार्यकर्ता इनकी आवाज बनने का काम किया है. पछले दो दशक से यह क्षेत्र जदयू एंव राजद के हाथों में रहा है.

रथ रवानगी पर हर्ष :वरुण

भाजपा का हाइटेक चुनाव प्रचार रथ रवानगी पर भाजपा के वरिष्ठ नेता वरुण सिंह ने खुशी जाहिर की है. एंव नरेन्द्र मोदी द्वारा विकास मॉडल सबका साथ सबका विकास की प्रशंसा की . वरुण ने कहा यह रथ समर्पित कार्यकर्ताओं के योगदान से बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में गांवों तक रवानगी हो रही है और रथ के माध्यम से आम जनता को संदेश भी दिया जा रहा है की बिहार के विकास के लिए बेहतर विकल्प है तो भाजपा ही सरकार है. सिंह ने कहा कि बिहार की आम जनता नरेंद्र मोदी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है. पूरी उम्मीद है कि बिहार एक बार फिर सुशासन के रास्ते पर आगे निकलेगा.
– रजनीकांत पाण्डेय

सबका विकास ही लक्ष्य

बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है गाँव में बसे अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाना. गांव की बेटियाँ प्राथमिक विद्यालयों से आगे नहीं बढ़ती थी लेकिन आज साइकिल योजना, पोषाक योजना, छात्रवृति योजना ने हमारी बेटियों को पंख लगा दिया है. उक्त बातें विगत दिनों महुआ के ऐतिहासिक कर्पूरी भवन में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में कही गयी श्रवण ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार केवल हवा में बात करती है हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है. सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एक जुट होकर साथ चलने के लिए भी कहा गया. गांव में चौक-चौराहे पर सरकार की उपलब्धियों को बारीकी से रखने तथा बताया गया कि लोग भूल भ्रम में न पड़ें. समारोह में जहानाबाद के पूर्व विधायक गणेश प्रसाद यादव ने भी अपने वक्तव्य रखे. उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता एक जुट होकर उम्मीदवार को विजयी बनाएं. इस कार्यक्रम में बाल श्रमिक आयोग के सदस्य अरुण कुमार वर्मा, वैशाली जिला के जदयू अध्यक्ष देव कुमार चौरसिया, संगठन प्रभारी अरविंद कुमार राय, पूर्व विधायक राजकिशोर सिन्हा, जिला युवा जदयू अध्यक्ष पंकज पटेल, प्रो. जनार्धन सिन्हा, वीरेंद्र कुमार सिन्हा, उपेन्द्र कुमार यादव, मुन्ना अंसारी, फुदन राय, असरफ अली, विनोद ठाकुर, उषा देवी, लालदेव कुशवाहा, दिलीप कुमार राय आदि ने सम्बोधित किया.■
नसीम रब्बानी

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

तनाव जीवन का हिस्सा पर घातक
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
आज के युग का सबसे बड़ा अभिशाप है मानसिक तनाव, भाग- दौड़ की जिन्दगी में मानसिक तनाव जीवन का एक हिस्सा बन गया है। ऐसे में तनाव से मुक्त जीवन एक कल्पना मात्र है, जब तनाव एक सीमा पार कर जाता है, तब हमारा मानसिक सन्तुलन बिगड़ता है और इसका असर शरीर पर भी होता है। मनोचिकित्सक डॉ बृज भूषण के अनुसार, कई कारण से मनोरोग होते हैं जैसे- चिन्ता, डिप्रेशन, डिसऑर्डर आदि इसके मुख्य कारण मानसिक तनाव है। कहीं शोरगुल वाली जगह पर काम करने से तनाव का कारण बनती है, तो कभी कुछ लोग को देर सुबह तक सोने के कारण से तनाव हो जाते हैं। तो कभी आस पास के बिगड़ते महौल से भी तनाव होता है ।
इसके आलावा खाने-पीने में बदलाव से भी जिन्दगी में तनाव हो जाता है। इनका हमारे स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है। डॉ बृज बताते है कि निरन्तर तनावग्रस्त बने रहना जीवन में हानिकारक है। चूँकि जीवन और उद्देश्य आपके सामने है, तनावग्रस्त से दूर रहना ही आपके लिए उतम होगा। अतः आप तनाव के बहुत से कारकों से बचें, जो आप आसानी से कर सकते हैं । काम को टालने की प्रवृत्ति से बचें, अगले सप्ताह में पड़ने वाले कार्यो की अग्रिम सूची बना लें, सूची के अनुसार कार्य करें। अपने पास उतना ही कार्य लें, जितना कि आप आसानी से कर सकें। बीच-बीच में अपनी मनपसंद गतिविधि जैसे-बागवानी, घूमना, मनपसंद खेल, टीवी देखना, संगीत समाचार, पत्र-पत्रिका वाचन, लेखन आदि कार्यो को करके आप तरोताजा महसूस करेंगे। चिंता करना छोड़कर हमेशा खुश रहें । तनाव अपने आप में अनेक बिमारियों और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। आगे बताया कि दो प्रकार से मनोरोग की इलाज की जाती है एक तो जीवनशैली से अवगत करा और दूसरा है दवाइयाँ इस रोग में डॉ ज्यादा तर नींद लगने और घबराहट की दवा देते है। ■
– रजनीकान्त पाण्डेय
डॉ. बृजभूषण K.G. Road ARA NEURO PSY.
URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

गुरारू विधानसभा क्षेत्र

टिकट के लिए दम लगा रहे हैं नेता

ऋषि लाल

बिंदी यादव

सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा

उजैर अहमद

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल और नेता तैयारियों में जुट गए हैं. वे जनता के बीच पहुंच रहे हैं. इसमें से कुछ नेता पटना से दिल्ली तक के बड़े से बड़े नेताओं के आगे-पीछे चक्कर लगाते दिख रहे हैं ताकि गुरारू विधानसभा क्षेत्र में उनकी सीट पक्की हो सके. गुरारू विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक भाजपा के सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा हैं. 2010 के चुनाव में दूसरे स्थान पर राजद उम्मीदवार विन्देश्वरी प्रसाद उर्फ बिंदी यादव थे. बिंदी यादव को पिछले चुनाव में 40 हजार मत प्राप्त हुए थे. लेकिन बिंदी यादव अब जदयू खेमे में हैं. इस कारण पूर्व जिला पार्षद उजैर अहमद खां की दावेदारी क्षेत्र में मजबूत देखी जा रही है. उजैर खां भी स्वर्गीय डॉ. शकील अहमद के भांजे हैं. जिले में राजद के एक ही मजबूत मुस्लिम नेता हैं और यहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 28 हजार है. ऐसे में इस बार उजैर अहमद खां की किस्मत खुल सकती है. उजैर 2010 विस चुनाव में रालोसपा के उम्मीदवार थे. इस बार गुरारू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के मौजूदा विधायक को पटकनी देने के लिए प्रमुख विरोधी गठबंधन राजद-जदयू के नेता अभी से ही रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं. इस सीट से डॉ. शकील अहमद को भाजपा के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देते रहे हैं. राजद यहां से तीन बार चुनाव जीत चुकी है. गुरारू विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को उम्मीदवार का चयन करने में खासी परेशानी हो रही है. उजैर अहमद खां कहते हैं कि गुरारू विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम समाज के वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. यहां अल्पसंख्यक वोटरों की संख्या 28 हजार है और जदयू-राजद गठबंधन के कारण यादव और मांझी वोट राजद उम्मीदवार के साथ है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मुझे संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने चुनावी मुद्दे पर कहा कि संगठित विकास एवं सबको सम्मान दिलाना मेरा पहले कर्तव्य होगा और इसके साथ ही क्षेत्र की विकास समस्या हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

जगदीशपुर को नए चेहरे की तलाश

मंगलेश तिवारी /आरा
feedback@chauthiduniya.com

चुनावी रंग धीरे-धीरे चढ़ने लगा है, जदयू के घर-घर दस्तक अभियान,केंद्रीय नेताओं के दौरे और विधान परिषद चुनाव में आये दिलचस्प नतीजों के कारण राजनीति गरमा गयी है. ऐसे में भोजपुर जिले में सबसे ज्यादा चर्चा जगदीशपुर सीट से उम्मीदवारी को लेकर हो रही है. आजादी के बाद शुरुआती दौर में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा फिर तीन बार निर्दलियों ने भी यहां बाजी मारी उसके बाद एक-एक बार लोकदल, इंडियन पीपुल फ्रंट (आईपीएफ), और समता पार्टी, जनता दल को भी जनता ने मौका दिया, लेकिन सन 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की लेकिन 10 वर्षो में जनता की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया. उसके बाद 2010 के विधानसभा भगवान सिंह नितीश की लहर में भी अपनी सीट बरकरार नहीं रख पाए थे उन्हें राजद के दिनेश ने बुरी तरह हराया था. जगदीशपुर विधानसभा में कुल 4,53,502 मतदाताओं में से पुरुष वोटर 1,50,054, तथा महिला वोटर 1,25,452, है. 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से फिरंगी हुकूमत थर-थर कांपती थी. लेकिन राजनीति के रहनुमाओं ने वीर बाकुड़ा की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही जगदीशपुर में उनके नाम पर सिर्फ राजनीति की हैं. यहीं कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी बाबू कुंवर सिंह की स्मृतियां अब भी उपेक्षित हैं. नेताओं को जब भी मौका मिलता है ऐतिहासिक स्थल जगदीशपुर किला के जीर्णोद्धार की मांग होती रही है. लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि उसके बाद जनप्रतिनिधि सबकुछ भूल जाते हैं. इसीलिए यहां के लोगों ने अबकी बार नए चेहरे को चुनने का मन बनाया है. यहां राज्य कला संस्कृति व युवा विभाग के अधीन संग्रहालय में चंद तस्वीरें व कुंवर सिंह की प्रतिमा तो लगा दी गयी, और इसे सरकार द्वारा सुरक्षित स्मारक भी घोषित कर दिया गया, लेकिन पर्यटन स्थल के रूप में इसका समुचित विकास नहीं हो पाया है. वर्ष 2003 में वीर कुंवर सिंह संग्रहालय व परिसर के सौन्दर्यीकरण के नाम पर करोड़ो रुपये स्वीकृत हुए. लेकिन सौन्दर्यीकरण के नाम पर किले में सफाई तक नहीं हुई. इस वर्ष एक बार फिर करोड़ो रुपये की राशि स्वीकृत हुई है पर शायद नेताओं को चुनाव की तारीख का इंतजार है. इसलिए अब तक राशि यथावत पड़ी है. वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि जगदीशपुर आज अपने विकास के लिए रो रही है. यहां ना ही शिक्षा की सही व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान दिया गया है. जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में पहले बक्सर ज़िले का भी एक हिस्सा शामिल था, लेकिन नए परिसीमन में इसका क्षेत्र पीरो की ओर बढ़ गया. नया परिसीमन बनने के बाद जदयू की टिकट पर निवर्तमान विधायक भगवान सिंह, राजद की टिकट से वर्तमान विधायक दिनेश और भाकपा माले से सुदामा प्रसाद चुनाव मैदान में थे. उस चुनाव में भगवान सिंह की हार हुई. उन्हें राजद के दिनेश ने दस हजार से भी ज्यादा मतों के अंतर से हराया भगवान सिंह कुशवाहा अब राजद के साथ है और 2014 में आरा संसदीय सीट से लोकसभा में भी असफल रह चुके हैं. इस महागठबंधन से जगदीशपुर इलाके से उनके राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है.

वहीं दूसरी ओर भाजपा गठबंधन का कोई ऐसा नेता इस इलाके में नहीं है जिसे भगवान या दिनेश के समक्ष मैदान में उतारा जा सके. इस क्षेत्र में राजपूत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है. दूसरे नंबर पर कुशवाहा हैं और तीसरे नंबर पर यादव मतदाता हैं. ऐसे में सीट की जातीय समीकरण को देखते हुए यहां से भाजपा गठबंधन के रालोसपा में शामिल हुए मशहूर शिक्षाविद कन्हैया सिंह को मैदान में उतारे जाने की भरपूर संभावना है. एक अनुमान के मुताबिक यहां राजपूत मतदाता इस बार निर्णायक साबित होंगे. वर्तमान विधायक राजद के भाई दिनेश यादव की जगह भगवान सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना तो है ही लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर जहां भगवान सिंह ने कहा कि पार्टी के आदेश का पालन करेंगे वहीं दिनेश ने भी कहा कि किसी भी परिस्थिति में वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे. और अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे. देखना यह दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में राजद की टिकट से चुनाव लड़ रहे भगवान सिंह को समर्थन नहीं किये जाने से नाराज राजद सुप्रीमो जगदीशपुर विधायक के साथ क्या सलूक करते हैं?■

पीपरा में होगी आर-पार की लड़ाई

राकेश कुमार

अरुण कुशवाहा

वी के राय

लव किशोर निषाद

सुभाष कुशवाहा

अवधेश कुशवाहा

2015 के आसन्न विधान सभा चुनाव में पीपरा विधान सभा से भाजपा में दावेदारों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सभी संशय में हैं कि सीट कहीं गठबंधन में न चली जाये. चुनावी धुरंधरों की मानें तो पूर्वी चम्पारण के ढाका और पीपरा विधान सभा क्षेत्र पर रालोसपा के दावेदार हैं लेकिन ढाका विधायक पवन जायसवाल के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद रालोसपा की दावेदारी पर कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं. भाजपा के दावेदारों में श्यामबाबू यादव, अरुण गुप्ता मौर्य, अरुण कुशवाहा, हरजीत सिंह राजू, अरुण गुप्ता, राधेश्याम यादव आदि का नाम आ रहा है.

पीपरा विधान सभा क्षेत्र तीन प्रखण्डों से बना है, जिसमें चकिया, मेहसी और तेतरिया शामिल हैं. पीपरा विधान सभा क्षेत्र शुरू से ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था. 2010 के चुनाव में यह सीट सामान्य हो गई. यहां के जनप्रतिनिधियों के इतिहास पर नजर डालें तो स्पष्ट होगा कि यहां किसी एक पार्टी वर्चस्व नहीं रहा है. 1972 एवं 1977 के चुनाव में सीपीआई के तुलसी राम विजयी हुए थे. 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस के नन्दलाल चौधरी एवं 1990 और 1995 के चुनाव में जनता दल के सहदेव पासवान ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. 2000 में राजद के सुरेन्द्र कुमार चन्द्रा उर्फ सतीश पासवान ने पीपरा सीट झटक ली. 2005 के चुनाव में फिर पासा पलट गया और भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण नन्दन पासवान जीते. अक्टूबर 2005 के उपचुनाव में कृष्ण नंदन पुनः विजयी रहे. 2010 में पीपरा विधान सभा क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र और हरसिद्धि को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित घोषित कर दिया गया. 2010 के चुनाव में जदयू के प्रत्याशी अवधेश कुशवाहा विजयी हुए.

2015 के आसन्न विधान सभा चुनाव में पीपरा विधान सभा से भाजपा में दावेदारों की भीड़ नजर आ रही है, लेकिन सभी संशय में हैं कि सीट कहीं गठबंधन में न चला जाये. चुनावी धुरंधरों की मानें तो पूर्वी चम्पारण के ढाका और पीपरा विधान सभा क्षेत्र पर रालोसपा दावेदार हैं लेकिन ढाका विधायक पवन जायसवाल के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद रालोसपा की दावेदारी पर कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं. भाजपा के दावेदारों में श्यामबाबू यादव, अरुण गुप्ता मौर्य, अरुण कुशवाहा, हरजीत सिह राजू, अरुण गुप्ता, राधेश्याम यादव आदि का नाम आ रहा है. वहीं रालोसपा से ललित कुमार सिंह, संत सिंह कुशवाहा दावेदार हैं. उधर लोजपा से डॉ. विपुल कुमार राय जोरदार तैयारी में हैं. महागठबंधन में राजद से सुबोध यादव चुनावी दंगल में कूदने की तैयारी में हैं तो जदयू से वर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद कुशवाहा हैं. जबकि जदयू से लवकिशोर निषाद भी चुनाव लड़ने की तैयारी में बताये जाते हैं.

भाजपा के श्यामबाबू यादव वर्तमान में स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह के प्रतिनिधि हैं. श्यामबाबू पीपरा कोठी क्षेत्र से दो बार जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं. दशकों से भाजपा के साथ रहे श्यामबाबू पार्टी के फैसले के अनुरूप काम करेंगे. वहीं विधायक अवधेश प्रसाद कुशवाहा को पराजित करने के संकल्प के साथ भाजपा नेता सुभाष कुशवाहा पीपरा से चुनाव की तैयारी में लगे हैं. उनका राजनीति में राजनीति का लम्बा अनुभव है. कुशवाहा बहुल पीपरा विधान सभा से गठबंधन से टिकट मिलने पर वे अपनी विजय सुनिश्चित मान रहे हैं. वहीं भाजपा से ही मेहसी निवासी अरुण कुमार मौर्य टिकट के दावेदार हैं. वे क्षेत्र की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं. भाजपा के ही अरुण कुशवाहा भी जोर आजमाइश कर रहे हैं. भाकपा से राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले पूर्व मुखिया अरुण कुशवाहा 2004 से ही भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं. 2005 के दोनों चुनाव में वे चुनाव प्रभारी रहे और दोनों ही बार पीपरा से भाजपा विजयी रही. बकौल अरुण कुशवाहा 2009 और 2014 के लोक सभा चुनाव में वे पीपरा के प्रभारी थे. दोनों चुनाव में पीपरा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मत मिले. अरुण कुशवाहा के अनुसार लोहे को लोहा ही काटता है. सीटिंग जदयू विधायक को वही हरा सकते हैं क्योंकि विधायक ने क्षेत्र के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया है. बाहरी होने के कारण जनता से हमेशा कटे रहे हैं. जबकि दशकों से क्षेत्र की जनता के बीच रहकर उनके सुख-दुख में साथ रहने के कारण उन्हें जमीनी नेता माना जाता है.

लोक जन शक्ति पार्टी के प्रबल दावेदार केशरिया के डॉ. विपुल कुमार राय हैं. एसके यादव डिग्री कॉलेज केशरिया के सचिव डॉ. वीके राय लोजपा की नैया पर सवार होकर वैतरणी पार करना चाहते हैं. डॉ. यादव क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं. केशरिया को अनुमंडल बनाने की मांग क्षेत्र की चिरपरिचित मांगों में से एक रही है. इसे लेकर आंदोलन से वे जुड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि टिकट मिलता है तो जीत सुनिश्चित है. क्षेत्र में यादवों की बड़ी संख्या है और गठबंधन के घटक दलों का सहयोग मिलेगा ऐसे में चुनाव जीतना आसान होगा. महागठबंधन के टिकट के दावेदार कांग्रेस नेता कमलेश्वर गुप्ता भी चुनावी समर में कूदने को तैयार हैं. स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त कमलेश्वर ने राजनीतिक सफर कम्यूनिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया. उनकी पत्नी अनिता गुप्ता दो बार वार्ड पार्षद रहीं है और एक बार पंचायत समिति सदस्य चुनी गई. वे बिजली यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं. मेहसी बीडी यूनियन के 20 वर्षों तक अध्यक्ष थे. वहीं भावी प्रत्याशी लव किशोर निषाद अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं. वे निषाद वर्तमान में जिला 20 सूत्री के सदस्य हैं.

क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों की है. पीपरा विस क्षेत्र में स्थित चकिया चीनी मील बन्द होने से यहां के किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. यहां के किसानो का एक मात्र कैश क्राप गन्ना है, लेकिन मील की बन्दी के कारण किसानो की माली हालत खराब है. वर्तमान विधायक अवधेश कुशवाहा बिहार सरकार के गन्ना मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन मील को शुरू कराने के लिए कोई सार्थक कार्यवाई नहीं कर सके. जिससे क्षेत्र के किसानों में नाराजगी है.■

feedback@chauthiduniya.com

महागठबंधन का लहराया परचम, भाजपा हुई परास्त

वाल्मीकि कुमार

बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव के रूप में पिछले 7 जुलाई को हुआ. निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में 10 जुलाई को मतगणना कार्य संपन्न हो गया. सीतामढ़ी-शिवहर स्थानीय निकाय से मुख्यतः तीन प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतरे थे. इनमें एनडीए गठबंधन से डुमरा प्रखंड प्रमुख देवेंद्र साह और महागठबंधन से दिलीप राय एवं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चर्चित कथा वाचक आचार्य सुदर्शन जी महाराज के पुत्र अमिताभ गुंजन उर्फ चुन्नू शामिल थे. चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी दिलीप राय ने बाजी मार ली. नतीजे के मुताबिक राजद महागठबंधन के दिलीप राय ने 2 हजार 467 मत लाकर जीत हासिल कर ली, जबकि भाजपा गठबंधन के देवेंद्र साह को महज 1 हजार 651 मत से ही संतोष कर दूसरे पायदान पर अटक जाना पड़ा. नव निर्वाचित प्रतिनिधि ने जीत पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जिले के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ ही महागठबंधन दल के नेताओं को धन्यवाद दिया है.

अभिवादन करते दिलीप राय

बधाई देने पहुचे नेतागण

चुनाव परिणाम की घोषणा होने के साथ ही जिले में भाजपा गठबंधन प्रत्याशी की पराजय को लेकर राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ने लगी है. कोई इसे पार्टी के अंदर चल रहा अंतर्कलह तो कोई प्रत्याशी की उदासीनता को हार का कारण बता रहा है. चर्चा चल रही है कि निवर्तमान विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद को पूर्व नियोजित साजिश के तहत चुनाव से किनारे किया गया. साथ ही पूर्व नियोजित योजना के अनुसार प्रमुख को बतौर मजबूत पार्टी प्रत्याशी के रूप में प्रदेश नेतृत्व के समक्ष पहुंचा दिया गया. पार्टी नेतृत्व ने चुनावी किला फतह करने की नियत से हरी झंडी दे दी. बाद में चुनावी मरहम लगाते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडेय ने सीतामढ़ी शहर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बैद्यनाथ प्रसाद को विधानसभा प्रत्याशी बनाये जाने की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जीताने की अपील की. परंतु प्रत्याशी का रवैया कार्यकर्ताओं को रास नही आया. बताया जाता है कि प्रत्याशी श्री साह नामांकन दाखिल करने के साथ ही संपन्न लोकसभा चुनाव जैसा हालात बनने और अपनी जीत होने के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो गये. न तो कार्यकर्ताओं के फोन को तरजीह दिया और न ही जमीनी कार्यकर्ताओं से खास मतलब रखा. मगर अपने स्तर से मतदाताओं के बीच वह सब कुछ किया जो विधान परिषद चुनाव के लिए अब तक चर्चित रहा है. मतलब कि वोटों की खरीद-फरोख्त के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी.

अब एक सवाल उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी आखिर चुनाव परिणाम ऐसा आया कैसे ? क्या जातीय सरगनाओं के फरमान को पंचायत प्रतिनिधियों ने एक सिरे से खारिज कर दिया ? इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि चुनावी सौगात मंजिल तक पहुचने से पहले ही रास्ता भटकती गयी. चंद चुनिंदे चेहरे दोनों हाथों से माल बटोरने में ही लगे रहे. इसका फायदा विरोधी दल के प्रत्याशी ने उठाने में फूर्ति दिखायी. नतीजा पार्टी गठबंधन की पराजय के रूप में अब सामने है.जहां तक जिले में पार्टी नेताओं की चुनावी सजगता का सवाल है तो कार्यकर्ताओं को तिरहुत स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद देवेशचंद्र ठाकुर के भाजपा में शामिल होने का भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद थी. निवर्तमान विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद भी चुनाव अभियान में लग कर प्रत्याशी को जीत दिलाने का प्रयास करते रहे. परंतु बेटिकट होने के कारण इनके तमाम प्रयास को अब दूसरे नजरिये से तौला जा रहा है. परंतु अब बारी विधानसभा चुनाव की है. अगर राजनीतिक प्रतिशोध की चिंगारी पार्टी के अंदर किसी कोना में सुलग रही होगी तो इसका विस्फोटक रूप विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है. संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा हुआ तो जिला से भाजपा का सफाया की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

चौबीसों घंटे का सेवक हूं : सुभाष

नंदन निराला

विधान सभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं. एक ओर जहां पूर्व प्रत्याशी अपने टिकट को पक्का करने में लगे हैं वहीं दूसरी तरफ नए लोग टिकट की दावेदारी का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. जमुई जिले के सिकंदरा विधान क्षेत्र में भी इन दिनों यही हाल है.

लोजपा के पूर्व प्रत्याशी सुभाष पासवान भी टिकट के लिए रात दिन एक किए हुए हैं. पार्टी के बड़े नेताओं का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है. लगातार अपने क्षेत्र में दमदार उपस्थिति के कारण भी सुभाष पासवान पार्टी में अन्य लोगों से बेहतर छवि बनाने में सफल रहे हैं. इसी सिलसिले में सुभाष पासवान से हमारी बातचीत हुई. टिकट बंटवारे के संबंध में उन्होंने कहा की पार्टी के त्रिमूर्ति यानि रामविलास पासवान, पशुपति कुमार पारस एवं चिराग पासवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है. चुनाव से संबंधित सारी तैयारी भी उन्होंने कर ली है. वे चुनाव का बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लंबे समय से मैं क्षेत्र की जनता की सेवा में लगा हूं. चुनाव हार जाने के बावजूद लगातार क्षेत्र में लोगों के बीच रहकर उनकी सेवा की है. आजादी के इतने सालों बाद भी सिकंदरा का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था.

आज भी कई गांव के लोग सड़क, बिजली आपूर्ति और स्वच्छ पेय जल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. उनकी सुनने वाला कोई नहीं है. वर्तमान विधायक रामेश्वर पासवान के कार्यकाल के बारे पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक तो कभी जनता के बीच जाते ही नहीं हैं. शायद उन्हें पता भी नहीं है कि किस इलाके में लोगों को क्या परेशानी है. दस वर्षों में उन्होंने जनता के विकास के जगह केवल अपना विकास किया है. यही कारण है कि उन्हें अपने ही पार्टी से टिकट मिलने के लाले पड़ गए हैं. क्षेत्र की जनता ने कुशासन को भुगता है. इसलिए जनता मुझ पर भरोसा करेगी, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है. मैं जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा.

आत्मविश्वास से लबरेज सुभाष से जब पूछा गया कि क्षेत्र में जनता के विकास के लिए आपने कौन-कौन सी योजनाएं बनाई हैं तो उन्होंने बताया कि अगर जनता मुझ पर विश्वास कर अपना सेवक चुनती है तो मेरे दिमाग में उनके लिए कई बेहतरीन योजनाएं हैं जो क्षेत्र का कायाकल्प कर सकती हैं. मूलभूत सुविधाओं का विकास तो किया ही जाएगा. मैं उन सारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसकी वह वाज़िब हक़दार है.

जनता को धोखा देने वाले नेताओं को समझाने के लिए क्षेत्र की जनता तैयार बैठी है. उन्होंने कहा कि पूर्व के नेताओं ने यहां जाति धर्म के नाम पर नफ़रत की राजनीति कर वोट प्राप्त किए हैं, लेकिन इस बार जनता जाति-धर्म-मज़हब से ऊपर उठकर विकास पर वोट देगी.■

feedback@chauthiduniya.com

चुनावी हलचल

केंद्र कर रहा सौतेला व्यवहार

बिहार विरोधी नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के तहत सीतामढ़ी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में एक दिवसीय धरना व उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डॉ अंबेदकर स्मारक स्थल पर जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर भडास निकाली. जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की योजनाओं में कटौती कर सौतेलापन व्यवहार कर रहे है. कार्यक्रम में उपाध्यक्ष सीताराम झा, सत्येंद्र कुमार तिवारी, परवेज आलम अंसारी, राज कुमार साह, संजय ठाकुर, महेश्वर गिरी, सुनील कुमाल सुमन, मो शाहनवाज, मो आलमगीर, संजय कुमार, मोहन गुप्ता, वीरेंद्र कुशवाहा, पप्पू प्रवीण, मणिभूषण कुमार, नागेश्वर तिवारी, मो नन्हे अंसारी, छोटन सिंह, कमलेश तिवारी, जयकृष्ण पूर्वे व विजेंद्र यादव समेत अन्य लोग शामिस थे.

जति जनगणना सार्वजनिक करे केंद्र

शिवहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में समाहरणालय मैदान में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया. मौके पर जिलाध्यक्ष मो. असद ने केंद्र सरकार पर बिहार के प्रति नांसाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जाति जनगणना सार्वजनिक करना चाहिए. उन्होंने कहा कि 18 योजनाओं में कटौती के कारण विकास योजनाओं पर ग्रहण लग रहा है. कार्यक्रम में बालदेव प्रसाद, मुरली मनोहर सिंह, निलय कुमार राहुल सिंह व सद्दाम हुसैन समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे.
– विकास

टॉपर रंजन व सौरभ सम्मानित

सीतामढ़ी शहर स्थित रेडक्रास के सभागार में स्मृति शेष मां झरिया देवी, सह बनारसी देवी, मेमोरियल स्कॉलरशिप के तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. मौके पर मैट्रिक का जिला टॉपर रंजन कुमार व सेंटर विज्ञान का टॉपर सौरभ कुमार को क्रमशः 51 सौ व 55 सौ प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया. समारोह के आयोजक प्रो डॉ विजय कुमार ने बताया कि अपनी माताजी की स्मृति में प्रति वर्ष जिले के दो टॉपर को सम्मानित करने का निर्णय लिया है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रजापिता ब्रहमा कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की संचालिका वंदना वहन के अलावा प्रो राज कुमार गुप्ता, नवल किशोर मिश्र व चंद्रकला देवी समेत अन्य लोग भी मौजूद थे. समारोह के द्वितीय सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया. मौके पर गीतकार गीतेश, सत्येंद्र मिश्र, जितेंद्र झा, आजाद, रामबाबू सिंह, सुरेश वर्मा समेत अन्य ने अपनी रचनाए प्रस्तुत की. इस मौके पर राजेश कुमार गुप्ता, धनंजय सिंह, प्रो प्रभुनाथ व डॉ विश्वनाथ बाजोरिया समेत अन्य लोग मौजूद थे.
– आदित्यानंद

अराजकता अपने चरम पर

पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में जिरादेई के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राघव प्रसाद ने बिहार में बढ़ती अराजकता और वर्तमान सरकार को पुनः सत्ता में नहीं लाने की मांग करते हुए कहा कि यह सरकार जनता को भूलावे में रखकर लगातार शोषण कर रही है. वहीं उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है. तो बिहार की जनता का विकास संभव है. इससे पहले भी एनडीए के बदौलत बिहार में विकास और सुशासन आया है. जनता की मांग को लेकर उन्होंने पुनः चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है. गौरतलब है कि बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से 2015 में वो विधान चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं.■
– चौथी दुनिया ब्यूरो

एक नज़र
चुनावी हलचल

जनता के सपने पूरे करूंगा

भाजपा के युवा नेता और फिल्म जगत के चर्चित चेहरा सुजीत पूरी मांझी विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार प्रत्याशी माने जा रहे हैं. जनता से निस्वार्थ कार्य को लेकर लगातार प्रयासरत रहे हैं. सुजीत ने अपने सपनों को छोड़कर जनता के बीच चुनाव लड़ने की दावेदारी की है. इनका मानना है कि सभी नेता बनने के बाद जनता को लूट कर अपना घर भरा करते हैं. सुजीत पूरी ने बताया कि मैं जनता के बीच अपने सपनों का बलिदान कर उनके सपनों का पूरा करना चाहता हूं. सुजीत लोगों के बीच जा कर अभी तक लोगों का खूब भरोसा जीता है. सुजीत का कहना है कि पूरे क्षेत्र में जनता की समस्या सुन रहा हूं और यथासंभव इससे समाधान का प्रयास कर रहा हूं . मुझे उम्मीद है कि जनता अपना आशीर्वाद देगी.

मंगलराज कायम करेंगे : मनोज

हम के युवा व कर्मठ नेता मनोज कुमार सिंह ने बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र को जंगलराज से मंगलराज तक ले जाने की बात कही है. मनोज की सोच को लेकर समाज और क्षेत्र में मजबूत पकड़ देखी जा रही है. समाज के बीच लगातार अपनी सेवा दे रहे मनोज ने कहा की जनता को सुख शांति और विकास की ओर ले जाने में अपनी भागीदारी करना अतरिक्त देता है. मनोज सिंह को लगता है कि क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति में कदम रखना जरूरी है. मनोज अखिल भारतीय क्षेत्रीय समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. मनोज अपने वर्गों के लोगों के साथ-साथ क्षेत्र के सभी वर्गों के लिए सक्रिय रहें है . बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता मनोज को आशा भरी निगाहों से देख रही है. आम जनता को उम्मीद है की बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में मनोज विकास की नई हवा बहेंगे.
–दिव्या त्रिपाठी

सुदर्शन जदयू को मजबूती देंगे

आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व पार्टी संगठन को और अधिक मजबूत एवं गतिशील बनाने के लिए जदयू ने मनोनीत किया बेगूसराय जिला का कार्यकारी कप्तान, सुदर्शन सिंह बनाए गए पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष, सिंह को राजनीति का लम्बा अनुभव है. इनमें गजब की सांगठनिक क्षमता है. गत विधानसभा चुनाव में चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सम्मानजनक वोट प्राप्त किया था. सुदर्शन सिंह का मुख्यमंत्री नितीश कुमार एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से काफी अच्छा राजनीतिक संबंध है. सिंह पार्टी नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को अपना राजनीतिक गुरू मानते हैं. सुदर्शन सिंह कहते हैं कि पार्टी नेतृत्व ने उनपर जो विश्वास किया है इसपर वे शत-प्रतिशत खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे.
– सुरेश चौहान

विकास पुरुष हैं नीतीश कुमार

सीतामढ़ी जिले के रून्नीसैदपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित विधायक गुडडी देवी के आवासीय परिसर में जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. मौके पर पूर्व सांसद मीना सिंह, नवल किशोर राय, गन्ना मंत्री डॉ रंजूगीता समेत अन्य राज्य सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. कहा कि केंद्र सरकार नितीश कुमार के विकास की पटरी पर अपना चुनावी रथ दौड़ाने की मंशा पाल रखी है. इसे सूबे की जनता चलने नही देगी. स्थानीय जदयू विधायक गुडडी देवी ने कहा कि बिहार में विकास को गति देने के कारण ही नितीश कुमार जन-जन के बीच विकास पुरूष के रूप में अपनी छाप छोडने में कामयाब रहे है. अगले चुनाव में विरोधी चाहे जितनी ताकत लगा ले आम-आवाम नितीश कुमार को एक मौका पुनः देने की ठान ली है. मौके पर बरिष्ठ जदयू नेता राजेश चौधरी, किरण गुप्ता, प्रो अमर सिंह, जिलाध्यक्ष रामजीवन प्रसाद, शोभा देवी समेत अन्य लोग मौजूद थे.
– विभा सिन्हा

प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अंकगणित के महत्वपूर्ण प्रश्न

सुबोध कुमार, Director
S.T.C., Motihari

31. यदि किसी संख्या के 2/9 भाग का मूल्य 2200 रू. है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है?
A) 900 B) 1800 C) 2700 D) 400

32. किसी छात्र को एक संख्या का 1/15 ज्ञात करना था लेकिन उसने 1/3 ज्ञात कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर पहले से 16 अधिक आया संख्या ज्ञात करें ?
A) 80 B) 60 C) 75 D) 90

33. एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 प्राप्त करने के लिए कहा गया परन्तु गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। इस प्रकार उसका उत्तर पहले से 150 अधिक था। तो संख्या ज्ञात करें ?
A) 180 B) 240 C) 280 D) 290

34. किसी संख्या में 8/17 से गुणा करने के अपेक्षा 8/17 से भाग देने पर परिणाम पहले से 225 अधिक प्राप्त होता है तो संख्या क्या थी ?
A) 132 B) 135 C) 136 D) 138

35. 70 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या, दूसरी संख्या का 2/5 भाग है, तो छोटी संख्या क्या है ?
A) 20 B) 30 C) 10 D) 40

36. पानी का एक ड्रम 3/5 भाग भरा है। जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है, तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है, तो ड्रम की क्षमता क्या है ?
A) 60 लीटर B) 65 लीटर C) 75 लीटर D) 80 लीटर

37. एक खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में, 3/10 भाग पानी में तथा 3 मीटर सतह के ऊपर है तो खंभे की ऊँचाई क्या है ?
A) $4\frac{1}{2}$ मीटर B) 4 मीटर C) 13 मीटर D) इनमें से कोई नही

38. एक पर्यटक टीम अपनी यात्रा का 1/3 भाग नाव से 4/15 भाग ट्रेन से 1/15 भाग बस से तथा शेष 7200 मीटर पैदल पूरा करती है तो कुल दूरी ज्ञात करें?
A) 21600 मीटर B) 20600 मीटर C) 20800 मीटर D) 21400 मीटर

39. एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपनी चार पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुण्ड की आधी गायें, दूसरे पुत्र को पूरे झुण्ड की 1/4 भाग गायें, तीसरे पुत्र को पुरे झुण्ड की 1/5 भाग गायें तथा चौथे पुत्र को शेष 7 गायें मिलती हैं तो n का मान क्या है?
A) 80 B) 100 C) 140 D) 180

40. एक व्यक्ति के पास 60,000 रू. है। वह $16\frac{2}{3}$ % धन अपने बड़े पुत्र को 1/4 भाग छोटे पुत्र को और शेष धन पुत्री को देता है तो पुत्री को कितना धन दिया ?
A) 35,000 B) 25,000 C) 20,000 D) 45,000

सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले प्रथम दस विजेताओं को पुरस्कृत किया जायेगा। SMS द्वारा उत्तर 8002817092 पर भेजें
शेष अगले अंक में

चेरियाबरियारपुर विधानसभा

समाजवादियों के गढ़ में मचेगा घमासान

अनिल चौधरी

मंजू वर्मा

संजू प्रिया

उर्मिला ठाकुर

सुदर्शन सिंह

सतीश कुमार

चेरियाबरियारपुर विधानसभा सीट जदयू के पास है और मंजू वर्मा यहां की विधायक हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू गठबंधन यदि यह सीट जदयू को देता है तो वर्तमान विधायक मंजू वर्मा केअलावा पूर्व सांसद राजवंशी महतो, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सावित्री रंभा वर्मा, पंकज सिंह एवं सुदर्शन सिंह प्रत्याशी के प्रमुख दावेदार होंगे. पिछले दिनों क्षेत्र में कुशवाहा महासम्मेलन का सफल आयोजन कर रंभा वर्मा अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दे चुकी है.

सुरेश चौहान/पंकज झा

आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादियों के गढ़ चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन को एनडीए गठबंधन से खुली चुनौती मिलने के आसार हैं. चेरियाबरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में आजतक समाजवादी पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी ही विजयी होते आए हैं.वर्तमान में इस सीट पर जदयू का कब्जा है. मंजू वर्मा यहां की विधायक हैं. गत विधानसभा चुनाव में जदयू के साथ भाजपा थी. इस बार जदयू के साथ राजद एवं कांग्रेस हैं. दूसरी ओर भाजपा के साथ लोजपा एवं रालोसपा हैं. दोनों गठबंधन का क्षेत्र में मजबूत जनाधार है. इसलिए यह मुकाबला रोमांचक होगा. एक ओर जदयू गठबंधन अपनी वर्तमान सीट को बरकरार रखने के लिए सारी शक्ति लगा देगी. दूसरी ओर भाजपा गठबंधन इस सीट को प्राप्त करने के लिए सारी ताकत झोंक देगी. पार्टी नीति सिद्धान्त एवं विकास से इतर जातीय समीकरण चुनाव परिणाम को प्रभावित करेंगा.

चेरियाबरियारपुर विधानसभा सीट जदयू के पास है और मंजू वर्मा यहां की विधायक है. आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू गठबंधन यदि यह सीट जदयू को देता है तो वर्तमान विधायक मंजू वर्मा के अलावा पूर्व सांसद राजवंशी महतों, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सावित्री रम्भा वर्मा, पंकज सिंह एवं सुदर्शन सिंह प्रत्याशी के प्रमुख दावेदार होंगे. पिछले दिनों क्षेत्र में कुशवाहा महासम्मेलन का सफल आयोजन कर रंभा वर्मा अपनी सांगठनिक क्षमता का परिचय दे चुकी है. इस महती सम्मेलन में पार्टी नेता नितीश कुमार और मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सहित अनेक नेताओं ने शिरकत की वहीं राजवंशी महतों सावित्री देवी, अनिता देवी, पंकज सिंह जदयू के निष्ठावान एवं समर्पित सदस्य हैं. सुदर्शन सिंह पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष है. जिले के सर्वाधिक महत्वाकांक्षी नेता के रूप में इनकी पहचान है. दल-बदल का रिकॉर्ड इनके नाम है. विधायक बनने की ललक में भाकपा (माले), लोजपा, राजद, भाजपा, कांग्रेस, रालोसपा से सफर करते हुए फिलवक्त जदयू की शरण में हैं. कांग्रेस में रहते हुए बागी बनकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. जदयू नेता एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनकी निकटता है. यदि गठबंधन कि यह सीट राजद को देता है तो राधाकृष्ण सिंह, उर्मिला ठाकुर एवं ब्रजनन्दन यादव में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता हैं. यदि यह सीट कांग्रेस को मिलता है तो पूर्व जिला महासचिव सतीश कुमार वीरू, पूर्व जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र महतों एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राम प्रवेश महतों में से कोई भी प्रत्याशी बनाया जा सकते हैं. सतीश कुमार वीरू को कांग्रेस की राजनीति पिता मदन मोहन प्रसाद सिंह एवं चाचा ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह से विरासत में प्राप्त हुई है.

दूसरी ओर भाजपा-लोजपा-रालोसपा गठबंधन जदयू गठबंधन को देने की स्थिति में है. रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एवं लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान की प्राथमिकता सूची में चेरियाबरियारपुर विधानसभा सीट हैं. भाजपा के दोनों घटक दलों की पैनी नजर इस विधानसभा सीट पर हैं. यदि यह सीट रालोसपा को मिलती है तो पार्टी के तेज-तर्रार प्रदेश महासचिव संजू प्रिया मुख्य दावेदार होंगी. यदि यह सीट लोजपा के खाते में जाती है तो अनिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाना तय हैं. ये क्षेत्र के पूर्व विधायक है. अनिल चौधरी सम्प्रति लोजपा के प्रदेश संसदीय दल के अध्यक्ष हैं.

जिले में वह बेदाग छवि वाले नेता माने जाते हैं. यदि यह सीट भाजपा को मिलती है तो पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम सुमिरन सिंह सूबे के पूर्व मंत्री अशोक कुमार महतों एवं अनिल कुमार सिंह में से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता हैं. ये सभी जमीन से जुड़े नेता हैं. माकपा-भाकपा (माले) गठबंधन भाकपा के भुवनेश्वर सहनी या राम पदारथ सिंह में से किसी को चुनाव मैदान में उतार सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

बेनीपुर में विकास बनेगा मुद्दा

कुमार विनोद/ जयशंकर वर्मा

दरभंगा संसदीय क्षेत्र में बेनीपुर क्षेत्र कभी कांग्रेस का गढ़ था. बिहार में कांग्रेस की स्थिति कमजोर होने के बाद इस क्षेत्र में राजद का प्रभाव रहा लेकिन परिसीमन के बाद बेनीपुर विधानसभा का निर्माण हुआ. इससे पहले बहेड़ी विधानसभा के अंतर्गत बेनीपुर आता था. 2010 में विधानसभा में भाजपा नेता गोपाल जी ठाकुर यहां से जीतकर पहुंचे. इस बार के विधानसभा चुनाव में परिदृश्य अलग है. पिछले चुनाव में भाजपा-जदयू ने मिलकर चुनाव जीता था. नीतीश के व्यक्तित्व का भी लाभ मिला और भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का व्यक्तित्व भी काम आया. लेकिन इस बार रास्ता आसान नहीं है.

जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा की कर्मभूमि बेनीपुर ही रहा है. संजय झा पिछले लोकसभा में भले ही हार गये थे

हरेकृष्ण यादव

गोपाल जी

संजय झा

लेकिन उन्होंने अपनी उपस्थिति जबरदस्त रूप से दर्ज करायी थी. अपने कार्यकाल के बारे में गोपाल जी ठाकुर का कहना है कि बेनीपुर अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र था. जर्जर सड़कों के कारण लोग इस क्षेत्र में आना नहीं चाहते थे. लेकिन अब पहले के बेनीपुर और आज के बेनीपुर में आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं. जनता समझती है कि अपना बहुमूल्य मत किसे दे. गोपाल जी ने कहा कि हमारे पास जनता के पास जाने का एक मात्र आधार विकास है. हम जातिगत आधार पर राजनीति नहीं करते. इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सम्पर्क सड़क, पुल पुलिया का निर्माण या पीएचईडी का काम एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में काम किया गया है.

गोपाल जी ठाकुर ने बताया कि समाज का आईना शिक्षा होती है. इसलिए शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया. 2 करोड़ 77 लाख की लागत से उच्चतर माध्यमिक जयानंद उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल का स्वरूप दिया जा रहा है. उच्च विद्यालय महीनाम, नवादा, बहेड़ा और बन्दा में एक करोड़ 15 लाख की लागत से भवन का निर्माण किया गया है. 58-58 लाख की लागत से उत्क्रमित उच्च विद्यलाय रढ़ियाम, विजुलिया, रामौली, कोयलाजान और अम्बा बिजुलिया में भवन का निर्माण किया गया. किसानों के विकास के लिए बेनीपुर प्रखंड में ई-किसान भवन का निर्माण किया गया. बहेड़ी में ई-किसान भवन का 1.20 लाख की लागत से निर्माण के लिए टेंडर किया गया है. बिरौल प्रखंड के देकुलीधाम में 34 लाख की लागत से राइस मिल का निर्माण किया गया. एक करोड़ की लागत से बहेड़ी में थाना भवन एवं सिपाहियों के लिए बैरक का निर्माण कार्य किया गया है. गोपाल जी के विकास के बावजूद पूर्व राजद प्रत्याशी हरेकृष्ण यादव ने इस विकास को दर किनार कर दिया है. उन्होंने कहा कि विधायक गोपाल जी ठाकुर ने ठेकेदारी के माध्यम से सिर्फ अपना विकास किया. अपने कार्यकाल में क्षेत्रीयता को बढ़ाने का काम किया है. बहेड़ी में मॉडल विद्यालय की योजना थी लेकिन इसे हटा कर बहेड़ा में बनवा दिया. फिर भी बेनीपुर की जनता देख रही है कि इस क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ.■

feedback@chauthiduniya.com

शेख़पुरा में दावेदारों की फौज

गंगा यादव

जीतेंद्र नाथ

प्रभात पांडेय

राजीव कुमार सिन्हा

रणधीर कुमार सोनी

शंभू यादव

सुनीला देवी

विजय यादव

विजय सम्राट

विनायक मिश्र

शेख़पुरा विधानसभा के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यूपीए गठबंधन या कहें महागठबंधन कम से कम एक मामले में तो एनडीए से आगे दिख रहा है. महागठबंधन के पास चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय प्रत्याशियों के विकल्प एनडीए से ज्यादा हैं. हालात यह हैं कि वर्तमान विधायक रणधीर कुमार सोनी फ सोनी मुखिया से आगामी चुनावों में दावेदारी झपटने की तैयारी जोरों पर चल रही है. लेकिन इनकी दावेदारी सर्वाधिक प्रबल है. पूर्व के चुनाव में इन्हें जीत हासिल करने के लिए लव-कुश के साथ अन्य जातियों का भी समर्थन हासिल करना पड़ा था. इस बार महागठबंधन के तहत अगर राजद से इन्हें थोड़ी-बहुत मदद भी मिल गई तो इनकी जीत सुनिश्चित होगी. जीत के प्रति आश्वस्त विधायक सोनी ने बताया कि पहले शेख़पुरा में पक्षपात की राजनीति होती थी. नेता सिर्फ नजदीकी लोगों के ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते थे. लेकिन इन्होंने इस प्रथा को तोड़ा है. पांच साल के दौरान उन्होंने सड़क, बिजली जैसे प्राथमिक विषयों में 99 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की बात कही. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे. अपराध मुक्त शेख़पुरा बनाकर विकास कार्य किया जा रहा है. कभी दहशत से भरा शेख़पुरा उनके नेतृत्व में अमन-चैन के साथ जी रहा है.

जदयू से टिकट की ख्वाहिश विजय यादव भी रखते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में एक षड्यंत्र के तहत मेरे टिकट को झपट लिया गया. इस बार चूक नहीं होगी. मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं. यह धरती आधुनिक बिहार के निर्माता और शेख़पुरा के विकास पुरुष राजो सिंह की है. यह उपक्षित है. यहां श्रमिक तथा मध्य वर्गीय किसान को न्याय के साथ विकास देने के लिए वे इस बार अवश्य चुनाव लड़ेंगे. जीतेन्द्र कुमार भी टिकट पाने की होड़ में शामिल हैं. उनका कहना है कि जदयू टिकट देती है तो लड़ेंगे, नहीं देगी तो भी लड़ेंगे.

उधर राजद से स्थानीय नेता शंभू यादव टिकट पाने की होड़ में हैं. उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो ने चुनाव की तैयारी में जुटने का आदेश दिया है. शंभू यादव पिछले दो चुनाव से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि हर दल राजद सुप्रीमो के फैसले का स्वागत करेगा. राजद से युवा नेता विजय सम्राट भी टिकट की चाहत में हैं. चर्चा है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की पहली पसंद विजय यादव हैं. विजय ने कहा कि उन्हें बस लालू प्रसाद के निर्णय का इंतजार है. सम्राट ने कहा कि वे राजद के समर्पित नेता है.

कांग्रेस का शेख़पुरा में बुरा हाल है. कभी यह इलाका गढ़ माना जाता था. राजो सिंह की मौत के बाद कांग्रेस हाशिये पर आ गई है. पार्टी की इच्छा है कि राजो सिंह के लिए समर्पित कुशल कार्यकर्ता गंगा कुमार यादव को इस बार पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाय. कांग्रेसियों का कहना है कि गंगा यादव को सभी जाति, धर्म, वर्ण का स्नेह प्राप्त है. अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो जिले में पार्टी का दबदबा बरकरार रह सकता है.

एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारों की संख्या कम है. कुछ भाजपा नेताओं का नाम उछाला जा रहा है. चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वालों में राजीव कुमार सिन्हा, रामबदन राय, पिन्कू मुखिया, रेश्मा भारती और दिनेश प्रसाद का नाम आ रहा है. 1977 से शेख़पुरा विधान सभा पर स्थानीय नेताओं का कब्ज़ा रहा है. इस बार स्थानीय नेताओं में राजीव कुमार सिन्हा का नाम प्रमुखता से उछाला जा रहा है. उन्होंने बताया कि अगर पार्टी टिकट देती है तो वे जनता की सेवा का कोई मौका नहीं चूकेंगे. इधर इसी दल की रेश्मा भारती पटना में कैंप कर टिकट के लिए प्रयासरत हैं. पूर्व विधान पार्षद राम बदन राय की भाजपा का टिकट चाहते हैं. डॉ. दिनेश प्रसाद ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपनी लिखित इच्छा डाल दी है. जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष पिन्कू मुखिया को विश्वास है कि भाजपा अगर टिकट देती है तो पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से वे जीत हासिल कर सकते हैं.

लोजपा से चन्दन यादव भी चुनाव लड़ना चाहते हैं. वे लोजपा के सांसद चिराग पासवान को विश्वास में लेकर यह सीट लोजपा की झोली में चाहते हैं. इस गठबंधन को मजेदार बनाने मे रालोसपा भी पीछे नहीं है. पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चन्द्रभूषण कुशवाहा ने इस बार शेख़पुरा विधान सभा सीट से रालोसपा का दावा ठोंक दिया है. उन्होंने बताया कि गठबंधन के विधान परिषद प्रत्याशी मुकेश यादव को शेखपुरा विधान सभा क्षेत्र से बढ़त दिलाने में उनकी भूमिका अहम रही है.

इधर सीपीआई के जिला सचिव प्रभात पांडेय ने बताया कि शेख़पुरा विधान सभा क्षेत्र से उनके दल ने चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है. उन्होंने ने बताया शेख़पुरा एक नेता के हटने से बंधुआ मुक्त हुआ है. संगठन में जान आई है. श्रमिक एवं मध्य वर्गीय तथा युवा नौजवान का सिर ऊंचा हुआ है. अगर यह सीट वाममोर्चा वाममोर्चा को मिलती है तो वे सीट के प्रबल दावेदार होंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

03 अगस्त–09 अगस्त 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

क्या 31 बच्चों का दाखिला हो पाएगा

प्रसिद्ध समाजसेवी, गांधीवादी, मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पांडेय पिछले दिनों लखनऊ में गांधी प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे थे. उनकी मांग है कि शिक्षा के अधिकार के तहत 31 गरीब बच्चों को लखनऊ के प्रमुख प्राइवेट स्कूल समूह सिटी मॉन्टेसरी में एडमिशन मिले. लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इससे मना कर दिया. स्कूल के संस्थापक प्रबंधक डॉ. जगदीश गांधी को सिटी मॉन्टेसरी स्कूल (सीएमएस) में गरीब बच्चों का पढ़ना गवारा नहीं हुआ. संदीप पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग भी की, लेकिन समाजवादी सरकार ने सुना नहीं. आखिरकार संदीप पांडेय को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी डॉ. जगदीश गांधी और अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ा. प्रशासन ने हफ्तेभर बाद संदीप पांडेय का अनशन तुड़वा दिया, लेकिन सरकार उनकी मांग नहीं तुड़वा पाई. चौथी दुनिया के आग्रह पर संदीप पांडेय ने पूरे प्रकरण पर खुद ही पूरी रिपोर्ट लिखी है, जो रिपोर्ट भी है और वैचारिकी भी...

संदीप पाण्डेय

भारत में 1968 में कोठारी आयोग ने समान शिक्षा प्रणाली एवं पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा को लागू करने की सिफारिश की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक सभी सरकारों ने उसे नजरअंदाज किया है. 2009 में (मुफ्त एवं अनिवार्य) शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसने कमजोर तबकों के परिवारों के बच्चों को सभी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की. पहले तो सरकारें इस प्रावधान को क्रियान्वित करने में गंभीर नहीं थीं. अब निजी विद्यालय कानून के इस प्रावधान की काट निकालने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं.

लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 2015–16 शैक्षणिक सत्र के लिए दिनांक 6 अप्रैल, 2015 को 31 गरीब परिवारों के बच्चों को शहर के जाने माने विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009, के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चों हेतु आरक्षण के प्रावधान के तहत दाखिले का आदेश किया. इनमें 15 बच्चे प्राथमिक एवं 16 प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिला लेंगे. 31 में से 23 बच्चे अनुसूचित जाति के, 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के व 2 सामान्य श्रेणी के हैं, जिनके परिवारों की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के जो 8 बच्चे हैं वे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से हैं. यानी ये सभी बच्चे वंचित समूहों से हैं. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने बच्चों को दाखिला देने के बजाए न्यायालय में याचिका दायर करने का निर्णय लिया. वह बच्चों को दाखिला न देने के तमाम कारण गिना रहा है. पहले तो वह कह रहा है कि उसके पास जगह की कमी है, क्योंकि उसने पहले ही जितनी क्षमता थी उतने दाखिले ले लिए हैं. फिर वह सवाल कर रहा है कि बच्चों के घर के पास एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय व कुछ निजी विद्यालय भी हैं तो दाखिले का आदेश सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ही क्यों किया गया?

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चों हेतु आरक्षण के प्रावधान को लागू किया था. यह बात दूसरी है कि लखनऊ में इसके तहत सिर्फ चार बच्चों को ही दाखिला मिला था. उत्तर प्रदेश के होशियार नौकरशाहों ने यह नियम बनाया कि यदि बच्चे के घर से एक किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई सरकारी प्राथमिक विद्यालय होगा तब वह किसी निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. पहले सरकारी विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख कर देना होगा कि वह बच्चे का दाखिला नहीं कर सकता तब बच्चा किसी निजी विद्यालय में दाखिले का दावा कर सकता है, वह भी जिलाधिकारी की अनुशंसा के बाद. जब प्रधानाचार्य को मालूम है कि ऊपर के अधिकारी नहीं चाह रहे कि गरीब बच्चे निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के तहत पढ़ें, तो वह ऐसा क्यों लिख कर देगा कि वह बच्चे का दाखिला अपने विद्यालय में नहीं कर सकता?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस वर्ष के शासनादेश के मुताबिक एक वार्ड को पड़ोस माना गया है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत गरीब परिवारों के बच्चों को आरक्षण का लाभ पड़ोस के विद्यालय में ही मिलेगा. जो सरकारी विद्यालय बच्चों के घर के पास में हैं वह उनके वार्ड में नहीं जबकि सिटी मॉन्टेसरी की इंदिरा नगर शाखा उसी वार्ड में स्थित है. दूसरा, शासनादेश के अनुसार सरकारी विद्यालय में यदि कक्षा 1 में 40 से ज्यादा बच्चों का दाखिला हो चुका है, तभी आप निजी विद्यालयों में दाखिले का दावा कर सकते हैं. उपर्युक्त सरकारी विद्यालय में 52 बच्चों का दाखिला हो चुका है. इस वार्ड में करीब 50 बच्चों का दाखिला उक्त प्रावधान के तहत अन्य निजी विद्यालयों में हो चुका है. 5 जून, 2015 तक लखनऊ शहर में कुल 318 व पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 2817 दाखिले हो चुके थे. सिर्फ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ही एक ऐसा है जिसने दाखिले से मना कर दिया है. कुछ अन्य विद्यालय भी दाखिला देने में आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन सिटी मॉन्टेसरी जैसी भूमिका किसी ने नहीं ली है.

न्यायालय ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा खड़े किए गए सवालों का जवाब शिक्षा विभाग से मांगा है. उसने दाखिले पर कोई रोक नहीं लगाई और न ही स्थगनादेश दिया है. इसके बावजूद सिटी मॉन्टेसरी बच्चों को दाखिला नहीं दे रहा. बेसिक शिक्षा अधिकारी 6 अप्रैल के अलावा 13 अप्रैल, 11 मई व जुलाई प्रथम सप्ताह में पुनः तीन बार सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को 31 बच्चों के दाखिले हेतु निर्देशित कर चुके हैं. किंतु सिटी मॉन्टेसरी पर ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा अधिकारी के पत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा. यह खुले आम शासन–प्रशासन की अवहेलना है. सिटी मॉन्टेसरी एक राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का दोषी माना जाना चाहिए.

वैसे सिटी मॉन्टेसरी शासन–प्रशासन के साथ मिल कर काफी काम करता है. हाल ही में श्री श्री रवि शंकर के आर्ट आफ लिविंग का उत्तर प्रदेश के आई.ए.एस. अधिकारियों हेतु कार्यक्रम का आयोजन सिटी मॉन्टेसरी की ही एक शाखा में हुआ. सिटी मॉन्टेसरी विद्यालय जिसकी 20 शाखाओं में करीब 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, दुनिया के सबसे बड़े विद्यालय की जिसे गिनीज़ बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड ने मान्यता दी है, 31 गरीब बच्चों को दाखिला न देने के लिए जगह की कमी होने का बहाना बना रहा है. सिटी मॉन्टेसरी यह भी कह रहा है कि सरकार एक बच्चे को पढ़ाने का जो 450 रुपये प्रति माह का खर्च देने वाली है वह कम है. उसके अनुसार एक बच्चे को पढ़ाने में कम से कम 2,200 रुपये प्रति माह का खर्च आता है. यह बड़े शर्म की बात है कि सिटी मॉन्टेसरी आई.ए.एस. आधिकारियों, वकीलों, न्यायाधीशों, मंत्रियों, सांसदों–विधायकों व पत्रकारों के बच्चों का 40 प्रतिशत शुल्क माफ कर देता है और गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात पर पैसे की कमी का बहाना बना रहा है. आई.ए.एस. अधिकारी, वकील, न्यायाधीश, मंत्री, सांसद–विधायक व पत्रकार के बच्चों को शुल्क में छूट देने के पीछे आखिर इस विद्यालय के प्रबंधक व भूतपूर्व विधायक जगदीश

(शेष पृष्ठ 18 पर)

शिक्षा के अधिकार की धज्जियां उड़ रही हैं

भारत में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून लागू है, लेकिन शिक्षा न तो नि:शुल्क है और न ही अनिवार्य. निजी विद्यालयों में तो फीस पड़ती ही है, सरकारी भी किसी न किसी बहाने कुछ पैसा वसूल ही लेते हैं. बहुत सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में काम करते बच्चों को देखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा अनिवार्य तो बिल्कुल नहीं. विडम्बना यह है कि कई बच्चे सरकारी कार्यालयों में चाय पहुंचाते देखे जा सकते हैं. दुनिया के सभी विकसित देशों व कई विकासशील देशों ने भी 99–100 प्रतिशत साक्षरता की दरें हासिल कर ली हैं. भारत में आधे बच्चे विद्यालय स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते. इसमें से आधे बाल मजदूरी के शिकार हैं. भारत जिस चीज का सबसे बड़ा दोषी है वह है समान शिक्षा प्रणाली और उसके साथ पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा को लागू न करना. इसके मायने यह हैं कि सभी बच्चों को लगभग एक गुणवत्ता वाली शिक्षा हासिल करने के अवसर उपलब्ध होना. दुनिया के जिन देशों ने 99 या 100 प्रतिशत साक्षरता की दर हासिल कर ली है उसमें बड़ा योगदान इन अवधारणाओं का है. ज्यादातर देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं. जब तक सभी बच्चों के लिए एक जैसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होगी तब तक हम सभी को शिक्षित भी नहीं बना सकते. भारत में अब दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं हैं-एक पैसे वालों के लिए जो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं तो दूसरी गरीब लोगों के लिए जो अपने बच्चे सरकारी विद्यालय में भेजने के लिए अभिशप्त हैं, जहां पढ़ाई ही नहीं होती. इस तरह भारत में शिक्षा अमीर व गरीब के बीच दूरी को और बढ़ा देती है. अमीर परिवारों के बच्चों के सामने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के तमाम विकल्प खुल जाते हैं तो गरीब के बच्चे का जिंदगी भर शोषण होता रहता है. जिनको पढ़ाई-लिखाई के आधार पर रोजगार मिलता भी है उसमें ऊपर के पदों पर तो छठा वेतन आने के बाद बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलने लगी हैं, लेकिन नीचे के सारे पदों पर अब संविदा व अस्थाई भर्तियां ही हो रही हैं. बहुत सारे काम अब ठेके पर कराए जा रहे हैं. जो पैसे वाले अपने बच्चों को फीस लिए जाने वाले विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं, चूंकि ऐसी मान्यता है कि निजी विद्यालयों में पढ़ाई बढ़िया होती है, यही लोग उच्च शिक्षा के लिए सरकारी संस्थानों जैसे भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबंध संस्थान में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस स्तर पर मान्यता है कि निजी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता नहीं. इससे साफ है कि गुणवत्ता का ताल्लुक निजी या सरकारी से नहीं, इच्छा शक्ति से है. हम जिसे चाहें उसकी गुणवत्ता सुधार दें व जिसकी चाहें गिरने दें. शिक्षा विषमता को बढ़ा देती है. गरीब का बच्चा जिसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलती अपनी शिक्षा के आधार पर अपना विकास भी नहीं कर सकता. इसलिए ज्यादातर गरीबों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से ही बाहर हो जाते हैं. नौकरी के बाजार में वे अमीरों के बच्चों के सामने टिक ही नहीं सकते. अंग्रेजी और कम्प्यूटर का ज्ञान इन बच्चों को स्पष्ट दो वर्गों में विभाजित कर संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का माखौल उड़ाता है. इस तरह गरीब के बच्चे को विषमता के दुष्चक्र को तोड़ने का मौका ही नहीं मिलता. शिक्षा पूरी करने में गरीबों के लिए बड़ी बाधा बनता है कुपोषण. जनवरी 2013 में प्रधानमंत्री ने एक रपट जारी करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है भारत में आधे बच्चे कुपोषित हैं. अब यदि प्रधानमंत्री ही शिकायत करने लगें तो समाधान कौन ढूंढेगा? यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है. अमेरिका जैसे घोर पूंजीवादी देश में विद्यालय स्तरीय शिक्षा पड़ोस के विद्यालय में पूरी होती है जिसका संचालन स्थानीय निकाय करता है. न सिर्फ किसी किस्म का शुल्क नहीं लगता बल्कि किताबें, पहनावा और घर से आने-जाने के लिए बस का खर्च भी विद्यालय ही वहन करता है. सबसे बड़ी बात है कि सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध रहती है. जो काम दुनिया के कई विकसित एवं विकासशील देशों ने कर दिखाया है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों नहीं कर रहा?

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

यूपी सरकार के खिलाफ पंचाट की शरण में अमिताभ

विद्रोही आईपीएस को घेरने में जुटी सरकार

दीनबंधु कबीर

आईपीएस अधिकारी को धमकी वाले प्रकरण में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और सम्पत्ति का ब्यौरा देने में आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर फंस गए हैं. धमकी देने से न मुलायम मुकर सकते हैं और सम्पत्ति के ब्यौरे के घालमेल से अमिताभ उबर सकते हैं. अमिताभ की सम्पत्ति के बारे में तो प्रदेश के लोकायुक्त से भी शिकायत की गई है. बलात्कार के आरोप के घेरे में अमिताभ ठाकुर को जकड़ने की सरकार की साजिश खुद सरकार के लिए ही उल्टा दांव साबित होने वाली है, क्योंकि अब यह तथ्य भी खुलने लगा है कि जिस दिन मुलायम की धमकी वाला टेप सार्वजनिक किया गया, उसी शाम को प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को शासन का निर्देश मिला कि अमिताभ के खिलाफ रेप का मामला फौरन दर्ज किया जाए. इस कार्रवाई की आपाधापी में सरकार उसकी कानूनी परिणति का आकलन करने से चूक गई. विशेषज्ञ कहते हैं कि परिणति का आकलन करने में सक्षमता होती तो मुलायम एक अधिकारी को धमकी देने का काम कतई नहीं करते.

बहरहाल, विद्रोही आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को कानून के शिकंजे में बांधने की सरकार की कोशिश जारी है. सरकार ने निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जांच करने के लिए पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष वीके गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी है. साथ ही आईजी कार्मिक बीपी जोगदंड को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है. अमिताभ ठाकुर ने सरकार के इस आदेश को पूरी तरह विधिविरुद्ध बताया और गृह विभाग के प्रमुख सचिव पत्र लिख कर कहा अखिल भारतीय सेवा अनुशासन एवं अपील नियमावली के नियम 8 (4) के अनुसार किसी भी आईपीएस अफसर के खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त करने के पूर्व उसे कारण बताओ नोटिस दी जाती है और नियम 8 (5) में उसका जवाब मिलने के बाद ही नियम 8 (6) के तहत जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है. जबकि इस मामले में उन्हें 13 जुलाई का आरोप पत्र देने के अगले दिन 14 जुलाई को बिना स्पष्टीकरण का मौका दिए ही उनके खिलाफ जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करने का आदेश दे दिया गया. उनके द्वारा 16 जुलाई को प्रेषित जवाब का परीक्षण तक नहीं किया गया. प्रमुख सचिव गृह को भेजे अपने पत्र में अमिताभ ठाकुर ने कहा कि उन्होंने आरोपपत्र मिलने के 24 घंटे के अन्दर 16 जुलाई 2015 को ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया था और कहा था कि 16 आरोप पूरी तरह निराधार हैं, लिहाजा निलंबन पूर्णतया अवैधानिक होने के कारण इसे तत्काल समाप्त करते हुए आरोप पत्र को खत्म किया जाए. ठाकुर ने जांच अधिकारी की नियुक्ति को नियमावली के विपरीत और द्वेष भाव से की गई कार्रवाई बताया और इसे केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल"कैट") में चुनौती दी है.

दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने धमकी प्रकरण की सीबीआई से जांच कराए जाने की अमिताभ ठाकुर की मांग को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को संदर्भित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने 16 जुलाई 2015 के अपने पत्र में कहा है कि आईजी अमिताभ ठाकुर द्वारा सीबीआई जांच की मांग का मामला डीओपीटी विभाग के क्षेत्राधिकार में है, अतः इसमें डीओपीटी के स्तर पर ही उचित निर्णय लिया जा सकता है. ठाकुर ने 13 जुलाई को गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मिलकर यह कहा था कि जबसे उनकी पत्नी ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ लोकायुक्त में परिवाद दायर किया है तबसे उन पर बलात्कार के मामले सहित तमाम फर्जी मुकदमे हुए और खुद मुलायम सिंह यादव ने 10 जुलाई को उन्हें फोन कर धमकी दी. लिहाजा इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए. लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ठाकुर की इस मांग को बड़ी चालाकी से टाल दिया. अमिताभ ठाकुर ने विभागीय जांच और कार्रवाई की औपचारिकताओं के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए भी समय मांगा था. अमिताभ ठाकुर का कहना था कि यदि निर्णयकर्ता प्राधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री उनके स्पष्टीकरण को सही नहीं मानते हैं तो वे कोई अग्रिम निर्णय लेने के पहले उन्हें इस विभागीय कार्रवाई में अपना पक्ष रखने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर अवश्य दें. विभागीय कार्रवाई एक अर्ध-न्यायिक कार्रवाई है जिसमें मुख्यमंत्री के निर्णयकर्ता अधिकारी होने के नाते आरोपी अधिकारी को उनके सामने अपनी बात कहने का विधिक अधिकार है. लेकिन मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया.

अमिताभ ने दिया सम्पत्ति का ब्यौरा

आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने आईजी कार्मिक बीपी जोगदंड के जरिये सतर्कता जांच के सम्बन्ध में मांगी गई सम्पत्ति की जानकारी सौंप दी. अमिताभ ने बताया है कि उनके निकट परिवार में चार लोग हैं जिनमें उनकी पुत्री तानया और पुत्र आदित्य उन पर आश्रित हैं, जबकि उनकी पत्नी सामाजिक कार्यकर्ता डॉ नूतन ठाकुर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रही हैं. अमिताभ के अनुसार उनके पास अपनी दो सम्पत्ति है, जिसमें एक गोमतीनगर का उनका मकान है और दूसरा नौकरी के पूर्व का मुजफ्फरपुर (बिहार) में प्लॉट है. अमिताभ की पत्नी के पास सीतामढ़ी और पटना में तीन और लखनऊ में छह सम्पत्ति है, जो उनकी स्वयं की आय से अर्जित है. अमिताभ ने पूरी नौकरी के दरम्यान म्युजिक सिस्टम, रूम हीटर, गीजर, ओवन, मिक्सी, माइक्रो ओवन, हैंडीकैम, डिजिटल कैमरा, वूलेन कारपेट, ब्रांडेड फर्नीचर, घड़ी, घरेलू जानवर आदि के खरीदे और बेचे जाने की सूचना देने के अलावा सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, एनएससी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शेयर, एलआईसी पॉलिसी, म्युचुअल फंड वगैरह के खरीदे और बेचे जाने का विवरण देने के लिए एक महीने का समय मांगा है.

एफआईआर के लिए कोर्ट जाएंगे अमिताभ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव द्वारा टेलीफोन पर धमकी दिए जाने के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने के खिलाफ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने अदालत की शरण में जाने का फैसला किया है. हालांकि एफआईआर के लिए उन्होंने लखनऊ के एसएसपी राजेश पांडेय को आवेदन भी सौंपा है. अमिताभ ठाकुर ने लखनऊ के एसएसपी को धारा 154 (3) सीआरपीसी के तहत पत्र भेज कर मुलायम सिंह यादव द्वारा उन्हें 10 जुलाई 2015 को फोन पर धमकी देने के मामले में धारा 506 आईपीसी में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया है. पत्र में कहा है कि उन्होंने 11 जुलाई को हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर विजय पाल सिंह यादव को एफआईआर दर्ज करने के लिए तहरीर दी थी, जिसे उन्होंने रिसीव किया लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की. अमिताभ ठाकुर ने कहा है कि यदि एसएसपी द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं गई तो वे 156 (3) सीआरपीसी के तहत सीजेएम कोर्ट जाएंगे.

अमिताभ के समर्थन में उतरे खेमका और चतुर्वेदी

उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के समर्थन में देश के दो नौकरशाह खुलकर सामने आ गए हैं. हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका और आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर को अपना नैतिक समर्थन दिया है. सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सर्वाधिक तबादलों से चर्चा में आए खेमका और एम्स में भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने वाले चतुर्वेदी ने अमिताभ ठाकुर से फोन पर बात की और कहा कि वे तहेदिल से उनके साथ हैं.

अमिताभ के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत

आईपीएस अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत में अमिताभ पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है. लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने बताया कि शिकायत का परीक्षण किया जा रहा है. आईपीएस के खिलाफ शिकायत आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने की है. आरोप है कि अमिताभ ठाकुर और उनके परिवारीजनों के नाम खरीदी गई अचल सम्पत्ति का मूल्य ज्यादा है, लेकिन उसे कम कीमत में खरीदा दिखाया गया है. लोकायुक्त से उन सम्पत्तियों को लेने के लिए आय के स्रोतों की जांच करने का अनुरोध किया गया है. अमिताभ ठाकुर पर पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि नौकरी पर रहते हुए उन्होंने सरकारी पद, कार्यालय और संसाधनों का दुरुपयोग किया. आरोपों से जुड़े करीब 50 पेज के साक्ष्य और दस्तावेज भी शिकायत के साथ संलग्न किए गए हैं. लोकायुक्त ने शिकायत पर औपचारिक रूप से जांच शुरू कर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

क्या 31 बच्चों का दाखिला हो पाएगा

पृष्ठ 17 का शेष

गांधी की क्या मंशा है? शायद समाज के रसूख वालों को अपने पक्ष में रखने के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही. उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना है कि वे प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का स्तर इतना अच्छा बना देंगे कि लोग निजी विद्यालयों से अपने बच्चों का नाम कटवा कर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लिखवाएंगे. सिटी मॉन्टेसरी सालाना करीब 30 अंतरराष्ट्रीय स्तर के और छोटे-मोटे तो अनेक कार्यक्रम आयोजित कराता है, जिनमें करोड़ों रुपये खर्च होते होंगे. इसके तमाम विद्यार्थी और शिक्षक विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में शरीक होते हैं. इनमें एक कार्यक्रम दुनिया भर के सेवारत व सेवा निवृत्त न्यायाधीशों को बुला कर भी किया जाता है. लेकिन 31 बच्चों के दाखिले के शिक्षा विभाग के आदेश के खिलाफ न्यायालय में जाकर सिटी मॉन्टेसरी देश के एक महत्वपूर्ण कानून का उल्लंघन करने का दोषी तो बन गया है. अब देखना यह है कि दुनिया भर के न्यायाधीश क्या एक कानून को न मानने वाले मेजबान का

आतिथ्य स्वीकार करेंगे? सरकारी विद्यालयों की स्थिति तभी सुधारी जा सकती है जब सभी सरकारी वेतन पाने वालों व जन प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए. ऐसा हो जाने पर सरकारी विद्यालयों की स्थिति रातों-रात सुधारी जा सकती है. इसके अलावा तो और कोई रास्ता समझ में नहीं आता. पता नहीं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री का सपना कब पूरा होगा? फिलहाल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009, के अंतर्गत जो 25 प्रतिशत गरीब परिवारों के बच्चों के आरक्षण का प्रावधान है, वह गंभीरता से लागू होना चाहिए. अभी तक सरकारों ने इस कानून के अनुपालन हेतु पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं दिखाई है. सरकारों को तो कोई दिलचस्पी है नहीं, यदि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जैसी प्रभावशाली संस्थाओं ने इस कानून को मानने से मना कर दिया तो अन्य विद्यालय भी उसकी देखा-देखी कानून को गंभीरता से नहीं लेंगे. इस तरह भारत के गरीब परिवारों के कुछ बच्चों जिन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर मिला है उससे उनको वंचित रखा जाएगा. इधर जमीनी स्तर पर ग्रामीण व गरीब भारत में काफी उथल-पुथल हो रही है. अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि मजदूरों के बच्चे भी अब आई.आई.टी. जैसे संस्थानों की कठिन प्रवेश परीक्षा में सफल हो रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में और खासकर गरीबों के बीच एक ललक जगी है कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसी से उसका बच्चा गरीबी और शोषण के कुचक्र से मुक्ति पा सकेगा. गरीब के पास जैसे ही इतनी क्षमता आती है कि वह अपने बच्चे को निजी विद्यालय में पढ़ा सके वह अपने बच्चे का दाखिला वहां करा देता है. जागरूक ग्रामीण अभिभावक अपने होनहार बच्चों को नवोदय विद्यालय में भेजना चाहते हैं, जो अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर हो गए हैं. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जब 31 बच्चों को दाखिला दे देगा तो सिर्फ 31 बच्चों का ही भला नहीं होगा. इससे तमाम गरीब परिवारों के बच्चों के लिए उस शिक्षा को हासिल करने के दरवाजे खुल जाएंगे जो उनकी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन ला सकेगी.■

(लेखक मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित हैं.)

निजी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण जरूरी

यह भी एक अजीब बात है कि अब शिक्षा विभाग अपने विद्यालयों को ठीक से संचालित करने के बजाए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को दाखिला दिलाने में अपना समय व ऊर्जा लगा रहा है. इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मिल कर अभी तक करीब तीन हजार से थोड़ा कम ही बच्चों का दाखिला कराया है. इतने थोड़े से बच्चों का दाखिला करा कर सरकार हरेक गरीब बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगी? गरीब में भी जो थोड़ा जागरूक होंगे वे अपने बच्चों का निजी विद्यालयों में दाखिला करवा लेंगे, लेकिन जो ज्यादा गरीब होंगे वे फिर छूट जाएंगे. अतः सरकार को चाहिए कि सिटी मॉन्टेसरी सहित अन्य विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करके उनको समान शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के तहत खुद चलाए. इन विद्यालयों में शिक्षण कार्य का प्रबंधन भले ही निजी हाथों में हो, लेकिन प्रशासनिक संचालन सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए ताकि सरकार अपने हिसाब से गरीब बच्चों को यहां पढ़ा सके. यदि सरकार सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में जरा भी गंभीर है, तो इसके सिवाए हमारे सामने कोई विकप्ल नहीं कि सारे निजी विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करके दुनिया के अन्य देशों की तरह जिन्होंने 99-100 प्रतिशत साक्षरता हासिल की है समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय की अवधारणा को देश में लागू किया जाए.

सरकारी तनख्वाह लेने वाले व जन प्रतिनिधियों के बच्चों के लिए सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए. यदि सरकार और प्रशासन में बैठे लोग सरकारी विद्यालयों को अपना नहीं मानेंगे तो भला और कौन मानेगा? जब हम किसी सड़क के किनारे दुकान पर कुछ खा रहे होते हैं अथवा चाय की दुकान पर चाय पी रहे होते हैं तो हमें कई बार यह अहसास ही नहीं होता कि जो हाथ हमें खिला-पिला रहे हैं उन हाथों में असल में पेंसिल-किताब होनी चाहिए. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24, 21-ए व 45 बाल दासता को रोकने के लिए पर्याप्त होने चाहिए थे. अब तो कई कानून भी बन गए हैं. कारखाना अधिनियम, 1948, खादान अधिनियम, 1952, बाल मजदूर (प्रतिबंध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986, नाबालिग बच्चों को न्याय (संरक्षा एवं सुरक्षा), 2000 व मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन ईमानदारी से हो जाता तो काम करते हुए बच्चे कहीं दिखाई नहीं पड़ते. इन कानूनों के होते हुए भी बाल मजदूरी धड़ल्ले से चल रही है. इसका मतलब है कि न तो सरकार उपर्युक्त कानूनों के क्रियान्वयन के प्रति गंभीर है और न ही नागरिकों को बाल मजदूरी से कोई दिक्कत है. कभी बच्चे के परिवार की मजबूरी बता कर या शिक्षा की बच्चे की जिंदगी में निरर्थकता बता हम किसी न किसी तर्क से बाल मजदूरी को जायज ठहरा देते हैं. यदि हम ऐसी किसी सेवा का उपभोग कर रहे हैं, जिसमें बाल मजदूर ने काम किया है तो हम भी स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं. इसके अलावा हमें अपने से नैतिक सवाल यह भी पूछना पड़ेगा कि हमें किसी का बचपन छीनने का अधिकार किसने दिया?

यदि हम बच्चे को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो हम उसके लिए जिंदगी में तरक्की के रास्ते बंद कर रहे हैं. कई बार यह कहा जाता है कि गरीबी के कारण बच्चा नहीं पढ़ पाता. किंतु यह भी तो सच है कि यदि उसे गरीबी का दुष्चक्र तोड़ना है तो शिक्षित होना पड़ेगा. ज्यादातर बाल मजदूर दलित एवं मुस्लिम समुदाय से हैं जो हमारे समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं. इन्हें शिक्षा से वंचित रखने का मतलब होगा इनकी गरीबी की स्थिति बनाए रखना. सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर के हिसाब से भारत दुनिया में अग्रणी देशों में है, लेकिन सामाजिक मानकों के हिसाब से हमारी गिनती सबसे पिछड़े देशों में होती है. दक्षिण एशिया में आजादी के समय सामाजिक मानकों की दृष्टि से श्रीलंका के बाद हमारा स्थान था. अब पाकिस्तान को छोड़ बाकी सभी देश हमसे आगे निकल गए हैं. सामाजिक मानकों में सुधार तभी हो सकता है जब मौलिक आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरतें पूरी हों और साथ ही शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी गुणवत्ता के साथ सभी को निःशुल्क उपलब्ध हों. ज्यादातर देशों जिन्होंने अपने सामाजिक मानकों में सुधार लाया है, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए अच्छी और निःशुल्क शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाएं की हैं.

भारत में सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होनी है, तो सिवाय समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने के, और कोई उपाय नहीं है. जब सरकारी अधिकारियों ने घाटे में चलने वाली एअर इण्डिया को यह नियम बना कर जिंदा रखा है कि सरकारी काम से यात्रा करने वाले लोगों को एअर इण्डिया से ही यात्रा करनी होगी तो सरकारी विद्यालयों को जिंदा रखने के लिए वे अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजने का नियम क्यों नहीं बना सकते?

इतने में तो गरीब बच्चों का एडमिशन हो जाता

सिटी मॉन्टेसरी स्कूल समूह के संस्थापक प्रबंधक जगदीश गांधी ने जो 12.6 लाख रुपये से अधिक के विज्ञापन छपवाए उससे 31 बच्चों को उनके स्कूल में शिक्षा मिल सकती थी. सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधक जगदीश गांधी ने मेरे नाम पत्र लखनऊ के कम से कम 7 बड़े अखबारों में 21 जुलाई 2015 को छपवाया है. यह पत्र वे मुझे मेरे निवास पर, मेरे अनशन समाप्त करने के बाद 17 जुलाई 2015 को स्वयं दे चुके थे. चूंकि मैं यह पत्र पहले ही पढ़ चुका हूं इसलिए मुझे यह नहीं पता कि यह किसके लिए अखबारों में छपवाया गया है? हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष इस सम्बन्ध में केस चल रहा है जिसमें सीएमएस प्रार्थी है. यह केस, बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के आदेश से सम्बंधित है, जो सीएमएस की इंदिरा नगर ब्रांच में 31 बच्चों के दाखिले को लेकर है जिसका सीएमएस विरोध कर रहा है. मैंने 7 दिन का अनशन भी रखा था जिससे कि जगदीश गांधी इन बच्चों को दाखिला दें.

हालांकि अनशन समाप्त हो गया है, लेकिन बच्चों का दाखिला अभी तक नहीं हुआ है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित की है कि सीएमएस इंदिरा नगर ब्रांच में 31 बच्चों के पढ़ाने के लिए जगह है, और हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट का आदेश बच्चों के हित में ही आएगा. 21 बच्चों को सीएमएस में एक साल तक पढ़ाने की कीमत (औसतन रुपये 4000 प्रति माह प्रति छात्र, जिसमें से रुपये 450 सरकार स्कूल को वापस देगी) लगभग रुपये 12.6 लाख आती है. यदि हम लखनऊ के कम-से-कम 7 अखबारों में मेरे नाम जगदीश गांधी का पत्र विज्ञापन की तरह छपवाने की कीमत को जोड़ें तो यह 12.6 लाख रुपये से अधिक आती है. यह अत्यंत खेद का विषय है कि जगदीश गांधी उन अभिभावकों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने बच्चे सीएमएस में पढ़ा रहे हैं. यदि उन्होंने यह पैसे 31 बच्चों को शिक्षित करने में व्यय किये होते तो कितना बेहतर होता. ■

मानवाधिकार के उल्लंघन में अव्वल उत्तर प्रदेश

सरकारी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे बंधुआ मज़दूर

वैष्णवी वंदना

बाण सागर परियोजना में थारू जनजाति के बंधुआ मजदूरों से जबरन काम कराए जाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने श्रावस्ती और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों से जवाब-तलब किया है. सरकारी बाण सागर परियोजना में काम पर लगे 41 बंधुआ मजदूरों को पिछले दिनों रिहा कराया गया था. सात मजदूर अब भी लापता बताए जा रहे हैं. सरकारी काम में बंधुआ मजदूरी के प्रकरण का खुलासा होने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इसे गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू की है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति डी मुरुगेशन ने इस घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए श्रावस्ती और मिर्जापुर के जिलाधिकारियों से पूरी रिपोर्ट तलब की है. दूसरी तरफ जौनपुर जिला जेल में पुलिस की पिटाई से हुई कैदी की मौत और उसके परिणाम स्वरूप जेल में हुए हिंसक संघर्ष को भी संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन से जवाब तलब किया है. चार महीने से अधिक समय से बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर 41 लोगों को छुड़ाया गया था. इनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं. श्रावस्ती जिला प्रशासन की पहल पर मजदूरों को छुड़वाया गया. सभी मजदूरों को उनके जिले से बस्ती में काम दिलाने के बहाने मिर्जापुर लाया गया था. श्रावस्ती से लाए गए मजदूरों को मड़िहान थाना इलाके के चिकुरिया गांव में बाण सागर परियोजना में काम कराया जा रहा था. श्रावस्ती जिले के भिनगा क्षेत्र के रहने वाले मजदूरों को बस्ती जिले में काम दिलाने का झांसा देकर मिर्जापुर ले आया गया और दलाल इन्हें ठेकेदार के हाथों सौंपकर चला गया. मजदूरों ने कई बार वहां से भागने का भी प्रयास किया था, पकड़े जाने पर ठेकेदार और उसके गुर्गे उनकी जबरदस्त पिटाई करते था. मजदूरों के परिजनों को सूचना मिलने पर उन्होंने श्रावस्ती के जिलाधिकारी से इसकी शिकायत की थी. इसके बाद श्रावस्ती के जिलाधिकारी ने मिर्जापुर के जिलाधिकारी से सम्पर्क कर उन्हें मामले से अवगत कराया. जानकारी मिलते ही श्रम विभाग और पुलिस महकमा सक्रिय हुआ और फिर मजदूरों को ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाया गया.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग की बाणसागर परियोजना में ही 41 मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखे जाने के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है. इन मजदूरों को बहुत कम मजदूरी दी जा रही थी और अफसरों और ठेकेदार ने यह कहकर इन को रोक रखा था कि काम खत्म होते ही उनकी बकाया मजदूरी भी दे दी जाएगी. ये सारे मजदूर थारू आदिवासी थे, जिन्हें कानून के तहत विशेष संरक्षण मिला हुआ है. इन मजदूरों में कई महिलाएं भी थीं. श्रावस्ती जिले से लाकर इनसे मिर्जापुर के चिकुलिया ढाढीराम गांव में बाणसागर सिंचाई परियोजना की साइट पर काम लिया जा रहा था. मजदूरों को पूरी दिहाड़ी भी नहीं दी जा रही थी. मजदूरों ने बताया कि मार्च में प्रति व्यक्ति 500 रुपये, अप्रैल में 450 रुपये, मई में एक हजार रुपये और जून में प्रति व्यक्ति 600 रुपये दिए गए थे. मजदूर जब भी घर जाने की बात करते तो उनकी पिटाई की जाती. इस मामले में मांगरे नाम के एक पुरुष और लालमोती नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया. लेकिन पता यह चला कि मंजूलता सिंह नाम की महिला अपने एक साथी के साथ इन मजदूरों को मिर्जापुर लेकर आई थी. बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर गोविंद चंद्र के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई. बताया गया कि मंजूलता का बेटा आलोक सिंह ही मजदूरों को लेकर आता था, लेकिन दस्तावेजों में आलोक का नाम कहीं नहीं मिला है. दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि भिनगा सिरसिया के भचकाही, मोतीपुर कला, कटकुइयां व रनियापुर के 41 मजदूर-मजदूरिनों और उनके साथ तीन बच्चों को दिलीप नाम का एक ठेकेदार मिर्जापुर ले गया था. ठेकेदार ने सभी मजदूरों को आलोक सिंह व अन्य ठेकेदार के सुपुर्द कर दिया था. थारू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी राघवेंद्र विक्रम सिंह से इसकी शिकायत की थी. इसके बाद ही मिर्जापुर के जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह को जानकारी देकर बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया जा सका. छापे में मिर्जापुर के एसडीएम सदर अशोक कनौजिया, सीओ गीतांजलि सिंह और सहायक श्रमायुक्त पंकज राणा शरीक थे.

मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाराबंकी के कोठी थाने में थाना प्रभारी और एक दारोगा द्वारा महिला से बलात्कार की कोशिश में विफल होने पर उसे जिंदा जला कर मार डालने की घटना को संज्ञान में लेते हुए यूपी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर रखी है. इसके पहले शाहजहांपुर के पत्रकार जगेन्द्र सिंह को पुलिस और राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के गुंडों द्वारा जला कर मारे जाने के मामले में आयोग ने सरकार को आड़े हाथों लिया था.

श्रम विभाग के एक अधिकारी ने तो यह भी कहा कि श्रावस्ती से मिर्जापुर लाए गए थारू मजदूरों को ठेकेदार के हाथों बेच दिया गया था. मिर्जापुर ले जाए गए मजदूरों की संख्या 48 थी, जिनमें चार महिलाएं, छह पुरुष, छह लड़कियां और 32 लड़के शामिल थे. लेकिन बरामदगी केवल 41 मजदूरों की हुई. सात मजदूर अब भी लापता हैं. इनमें कई बाल मजदूर हैं.

दूसरी तरफ प्रदेश के जौनपुर जिला जेल में कैदी की हत्या पर भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी की है. जौनपुर जिला कारागार में पिछले दिनों बंदी रक्षकों की पिटाई से श्याम कुमार यादव नामक कैदी की मौत हो गई थी. जेल प्रशासन का कहना है कि महिला कैदी से छेड़खानी करने के कारण आपस में ही मार पीट हुई थी, जिसमें श्याम कुमार की मौत हो गई थी. लेकिन कैदी की मौत से नाराज कैदियों और बंदी रक्षकों के बीच जबर्दस्त संघर्ष हुआ था जिसमें कुछ जेलकर्मियों समेत कई लोग जख्मी हो गए थे. इस मामले में लाइन बाजार थाने में दो मुकदमे भी दर्ज कराए गए और मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले की अपने स्तर से भी जांच शुरू कर दी है. आयोग ने इस घटना को मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बताया है.

मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बाराबंकी के कोठी थाने में थाना प्रभारी और एक दारोगा द्वारा महिला से बलात्कार की कोशिश में विफल होने पर उसे जिंदा जला कर मार डालने की घटना को संज्ञान में लेते हुए यूपी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी कर रखी है. इसके पहले शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को पुलिस और राज्यमंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के गुंडों द्वारा जला कर मारे जाने के मामले में आयोग ने सरकार को आड़े हाथों लिया था. बाराबंकी के कोठी थाने में महिला को जलाकर मारने की घटना में आयोग राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. बाराबंकी के कोठी पुलिस थाने में 6 जुलाई को महिला की तब जलाकर हत्या कर दी गई थी, जब उसने पुलिसकर्मियों के बलात्कार के प्रयास का विरोध किया था.

लचर कानून व्यवस्था जिम्मेदार

मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में सबसे ज्यादा 20 हजार शिकायतें दर्ज की गईं. उत्तर प्रदेश के बाद इस सूची में दिल्ली और हरियाणा का नंबर आता है, जिसके खिलाफ आयोग में क्रमशः 2,800 और 2,000 शिकायतें दर्ज की गईं. लेकिन कहां 20 हजार और कहां दो हजार. दिलचस्प तथ्य यह है कि जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर की पुलिस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें काफी कम हैं. पिछले तीन साल में जम्मू-कश्मीर की पुलिस के खिलाफ आयोग में सौ के लगभग शिकायतें ही दर्ज कराई गईं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने पिछले दिनों बरेली में एक दीक्षांत समारोह में कहा था कि पूरे देश में मानवाधिकार उल्लघंन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में मानवाधिकार उल्लंघन के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश से ही दर्ज होते हैं और जांच में वे अधिकांशतः सही भी पाए जाते हैं. बालाकृष्णन ने कहा कि प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था सही हो तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को काफी हद तक रोका जा सकता है. लचर कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामले काफी बढ़ने लगे हैं. जांच के बाद मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े मामले पुलिस थानों में ही सबसे अधिक सामने आते हैं ■

feedback@chauthiduniya.com

हरीश-बहुगुणा की लड़ाई में आर्या का पलड़ा भारी

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिस तरह अपनी राजनीतिक कार्यप्रणाली से मिशन 2017 को सफल बनाने के लिए लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां अपने खाते में डाल रहे हैं. उनके धूर विरोधी रहे कांग्रेस के ही दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को रावत की कार्यप्रणाली में ही लगातार खोट नज़र आ रही है. बहुगुणा ने रावत के सभी अच्छे कामों पर यह कह कर पानी फेर दिया कि विकास की गाड़ी हरीश को तेज रफ्तार में चलाना चाहिए, जनता को बेहतर सेवा की अपेक्षा है जिसके लिए मैं सदैव उन्हें याद दिलाता रहूंगा. राजनीति में खानदानी विरासत से पधारे बहुगुणा में हरीश सरकार की जनसेवा में खोंट ही खोंट नजर आ रहा है. बहुगुणा के इस न्याय को राजनीति के मर्मज्ञ जिस चश्मे से देख रहे हैं. इसमें उन्हें दस जनपथ की संलिप्तता नज़र आ रही है. देवभूमि की राजनीति में पिता हेमवती नन्दन बहुगुणा की विरासत के सहारे राजनीति के फर्स से अर्स पर पहुंचे विजय बहुगुणा की बेचैनी के एक-एक शब्द के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं. राजनीति के जानकर मानते हैं कि उत्तराखंड में बेहतर जन सेवा का इतिहास रच कर हरीश ने जिस तरह अपनी राजनीतिक जड़ जमा ली है. वह दिल्ली दरबार के हाईकमान को भी अब डराने लगा है. राजनीति के इस हलचल में एक बात साफ कर दी है कि वर्ष 2017 में सूबे में कांग्रेस की शानदार वापसी भी होती है, तो सूबे की सत्ता का ताज हरीश के सर पर नहीं होगा. हरीश रावत को अपनी पहली पसंद बनाने का दिखावा करके हाई कमान उन्हें दिल्ली दरबार की शोभा के रूप में रखेगी. इस संभावना ने एक ऐसा यक्ष प्रश्न हरीश का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा खड़ा कर दिया है कि बड़े बड़े देवभूमि के राजनीतिक समीक्षक भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे है और यह अनुत्तरित सवाल आने वाले वक्त की बाट जोह रहा है.

उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पंद्रह वर्ष के इतिहास का अवलोकन करने पर यह मिलता है कि इस नवोदित हिमालयी राज्य पर बारी-बारी से देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने शासन किया. कभी कांग्रेस ने तो कभी भारतीय जनता पार्टी ने. इन दोनों दलों के दिग्गजों ने जब भी नेता के चुनाव पर मंथन किया तो उन्हें ऊंची जाति के ब्राह्मण-क्षत्रिय दो जातियों में ही सूबे के मुखिया बनने की काबलियत दिखी. जिसका परिणाम रहा कि इस देवभूमि में दलित जाति के नेताओं के साथ लगातार सौतेला बरताव होता रहा. कांग्रेस ने तो हिम्मत करके अपने संगठन के मुखिया के पद पर श्रेष्ठ जनसेवा के लिए विख्यात यशपाल आर्या को संगठन के प्रदेश मुखिया की जिम्मेदारी सौपी भी, भाजपा इस मामले में अपने सामंती सोच के चलते फिसड्डी ही सिद्ध हुई. राज्य में नरेन्द्र मोदी की लहर में पांच की पाचों सीटे हिमालयी जनता ने भाजपा की झोली में डाल दिया फिर भी केंद्र में जब मोदी ने सरकार का गठन किया तो एक भी सांसद को सरकार का अंग नहीं बनाया. बाद में एक बार यह चर्चा उड़ी की मोदी जी अपने मंत्रिमंडल में अपने एक मात्र दलित सांसद अजय टम्टा को शामिल कर सम्मानित करने जा रहे हैं. इस खबर के बाहर आते ही उत्तराखंड भाजपा में भूचाल आ गया. जिसका असर रहा कि मोदी को कदम वापस लेना पड़ा. राज्य के ऊंची जाति के नेताओं ने इसे अपनी मूंछ से जोड़ लिया.

कांग्रेस 2017 में सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड में दलित नेता की ताजपोशी कर उत्तरप्रदेश सहित पूरे देश में मायावती के दलित राजनीति का जवाब देने की मंसा पाल रखी है. जिसमें यशपाल आर्या एक ऐसे नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जिनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है. आर्या को गांधी परिवार का पसंदीदा नेता होने के कारण ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था. आर्या का संगठनात्मक कार्यकाल भी गांधी परिवार को संतोष देने वाला रहा. हरीश-बहुगुणा के आपसी कलह में मध्य का रास्ता एक ऐसा रास्ता होगा जो आर्या के भाग्योदय का संकेत दे रहा है. कांग्रेस हरीश की बढ़ती उम्र और राजनीतिक कौशल का लाभ लेने के लिए राहुल दरबार के रत्नों में सुमार करना चाहती है. इस प्रदेश की राजनीति में अपनी दबंग राजनीति के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत भी एक चर्चित चेहरा हैं जिन्होंने आर्या के प्रदेश अध्यक्ष रहते नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के लिए सड़क से सदन तक लंबी लड़ाई का इतिहास रचा था.

कांग्रेस 2017 में सूबे के मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड में दलित नेता की ताजपोशी कर उत्तरप्रदेश सहित पूरे देश में मायावती के दलित राजनीति का जवाब देने की मंसा पाल रखी है. जिसमें यशपाल आर्या एक ऐसे नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं, जिनमें सबको साथ लेकर चलने की क्षमता है. आर्या को गांधी परिवार का पसंदीदा नेता होने के कारण ही प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था. आर्या का संगठनात्मक कार्यकाल भी गांधी परिवार को संतोष देने वाला रहा. हरीश-बहुगुणा के आपसी कलह में मध्य का रास्ता एक ऐसा रास्ता होगा जो आर्या के भाग्योदय का संकेत दे रहा है. कांग्रेस हरीश की बढ़ती उम्र और राजनीतिक कौशल का लाभ लेने के लिए राहुल दरबार के रत्नों में सुमार करना चाहती है. इस प्रदेश की राजनीति में अपनी दबंग राजनीति के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत भी एक चर्चित चेहरा हैं जिन्होंने आर्या के प्रदेश अध्यक्ष रहते नेता प्रतिपक्ष के रूप में कांग्रेस के लिए सड़क से सदन तक लंबी लड़ाई का इतिहास रचा था. कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी के बाद जिस तरह वेटिंग में रख कर विजय बहुगुणा की ताजपोशी की गई इससे पहले ही हाईकमान का नज़रिया साफ हो चुका है कि डॉ. हरक इस दौर से बाहर कर दिए गए हैं. जबकी पिछली बार ही सबसे तगड़ा दावा इन्हीं का था. राहुल का दलित के घर खाना खाना, दलितों को गले लगाना उत्तराखंड में जाति-पात के ऊपर की राजनीति का सूत्रपात करने जा रही है. जिसमें राजनीति के जानकर हर स्तर से आर्या की साफ सुथरी राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए राजनीति में नया अध्याय जुड़ने की बात स्वीकारने लगे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com